राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 66

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 15 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

शुभकामनाएं

आजादी का यह उत्सव हम सब को राष्ट्र के समग्र उत्थान के प्रति सजग-सक्रिय-सचेत करे और सर्वत्र सद्भाव एवं राष्ट्र गौरव की भावना का संचार हो, इस आकांक्षा के साथ 73वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

-प्रधान संपादक

एक नई आजादी...

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम के तहत शीर्ष कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 किया गया। पेज 3

जांबाज का वीर चक्र से 'अभिनंदन'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वीरता पुरस्कारों की घोषणा, बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल पांच पायलटों को वायु सेना मेडल

तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से बुधवार को हर साल की तरह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कारों का एलान किया गया। पाक के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद गुलाम कश्मीर में पाक के एफ-16 विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से नवाजा जाएगा।

अभिनंदन ने पाक के साथ हुए हवाई संघर्ष में अत्याधुनिक एफ-16 विमान को मिग-21 बाइसन के जरिये मार गिराया था। हवाई संघर्ष में अभिनंदन का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके बाद वह पाक सीमा में चले गए थे और तीन दिन बंदी रहे थे। बता दें कि वीर चक्र युद्धकाल में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है।

अभिनंदन वर्धमान की फाइल फोटो। एएनआइ

बालाकोट ये पांच जांबाज होंगे सम्मानित : विंग कमांडर अभिनंदन के अलावा बालाकोट में जैश-ए-मुहम्मद के ठिकानों पर हमला करने वाले वायुसेना के दूसरे पायलटों को भी सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन सभी पायलटों विंग कमांडर अमित रंजन, स्क्वाड्रन लीडर राहुल बोसाया, पंकज भुजडे, बीकेएन रेड्डी और शंशाक सिंह को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। ये सभी मिराज-2000 लड़ाकू विमान के पायलट हैं।

महिला अधिकारी मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल : इस मौके पर खासतौर पर महिला स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल प्रदान करने की घोषणा करके सराहा गया। मिंटी को यह पुरस्कार बालाकोट हवाई हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष के दौरान दिए गए उनके योगदान के लिए दिया जाएगा।

शहीद प्रकाश जाधव को कीर्ति चक्र, सात सैनिकों को शौर्य चक्र पेज>>3

जश्न की तैयारी

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले का विहंगम नजारा। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किले की प्राचीर से लगातार छठी बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन का देश-दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। ध्रुव कुमार

अलवर कोर्ट ने पहलू खान की हत्या में बरी किए छह आरोपित

फैसला ▶ आरोपितों को अदालत में मिला संदेह का लाभ

राजस्थान सरकार फैसले को देगी चुनौती, कोर्ट के बाहर भारत माता की जय के नारे

जागरण संवाददाता,जयपुर

बहुचर्चित अलवर मॉब लिंचिंग (उन्मादी हिंसा) मामले में आखिरकार सत्र न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुना दिया। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट-1 (एडीजे) की जज डॉ. सरीता स्वामी ने कथित गो तस्कर पहलू खान की हत्या के करीब 28 माह पुराने मामले के सभी छह आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। पुलिस ने इस मामले में नौ लोगों (छह बालिग और तीन नाबालिग) को आरोपित मानते हुए चार्जशीट पेश की थी। सभी छह बालिग आरोपित जमानत पर थे। नाबालिगों का केस किशोर न्यायालय में अलग चल रहा है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बुधवार रात बताया कि फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार ऊपरी अदालत में अपील करेगी।

कोर्ट के फैसले के बाद पहलू खान और उसके दोनों बेटों के वकील कासिम खान ने कहा कि वह फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। वहीं बचाव पक्ष के वकील योगेंद्र खडाना ने कहा कि कोर्ट ने तथ्य जांचने के बाद ही सबको बरी किया है। कोर्ट का लिखित फैसला शुक्रवार को मिलने की उम्मीद है। बरी हुए सभी छह लोगों के कोर्ट से बाहर आने पर वहां जमा समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। पुलिस ने सभी को अपनी सुरक्षा में उनके घरों तक पहुंचाया।

इस आधार पर मिला संदेह का लाभ : कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मृतक पहलू खान के दोनों बेटे इरशाद और आरिफ आरोपितों विपिन यादव,रवींद्र कुमार,कालूराम,दयानंद,भीम राठी और योगेश कुमार की पहचान नहीं कर सके, जबकि वे घटना के समय मौजूद थे। साथ ही पुलिस ने जो वीडियो कोर्ट में पेश किया उसकी फॉरेंसिक लैब में जांच नहीं कराई गई। वीडियो की फुटेज साफ नजर नहीं आने की बात भी कोर्ट ने कही। वीडियो किसने बनाया यह भी नहीं बताया गया। पुलिस ने पहलू खान की मौत हार्टअटैक से बताई, वहीं मेडिकल बोर्ड ने मारपीट में गहरी चोट लगने से। पहलू खान पक्ष इस मसले पर सत्यापित दस्तावेज पेश नहीं कर सका। एफआईआर के मुताबिक घटना की जानकारी दो अप्रैल 2017 को सुबह 4.24 बजे हुई,जबकि पुलिस ने चार्जशीट में बताया था कि पहलू खान के बयान एक अप्रैल की रात 11:50 पर रिकॉर्ड कर लिए गए थे। इसी तरह, मौत से पहले पहलू खान द्वारा पुलिस को बताए गए नाम अलग थे और पुलिस ने रिपोर्ट में जो नाम लिखे वे अलग हैं। यह प्रकरण पूरे देश में गूंजने के बाद तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने सीआईडी,सीबी से मामले की जांच कराई थी।

यह है पूरा मामला : एक अप्रैल,2017 को हरियाणा के नूंह मेवात निवासी 55 वर्षीय पहलू खान अपने दोनों बेटों आरिफ और इरशाद के साथ पिकअप गाड़ी में जयपुर के हरमाड़ा से दो गाय खरीदकर अपने घर ले जा रहा था। शाम सात बजे बहरोड़ पुलिया पर भीड़ ने उन्हें रोक लिया और मारपीट की थी। सूचना पर पुलिस पहुंची और पहलू को बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया,जहां चार अप्रैल को उसकी मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को ट्रायल कोर्ट बहरोड़ से अलवर एडीजे कोर्ट स्थानांतरित किया गया था।

नए बदलावों से जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को होगा फायदा : राष्ट्रपति

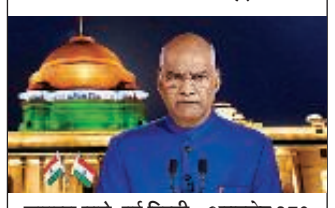

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के साथ लद्दाख के स्वरूप में आए बदलाव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां के लोगों के लिए लाभकारी करार दिया है। 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर किए गए बदलावों से समानता सुनिश्चित करने वाले प्रगतिशील कानून वहां लागू होंगे। इसमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार से लेकर तत्काल तीन तलाक जैसे अहम कानूनों का फायदा शामिल है।

कोविंद ने कहा, उन्हें भरोसा है कि जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के लिए हाल में किए गए बदलावों के बाद वहां के नागरिक अब उन सभी अधिकारों और सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे जो देश के अन्य नागरिकों को मिलते हैं। सभी बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित होगी। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। तत्काल तीन तलाक जैसे अभिशाप समाप्त होने से बेटियों को भी न्याय के साथ भयमुक्त जीवन का अवसर मिलेगा।

'जियो और जीने दो' के सिद्धांत पर चलता रहा है भारत का समाज पेज>>3

पाकिस्तान को डर बालाकोट से भी बड़ी कार्रवाई करेगा भारत

- इमरान खान ने कहा-गुलाम कश्मीर में हमला कर सकता है पड़ोसी मुल्क
- अनुच्छेद 370 हटाने पर भारत को बड़ी कीमत चुकाने की दी धमकी
- पाकिस्तानी पीएम बोले-भारत से छिड़ सकता है युद्ध

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान ने जाने-अनजाने पहली बार कुबूल किया है कि भारत ने बालाकोट में भीषण हवाई हमला किया था। बौखलाए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाक के पास ठोस जानकारी है कि भारत बालाकोट से भी बड़े हमले की योजना बना रहा है। कश्मीर के ताजा हालात से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए वह ऐसा करने वाला है। मेरा मोदी को यही संदेश है कि अगर वह कार्रवाई करेंगे तो हम भी मुनासिब जवाब देंगे।

गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में बुधवार को इमरान ने कथित विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत अब पुलवामा के बाद किए हवाई हमले से भी खतरनाक योजना बना रहा है। वह कश्मीर (गुलाम कश्मीर) में कुछ कार्रवाई कर सकता है। इस आधार पर हम राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की दो बैठकें कर चुके हैं।' इमरान ने धमकाते हुए कहा, 'हम हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आप जो भी करेंगे हम उसका जवाब देंगे। अगर आप हमको सबक सिखाने की सोच रहे हैं तो ध्यान से सुनें, अब हम आपको सबक सिखाएंगे।'

इमरान ने कहा, अगर अब पाक और भारत के बीच युद्ध छिड़ा तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार होगा। खान ने दावा किया कि विश्व की मुस्लिम आबादी समेत पूरी दुनिया इस समय संयुक्त राष्ट्र की ओर देख रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सितंबर में होने वाले वार्षिक सत्र का हवाला देते हुए पाक प्रधानमंत्री ने यह प्रपंच रचा है। भारत के आंतरिक मामले को लेकर पाक ने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक भी बुलाने की मांग की है। ज्ञात हो, इमरान ने पहली बार भारत से युद्ध छिड़ने की बात की है। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इमरान ने धमकी दी थी कि जम्मू और कश्मीर में पुलवामा जैसे और हमले हो सकते हैं। तब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि पाक बिना बात के अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने बिगड़े हुए हालात दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसा नहीं सोचता।

अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी ने की गलती : उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ की नफरत भरी विचारधारा से सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार ने राजनीतिक गलती की है। इसके लिए भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने अपना आजादी दिवस मनाते हुए 'कश्मीरियों से एकजुटता दिवस' मनाया। इस मौके पर इमरान ने कहा, 'मैं मानता हूं मोदी ने सामरिक गलती कर दी है। यह मोदी और उनकी भाजपा सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा।'

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान ने कहा, 'मैं कश्मीर के मुद्दे को आगे तक लेकर जाऊंगा। मैं कश्मीर की आवाज बनूंगा, कश्मीर का दूत बनूंगा।' उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की ओर ध्यान खींचना मुश्किल था। लेकिन अब मोदी की एक गलती से कश्मीर का मुद्दा स्पॉटलाइट यानी वैश्विक मीडिया की नजरों में आ गया है। मोदी ने असल में इस विवाद का अंतरराष्ट्रीयकरण करने में मदद की है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस को बतौर काला दिवस मनाने की तैयारी की है।

पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुधवार को पाक के पीएम इमरान खान ने गुलाम कश्मीर में विधानसभा को संबोधित किया। एएफपी

कश्मीर की हकीकत बदली नहीं जा सकती : बाजवा

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के आजादी दिवस पर ट्विटर पर संदेश जारी कर सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीर पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। कश्मीर की हकीकत को ना तो 1947 के अवैध दस्तावेज से बदला जा सकता था और ना ही अभी या भविष्य में कोई कार्रवाई करके ही बदला जा सकता है। जनरल बाजवा ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तानी सेना जम्मू और कश्मीर के लिए जान लगा देगी। सेना कश्मीर के लिए अपने राष्ट्रीय दायित्व को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

स्वतंत्रता के सारथी

नीलामी दे रही 'आयरन लेडी' को सलामी

कोलकाता : एक लाख एक...एक लाख दो...एक लाख तीन...! यह सामान अब आपका हुआ। हमने नीलामकर्ता को इसी तरह विभिन्न चीजों की नीलामी करते देखा है। गौर करने वाली बात यह है कि नीलामकर्ता की भूमिका में हैं 83 वर्षीय भानुमती पारेख, जिन्हें 'आयरन लेडी' के खिताब से नवाजा जा चुका है। (पेज-13)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

जन्मभूमि पर दावा साबित करने को रामलला ने रखे सुबूत

नई दिल्ली : अयोध्या में ही भगवान राम ने जन्म लिया था और विवादित जगह ही उनका जन्मस्थान है यह साबित करने के लिए बुधवार को रामलला विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक, दस्तावेजी और पुरातात्विक सुबूत पेश किए। मामले में शुक्रवार को भी बहस जारी रहेगी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

लगातार तीसरे हफ्ते औसत से ज्यादा बारिश

मुंबई : देश में लगातार तीसरे हफ्ते औसत से ज्यादा बारिश हुई है। इससे कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने की आशंका तो कम हुई है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल में बारिश व बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 270 से ज्यादा की मौत हुई है।

मीका पर इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने लगाया प्रतिबंध

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

मीका सिंह फाइल फोटो

पाकिस्तान में परफॉर्म करके मीका ने देश का नाम खराब किया : गुप्ता

पाकिस्तान में परफॉर्म करने वाले गायक मीका सिंह पर ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर मीका प्रतिबंध हटाने का निवेदन करेंगे तो भी प्रतिबंध नहीं हटेगा। फिलहाल मीका की तरफ से पाबंदी को लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा, 'मीका ने देश के साथ गद्दारी की है। पुलवामा हमले में कई जवान शहीद हुए थे। अनुच्छेद 370 खत्म होने पर पाक का भारत के प्रति रवैया भी उन्होंने देखा था, इसके बावजूद वहां जाकर परफॉर्म करके उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ देश का नाम भी खराब किया है। देश के गौरव से ज्यादा उन्होंने पैसों को अहमियत दी है। आजीवन प्रतिबंध के तहत फिल्म प्रोडक्शन हाउस, म्यूजिक कंपनी और ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ उनके कांट्रैक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है। बॉलीवुड का कोई भी निर्माता, म्यूजिक कंपनी उनके साथ काम नहीं करेंगे।' गुप्ता ने कहा कि अगर इंडस्ट्री से कोई भी मीका को काम देगा तो एसोसिएशन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। ज्ञात हो, आठ अगस्त को मीका ने कराची में परवेज मुशर्रफ के करीबी रिश्तेदार के समारोह में परफॉर्म किया था।

हरियाणा में आइपीएस अधिकारी विक्रम कपूर ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

विक्रम कपूर फाइल

डीसीपी (एनआइटी) ने पिस्टल से मार ली गोली, इंस्पेक्टर कर रहा था ब्लैकमेल

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आइपीएस अधिकारी विक्रम कपूर ने बुधवार सुबह सेक्टर-30 पुलिस लाइन स्थित अपने आवास पर गनमैन की सर्विस पिस्तौल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में कपूर ने भूपानी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल सईद और सतीश मलिक नाम के शख्स द्वारा ब्लैकमेल किए जाने की बात लिखी है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इंस्पेक्टर अब्दुल सईद को हिरासत में लिया गया है।

मूलरूप से करनाल के सेक्टर-6 निवासी विक्रम कपूर साल 1982 में बतौर एएसआइ हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। पदोन्नत होते हुए 2017 में आइपीएस बने। मौजूदा समय में डीसीपी (एनआइटी) के पद पर तैनात थे।

पत्नी नीलम के मुताबिक, सुबह वे बाथरूम में थीं, तभी गोली की आवाज सुनी। बाहर आईं तो देखा पति ड्राइंग रूम के सोफे पर लहूलुहान पड़े थे। पिस्तौल उनके पास पड़ी थी। अस्पताल ले जाने से पहले ही कपूर ने दम तोड़ दिया। पोस्टमॉर्टम में डॉक्टरों को पिस्टल की गोली रीढ़ की हड्डी के पास मिली है। इससे अनुमान है कि डीसीपी ने सिर पर पिस्टल रखकर गोली चलाई। सूत्रों ने बताया कि अब्दुल सईद ने पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल करने की बात बताई है। बदनामी के डर से डीसीपी ने खुदकशी कर ली। (पेज-2 देखें)

सर्वे शुरू

सरकार ने लांच किया ग्रामीण स्वच्छता सर्वे-2019, पिछली बार की तुलना में इस साल करीब तीन गुना गांवों में होगा सर्वेक्षण, शीर्ष स्थान हासिल करने वाले राज्यों को दो अक्टूबर को सम्मानित करेंगे पीएम

ग्रामीण स्वच्छता से तय होगी जिलों-राज्यों की रैंकिंग

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 सर्वे जारी किया। प्रेट्र

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जमीनी स्तर पर असर को मापने और गांवों में सफाई का हाल जानने को सरकार व्यापक स्तर पर 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019' कराने जा रही है। इसके तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के 698 जिलों के 17,475 गांवों में सर्वे के बाद स्वच्छता के आधार पर जिलों और राज्यों की रैंकिंग की जाएगी। जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा, उन्हें पीएम दो अक्टूबर को सम्मानित करेंगे।

यह दूसरा मौका है जब सरकार गांवों में स्वच्छता सर्वेक्षण कर रही है। इससे पूर्व 2018 में भी सरकार ने ऐसा सर्वेक्षण किया था। हालांकि उस समय सिर्फ छह हजार गांवों को ही इसमें शामिल किया गया था। इस बार गांवों की संख्या में करीब तीन गुना वृद्धि की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारी अरुण बरोका ने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। यह सर्वेक्षण 45 दिन में किया जाएगा। यह काम 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इस दौरान देशभर में 87,000 सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत, आंगनवाड़ी, बाजार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर स्वच्छता का हाल देखा जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान लोग मोबाइल एप के माध्यम से भी अपना फीडबैक दे सकेंगे।

बरोका ने कहा कि जिलों और राज्यों की रैंकिंग सेवास्तर की प्रगति, नागरिकों की प्रतिक्रिया और सर्वे दल की राय के आधार पर की जाएगी। सर्वेक्षण लांच करने के बाद जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सरकार यह सर्वेक्षण एक निजी एजेंसी से करा रही है। इस एजेंसी का चयन प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल के सर्वे का फोकस ठोस कचरे और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर होगा। यह गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने से आगे का कदम है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि ओडीएफ प्लस के तहत जैविक कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।

गार्डेनिया गेट-वे के खरीदारों को राहत, बैंक ने वापस लिया नोटिस

जागरण संवाददाता, नोएडा

जागरण प्रभाव

सेक्टर-75 स्थित गार्डेनिया गेट-वे के 200 अधिक खरीदारों को अब अपना घर खाली नहीं करना होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 78 करोड़ की ऋण अदायगी नहीं करने पर खरीदारों को 15 दिन में घर खाली करने का नोटिस थमाया था। खरीदारों के दबाव के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यह नोटिस वापस ले लिया है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड ने गार्डेनिया गेट-वे प्रोजेक्ट के लिए यूनियन बैंक से दिसंबर 2015 में 78 करोड़ 45 लाख का ऋण लिया था।'। खरीदारों ने बिल्डर को फ्लैट की पूरी कीमत दे दी है और फिलहाल सभी फ्लैट में परिवार रह रहे है। आरोप है कि बिल्डर ने बैंक से लिया गया ऋण अभी तक वापस नहीं किया है। बैंक ने वसूली के लिए बिल्डर को कई बार नोटिस भी भेजा लेकिन बकाया राशि नहीं मिली। इस पर यूनियन बैंक ने 5 अगस्त को फ्लैट खरीदारों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा था कि सभी फ्लैट खरीदारों को 20 अगस्त तक फ्लैट खाली करने होंगे। इससे खरीदारों में हड़कंप मच गया। उन्होंने प्रशासन व प्राधिकरण के अफसरों से शिकायत करने के साथ ही बैंक से भी संपर्क साधा। खरीदारों के दबाव में बैंक ने नोटिस को वापस ले लिया है।

अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन के अध्यक्ष बीएस लवानिया का कहना है कि बैंक द्वारा नोटिस वापस लेने से खरीदारों को राहत मिली है। मीडिया उनकी समस्या नहीं उठाता तो यह संभव नहीं हो पाता। उन्होंने कहा, अभी भी फ्लैट मालिकों की समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। बिल्डर पर नोएडा प्राधिकरण का भी 35 से 40 करोड़ रुपये बकाया है। इस वजह से प्राधिकरण ने अभी तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) नहीं दिया है। ओसी नहीं मिलने की वजह से उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है।

दूसरी शादी के आरोप में गुजरात का आइएएस अधिकारी निलंबित

अहमदाबाद, प्रेट्र : गुजरात सरकार ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी गौरव दाहिया को निलंबित कर दिया। दिल्ली की एक महिला ने अधिकारी पर दूसरी शादी करने और धोखा देने का आरोप लगाया है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि आइएएस अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना होगा।

मुख्य सचिव जेएन सिंह ने कहा, 'जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने बुधवार को गौरव दहिया को निलंबित किया है।' मुख्य सचिव ने जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। हाल ही में कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सरकार के बयान में कहा गया है, 'दहिया को उनके खिलाफ चल रही जांच के आलोक में निलंबित किया गया है। वह अनुशासनिक कार्रवाई का भी सामना करेंगे।' पिछले महीने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रमुख सचिव सुनैना तोमर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी।

3 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। उनको यह सम्मान उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए दिया जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 15 अगस्त 2019

न्यूज गैलरी

स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर लगाएं रोक : हाई कोर्ट

नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोक लगाई जाए। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में कोई तंबाकू या सिगरेट की दुकान न चलने दी जाए। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि तंबाकू पर रोकथाम के लिए बनाए गए कानून को पूरी तरह लागू कराना सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और संबंधित निकाय तय करें कि इस कानून का पूरी तरह पालन किया जाए। याचिका में कहा गया था कि राजधानी में कई शिक्षण संस्थानों के पास सिगरेट-तंबाकू उपलब्ध है, जो कि नियमों के खिलाफ है। (जासं)

ओला, उबर की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली : राजधानी में ओला और उबर कैब की कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और संबंधित कंपनी से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि सिटी टैक्सी योजना का पालन दोनों ही कंपनियां नहीं कर रही हैं। इस योजना के तहत सवारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैब संचालक की है। कैब के चालक की पुलिस जांच सहित कई विषय हैं, जिनका सिटी टैक्सी योजना में जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि हाल की खबरों में देखने में आया है कि कैब चालक सवारी पर अपराध में संलिप्त पाए गए हैं। याचिका में मांग की गई है कि ओला और उबर कैब में सुरक्षा और अन्य मानकों पर जवाबदेही तय की जाए। (जासं)

550वें प्रकाश पर्व को समर्पित विधानसभा सत्र बुलाने की मांग

नई दिल्ली : राजौरी गार्डन के विधायक और शिरोमणी अकाली दल बादल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष से गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। प्रकाश पर्व इस वर्ष पूरे भारत में श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार अन्य देशों में भी भारतीय दूतावास के माध्यम से यह प्रकाश पर्व मना रही है। इस मौके पर यादगारी सिक्का भी जारी किया गया है। शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जब सारे विश्व में गुरुपर्व मनाया जा रहा है तो दिल्ली विधानसभा का भी विशेष सत्र बुलाकर गुरु नानक देव जी की शिक्षा व वर्तमान समाज में उसके महत्व पर चर्चा की जानी चाहिए। गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के नहीं, बल्कि सभी के गुरु थे। (जासं)

जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा

चौकसी ▶ पांच दर्जन से अधिक इमारतों की छतों पर एंट्री एयरक्राफ्ट व एयर डिफेंस गन तैनात

आतंकी खतरे से निपटने के लिए पूरी तैयारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस पर हर संभावित आतंकी खतरे से निपटने के लिए देश की तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां समेत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आइटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, एसपीजी, एयरफोर्स व दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खलल भी डाल सकते हैं। राजधानी को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। दहशतगर्दों के मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए न केवल 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास से लेकर लालकिला तक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बल्कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा के इतने खास प्रबंध किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। चप्पे-चप्पे पर पुलिस व पैरा मिलिट्री की तैनाती की गई है।

दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता व डीसीपी मध्य जिला मंदीप सिंह रंधावा के मुताबिक जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा रहेगा। बुधवार आधी रात 12 बजे दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गईं। एक भी व्यावसायिक वाहन को दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। निजी वाहनों की भी सघन तलाशी के बाद ही दिल्ली में प्रवेश करने दिया जा रहा है।

आसमान से कोई लाल किला व उसके आसपास हमला न कर दे, इसके लिए लाल किला, आइएसबीटी, गीता कालोनी फ्लाईओवर, सिविक सेंटर (निगम मुख्यालय) आदि पांच दर्जन से अधिक ऊंची इमारतों की छतों पर एंट्री एयरक्राफ्ट व एयर डिफेंस गन लगाए गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर से दिनभर लाल किले के आसपास सुरक्षा का जायजा लिया गया।

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किला के आगे कड़ी निगरानी करते सुरक्षा कर्मी। ध्रुव कुमार

पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक पहले ही सभी 15 जिलों में जाकर पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को चौकस रहने के निर्देश दे चुके हैं। दिल्ली एक महीने से हाईअलर्ट पर है। प्रमुख आयोजन स्थल लाल किला सहित आसपास के इलाके मध्य दिल्ली व नई दिल्ली में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए हैं। बुधवार आधी रात को ही सुरक्षा एजेंसियां, पैरा मिलिट्री व दिल्ली पुलिस ने राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया।

सभी बाजारों व प्रमुख प्रतिष्ठानों सहित संवेदनशील स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर भी सुरक्षाकर्मियों की चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को जनरल इनपुट मिले हैं कि आतंकी कहीं भी अचानक भीड़ में घुसकर हमला कर सकते हैं।

लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। इससे राजघाट व गांधी मेमोरियल आदि जगहों पर भी वीवीआइपी मूवमेंट होगा। लिहाजा उन स्थानों पर भी पुलिस की अतिरिक्त चौकसी रहेगी। एनएसजी व एसपीजी ने भी सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। लाल किला के आसपास की सभी ऊंची बिल्डिंग पर सुरक्षाकर्मी बुधवार को ही तैनात कर दिए गए। वे तेज क्षमता वाली दूरबीन से ऊंचाइयों से हर शख्स पर नजर रख रहे हैं। स्पेशल सेल इंटरसेप्शन के जरिये देश से बाहर और खासतौर पर पाकिस्तान व अफगानिस्तान जाने व आने वाली हर कॉल को सुन रही है।

लाल किला के 10 किलोमीटर की परिधि में जगह-जगह मचान व मोर्चा बनाए गए हैं, जहां एलएमजी व एमपी 5 जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर पैरा मिलिट्री के जवान तैनात किए गए हैं। लाल किला के सामने स्थित सभी मकानों में रहने वाले लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने घरों के दरवाजे व खिड़कियां कार्यक्रम खत्म होने तक बंद रखें।

राजीव की जयंती के बहाने सोनिया फूंकेंगी चुनावी बिगुल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भले ही दिल्ली कांग्रेस इस समय नेतृत्व विहीन हो और हरियाणा में भी प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अशोक तंवर एवं भूपेंद्र सिंह हुड्डा में विवाद छिड़ा हो, लेकिन पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दोनों ही राज्यों के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की तैयारी कर ली है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के 75वें जन्मदिवस के बहाने वह न केवल दिल्ली में एक बड़े आयोजन को संबोधित करेंगी, बल्कि विधानसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल भी फूंकेंगी।

राजीव गांधी का जन्मदिन हालांकि 20 अगस्त को होता है, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) 22 अगस्त को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसी उपलक्ष्य में रैलीनुमा बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। सूत्रों की मानें तो इसका मकसद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित करना, प्रोत्साहित करना, जोश भरना और उन्हें नई रणनीति से अवगत कराना है।

इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंगलवार शाम 15, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की अगुवाई में एक बैठक भी हुई। इसमें दिल्ली कांग्रेस के तीनों कार्यकारी अध्यक्ष हारून युसूफ, राजेश लिलोठिया और देवेंद्र यादव के अलावा पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, डॉ. नरेंद्र नाथ, जितेंद्र कोचर इत्यादि मौजूद थे तो हरियाणा कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, किरण चौधरी और कैप्टन अजय सिंह यादव उपस्थित रहे।

सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने का काम दोनों राज्यों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपा गया है। एआइसीसी से मिले आदेश के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को सभी जिला अध्यक्षों की एक बैठक रखी गई। 17 अगस्त को जिला पर्यवेक्षकों की बैठक रखी गई है और इसके बाद ब्लॉक स्तर पर बैठक की जाएगी।

बताया जाता है कि इस कार्यक्रम में सोनिया के साथ राहुल गांधी, दिल्ली और हरियाणा के तमाम बड़े नेता और एआइसीसी के भी अनेक कद्दावर नेता शिरकत करेंगे।

चाको ने मांगा सोनिया से समय : एआइसीसी महासचिव और दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी रहे पीसी चाको ने सोनिया गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। हालांकि अभी उन्हें समय मिला नहीं है, लेकिन सूत्रों की मानें तो इस मुलाकात में वह दिल्ली की राजनीति और नए अध्यक्ष के चयन सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं।

सरकारी स्कूलों में लागू होगा देशभक्ति पाठ्यक्रम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे अगले साल से देशभक्ति का पाठ पढ़ेंगे। अगले साल से सभी सरकारी स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित 'संविधान के 70 साल' अभियान कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की।

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि शिक्षा पूरी करने के बाद हर बच्चा अच्छा इंसान बने। अपने परिवार का भरण पोषण करने के काबिल और सच्चा देशभक्त बने। इस पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को अपने देश पर गर्व करना, देश की समस्याओं के समाधान में जिम्मेदारी लेना और देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखना सिखाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पाठ्यक्रम में बच्चों को संविधान पढ़ाकर देशभक्त नागरिक बनाया जाएगा। उन्हें अपने अधिकारों के साथ यह भी बताया जाएगा कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से किस प्रकार करें। उन्होंने कहा कि आज लोगों को देशभक्ति तभी याद आती है जब भारत-पाकिस्तान का मैच होता है या बॉर्डर पर तनाव होता है। लोग रोजाना की कामों में देश को भूल जाते हैं। हमें बच्चों में देशभक्ति का ऐसा जज्बा पैदा करना है कि वे देश के लिए कुर्बानी देने से भी पीछे न हटें। वे कभी रिश्वत लें तो उन्हें ऐसा महसूस हो कि उन्होंने देश से गद्दारी की है। वे ट्रैफिक लाइट जंप करें तो उन्हें लगे कि देश के साथ धोखा किया है। बच्चों में ऐसी भावना होनी चाहिए कि विदेशी नागरिक अपने मेहमान लगें। हम उन्हें सम्मान दें। इस पाठ्यक्रम में बच्चों को कहानियों, इतिहास, संस्कृति के माध्यम से अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। बच्चों को देश के प्रति जिम्मेदारी का अहसास कराया जाएगा। उन्हें यह अहसास दिलाना है कि गरीबी, किसानों की आत्महत्या, भ्रष्टाचार आदि समस्याएं उन्हें खुद ही दूर करनी हैं।

उपमुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक और प्रिंसिपल देशभक्ति पाठ्यक्रम तैयार करने में सक्षम हैं। उन्होंने जिस तरह से हैप्पीनेस और उद्यमिता पाठ्यक्रम तैयार किया, उसी तरह देशभक्ति पाठ्यक्रम भी तैयार करेंगे। इसके लिए देश के प्रबुद्ध लोगों से इनपुट लिए जाएंगे।

नेपाल के राजदूत आचार्य ने केजरीवाल से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की।

आचार्य ने उन्हें नेपाल सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई दी। आचार्य ने कहा कि नेपाल के लोग दिल्ली में भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जो शारीरिक ही नहीं, भावनात्मक रूप से भी इस स्वतंत्रता से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम, जिसमें नेपाल के कई निजी स्कूलों ने भी दिलचस्पी दिखाई है, के अनुभवों को राजदूत के साथ साझा किया। दिल्ली सरकार के स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम को एक साल पूरा होने वाला है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को नेपाल के स्कूल के साथ अपने अनुभव साझा करने की खुशी होगी। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजदूत को दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक और स्कूल देखने का न्यौता दिया।

केजरीवाल ने 'संविधान के 70 साल' अभियान कार्यक्रम के दौरान घोषणा की

विधानसभा की मनोहर छटा

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अतिरिक्त 100 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान विधानसभा स्थित संगीतमय फव्वारे का भी उद्घाटन किया गया,जो कि रंगबिरंगी रोशनी से नहा उठा। इस अवसर पर विधानसभा व फव्वारे की छटा देखते ही बन रही थी। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल समेत अन्य लोग उपस्थित थे। संजय

तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

पूर्व मंत्री व राज्यसभा सदस्य विजय गोयल के नेतृत्व में अशोक रोड से अमर जवान ज्योति तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। साइकिल पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लिए युवा 'लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा ही तिरंगा' के नारे लगा रहे थे। इस यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान और बाबुल सुप्रियो भी शामिल थे। अमर जवान ज्योति पर सभी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

डॉ. बालियान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूत भारत के सपने को साकार कर दिया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू-कश्मीर के लिए 'इंसानियत कश्मीरियत और जम्हूरियत' का सूत्र दिया था। वोट बैंक की राजनीति की वजह से अनुच्छेद 370 के हटने में विलंब हुआ। अब हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम गुलाम कश्मीर को भी स्वतंत्र कराएं।

गोयल ने कहा कि सरदार पटेल ने रियासतों को जोड़कर देश को मजबूत किया था। प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार को दूर कर देश को मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद व गंदगी से भारत को मुक्त कराने का संदेश दिया है। उनके इस संदेश को जनजन तक पहुंचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है।

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अशोक रोड से साइकिल पर तिरंगा यात्रा निकालते केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रीयो, संसद सदस्य विजय गोयल और अन्य लोग। ध्रुव कुमार

उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश पर अपना सबकुछ न्योछावर कर दिया। देश पर जब-जब विपत्ति आई है, हमारे वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है। उन्हें याद करने के लिए लोग हाथों में तिरंगा लेकर अशोक रोड चौक से अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पहुंचे हैं।

सामान्य रहेगा मेट्रो का संचालन, चार स्टेशनों पर खुलेंगे चुनिंदा गेट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो की सेवा सामान्य रूप से संचालित रहेगी। वायलेट लाइन पर लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और आइटीओ मेट्रो स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कुछ चुनिंदा गेट से प्रवेश और निकासी की व्यवस्था होगी। लोगों को कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ेगा। समारोह की समाप्ति के बाद सभी गेटों से प्रवेश और निकास की व्यवस्था होगी। मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग गुरुवार दोपहर दो बजे तक बंद रहेगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अधिकारियों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी रूट के सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वायलेट लाइन के चार स्टेशनों लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और आइटीओ पर चुनिंदा द्वार से प्रवेश और निकासी की अनुमति होगी। इस अवधि में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों पर कुछ द्वार बंद रहेंगे। लोगों की सुविधा के लिए लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। समारोह के बाद भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। सुरक्षा कारणों से लोगों को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा। इस दौरान यात्रियों की असुविधा ने हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा।

मुजेसर थाने का मुकदमा नंबर 753 बना हुआ था डीसीपी के जी का जंजाल

हरेंद्र नागर, फरीदाबाद

डीसीपी एनआइटी आइपीएस विक्रम कपूर के आत्महत्या करने के पीछे की वजह को लेकर भले ही पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन इतना तय है कि मुजेसर थाने का मुकदमा नंबर 753 उनके लिए जी का जंजाल बना हुआ था। सूत्रों के अनुसार यह मुकदमा ही डीसीपी के आत्महत्या की वजह बना। 6 नवंबर 2018 को संजय कॉलोनी चौकी में तैनात एचसी हेमंत कुमार की शिकायत पर मुजेसर थाने में 753 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था।

हेमंत कुमार के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एटीएम हैंग कर लोगों के रुपये निकालने वाले तीन बदमाश संजय कॉलोनी 33 फुट रोड पर घूम रहे हैं। वह साथी मनोज कुमार के साथ तुरंत वहां पहुंचे। वहां एटीएम के पास तीनों बदमाश कार में बैठे दिखाई दिए। एचसी हेमंत और मनोज ने कार के आगे मोटरसाइकिल रोक दी। तीनों बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल को कार से टक्कर मारकर गिरा दिया और उनके ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की और फरार हो गए। पुलिसकर्मी किसी तरह बचे। इस मुकदमे में पलवल के गांव घाघोट निवासी इरसाद सहित तीन को नामजद किया गया था। बाद में पता चला कि कार चला रहा युवक इंस्पेक्टर अब्दुल सईद का भांजा था। मुजेसर थाना डीसीपी एनआइटी अंतर्गत आता है।

डीसीपी विक्रम कपूर के भाई सुरेंद्र पाल सिंह खबर सुनकर बुरी तरह टूट गए। जागरण

सूत्रों के अनुसार मामले की जांच में अब्दुल सईद द्वारा मिन्नत करने पर डीसीपी ने अब्दुल सईद के भांजे का नाम निकाल दिया था। मगर शिकायतकर्ता पुलिसकर्मियों ने पुलिस आयुक्त को शिकायत दे दी। इसके बाद जांच के लिए एसआइटी का गठन किया गया, जिसमें आरोपित का नाम फिर से शामिल कर लिया गया। कथित तौर पर इस मामले में रुपयों का लेन-देन होने की भी बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार अब्दुल सईद ने इस मुकदमे के सिलसिले में डीसीपी विक्रम कपूर से फोन पर बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब इसी रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर वह उन पर दबाव बना रहा था कि एसआइटी की जांच में भी उसके भांजे का नाम न आए। यही दबाव उनकी आत्महत्या की वजह बना। इस मामले में एक महिला के शामिल होने की भी चर्चा चल रही है, मगर उसकी किसी भी स्तर पर पुष्टि नहीं हो सकी।

ऐसा बहुत कम होता है कि आइपीएस अधिकारी निचले स्तर के पुलिसकर्मी से ब्लैकमेल हो जाए। एक पूर्व आइपीएस अधिकारी ने बताया कि आइपीएस की एक लॉबी है। अगर किसी आइपीएस से कोई गलती हो गई है या उस पर कोई गलत दबाव बना रहा है तो यह लॉबी उसको बचाने का हर संभव प्रयास करती है। इस लॉबी में आइपीएस अपनी बड़ी से बड़ी गलती भी बताकर मदद ले लेते हैं। डीसीपी विक्रम कपूर के भी कई उच्च स्तर के अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं। डीसीपी के लिए इंस्पेक्टर अब्दुल सईद से निपटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस मामले में डीसीपी का आइपीएस लॉबी से साथ न लेना भी समझ से परे है। यह इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं थी, जिसे डीसीपी किसी भी स्तर पर बाहर न लाना चाहते हों। ये सभी बातें जांच में ही स्पष्ट हो पाएंगी।

छात्र राजनीति

चुनाव अधिकारी बनने के इच्छुक हर विभाग के चार से पांच छात्रों के नाम किए गए तय, चुनाव समिति का गठन 20 अगस्त को होने की संभावना

जेएनयू में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएनयू के छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि बुधवार को कंवीनर रिपोर्ट तैयार की गई। इसमें हर विभाग से ऐसे चार से पांच छात्रों के नाम तय किए हैं जो चुनाव अधिकारी बनना चाहते हैं। यह रिपोर्ट विभाग की गवर्निंग बॉडी को सौंप दी गई है।

छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि 16 और 19 अगस्त को भी ऐसी ही रिपोर्ट बनेगी। इसके बाद हर विभाग की गवर्निंग बॉडी मीटिंग (जीबीएम) में इस पर फैसला होगा। जीबीएम से नाम आगे बढ़ने के बाद इसे जेएनयू की शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। इसके बाद जेएनयू छात्र संघ के मौजूदा महासचिव चुनाव समिति के सदस्यों की सूची को अधिसूचित करेंगे और फिर चुनाव समिति का गठन हो जाएगा। 2019 के छात्र संघ चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति और चुनाव समिति का गठन 20 अगस्त को हो सकता है। वहीं, छात्र संघ चुनाव के चारों पदों- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पर जीत को लेकर छात्र संगठनों ने अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। जेएनयू में पानी की आपूर्ति, हॉस्टल की कमी, पुस्तकालय में छात्रों के लिए जगह में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर छात्र संघ चुनाव लड़ा जाएगा।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीबी), अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा), ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन (एआइएसएफ), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) छात्र संघ चुनाव में अपने-अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रेसिडेंशियल डिबेट और इसके बाद वोटिंग होगी। मतगणना में करीब चालीस घंटे लगते हैं, क्योंकि जेएनयू में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। सभी छात्र संगठन मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के नेताओं को भी कैंपस में चुनाव प्रचार के लिए ला सकते हैं। पिछले वर्ष भी कई संगठनों ने ऐसा किया था।

जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए चुनाव समिति का गठन छात्रों द्वारा किया जाता है। इसमें प्रशासन की तरफ से कुछ भी तय नहीं किया जाता है। यह जेएनयू की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। छात्र संघ चुनाव की समिति में छात्र ही शामिल होते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी भी छात्र ही होता है।

विवि प्रशासन तैनात करेगा अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी

छात्र संघ चुनाव में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। पिछले वर्ष 12 सितंबर की रात को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी। वहीं, 16 सितंबर के दिन छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए थे, जिसके बाद एबीवीपी और वामपंथ छात्र संगठनों के बीच हाथापाई भी हुई। इसमें कुछ छात्र घायल भी हो गए थे। इन सब को रोकने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कैंपस में की जाएगी।

शिक्षकों के खिलाफ जारी आरोप पत्र पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जेएनयू प्रशासन की ओर से जारी आरोप पत्र पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए जेएनयू प्रशासन से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने 45 शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएनयू प्रशासन को नोटिस जारी कर 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

48 शिक्षकों को जारी किए गए आरोप पत्र में आरोप है कि ये सभी शिक्षक पिछले वर्ष जुलाई में एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा था कि उन्होंने किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें झूठे मामले में फंसाने के लिए यह आरोप पत्र जारी किया गया है। इसमे कुल तीन आधार बताए गए हैं। इनमें से एक आधार यह है कि सीसीएस कंडक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रदर्शन करने से रोकता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट के अगस्त 2017 के आदेश का हवाला दिया कि इसमें कुछ जगहों पर प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ने कहा कि जेएनयू शिक्षक सामान्य तौर पर सीसीएस कंडक्ट के तहत नहीं आते।

दानिक्स अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर बुधवार देर शाम 18 दानिक्स अधिकारियों को अतिरिक्त कार्य भार और नई नियुक्ति का आदेश मिला है। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी बलवान सिंह जागलान को आइपीजीसीएल, पीपीसीएल और डीटीएल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम के महाप्रबंधक और विशेष ऊर्जा सचिव डी वर्मा को डीएसआइआइडीसीके मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार, विशेष वित्त सचिव नीरज भारती को डीएससीएससी के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन के विशेष सचिव और विशेष गृह सचिव मो. अली अशरफ को दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सेवाएं विभाग के उप सचिव अश्विनी कुमार मेहता द्वारा जारी आदेश के मुताबिक वरिष्ठ दानिक्स अधिकारी आनंद कुमार तिवारी को खाद्य आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त आयुक्त, विवेक कुमार को संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी, शिंगारे रामचंद्रा महादेव को उप शिक्षा निदेशक, नागेंद्र शेखर पति त्रिपाठी को एसडीएम अलीपुर, कृष्ण कुमार को एसडीएम रोहिणी, राकेश कुमार को एसडीएम साकेत, पदमाकर राम को सहकारी समितियों का उप रजिस्ट्रार, महेश कुमार गुप्ता को दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग का रजिस्ट्रार, कपिल चौधरी को उप शिक्षा निदेशक, गौरव यादव को एसडीएम कंझावला, राहुल सैनी को डीएसएसएसबी का उप सचिव, आतिश कुमार को एसडीएम पटेल नगर, बलराम मीणा को परिवहन विभाग का उपायुक्त और अजीत सिंह ठाकुर को एसडीएम द्वारका नियुक्त किया गया है।

2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने बनाई है योजना। योजना के मुताबिक 18.5 करोड़ ग्रामीण घरों में से 15 करोड़ से अधिक को नल का पानी मुहैया कराया जाएगा।

भ्रष्टाचार के प्रति हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की : मोदी

नई दिल्ली, आइएएनएस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी दूसरी पारी में 75 दिन पूरे कर लिए हैं। भ्रष्टाचार, शिक्षा समेत तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में विस्तार से अपनी राय रखी। वह कहते हैं कि आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था को दीमक की तरह चाट रहा था। सभी के दिमाग में यही बात थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कौन शुरू करेगा। सभी मानते हैं कि भारत के विकास की दौड़ में भ्रष्टाचार बड़ी बाधा है। यह सिर्फ धन का मामला नहीं है बल्कि, भ्रष्टाचार से समाज में भरोसा खत्म हो रहा है। इसलिए हमने सत्ता में आने के साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की बिना उसके राजनीतिक नफा-नुकसान पर विचार किए। इसका नतीजा भी दिखने लगा है। न सिर्फ भ्रष्टाचार कम हुआ है, बल्कि समाज में भरोसा बढ़ा है। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, लेकिन बेवजह हम किसी को परेशान भी नहीं करेंगे। यही कारण है कि आयकर विभाग के कई अधिकारियों को समय से पहले ही सेवा से हटा दिया गया।

साक्षात्कार

- **प्रधानमंत्री ने कहा, हम चुनाव नहीं लोगों का भरोसा जीतने के लिए करते हैं काम**
- **लोगों को अब भाई-भतीजावाद और वंशवाद की राजनीति स्वीकार्य नहीं**

एक सवाल पर पीएम ने कहा, लोगों ने अब मन बना लिया है। 21वीं सदी में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, वंशवाद की राजनीति उन्हें स्वीकार्य नहीं होगी। मोदी का स्पष्ट मानना है कि भारत जैसे देश को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत अहम है। तकनीकी क्षेत्र से लेकर देश के समेकित विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। शिक्षा से न सिर्फ लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आयेगा बल्कि देश की सूरत भी बदलेगी। इसके महत्व को समझते हुए उनकी सरकार शिक्षा के हर पहलू को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में शोध व अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया है, उस पर सभी से सुझाव मांगे गए हैं। स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस,मशीन के उपयोग पर बल दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी का गठन किया है। 2022 तक इसको एक लाख करोड़ रुपये का फंड देने का लक्ष्य है। अब तक 21 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराए गए हैं। अब तक 60 उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता दी गई है, जिसमें 52 विश्वविद्यालय हैं। पीएम ने कहा, भारत में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत में नैसर्गिक सौंदर्य वाले कई स्थान हैं। गत पांच वर्षों में विदेशी सैलानियों की संख्या में 50 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

खाड़ी देशों से संबंधों में सुधार : खाड़ी देश से संबंधों और विदेश नीति के सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके दो पहलू हैं। एक वर्ग यह मानता था कि मेरी सरकार विदेश नीति के मामले में असफल रहेगी। सिर्फ खाड़ी के देशों के साथ संबंधों को लेकर ही नहीं बल्कि व्यापक परिपेक्ष्य में। लेकिन हमारी सरकार ने खाड़ी समेत दुनिया के तमाम देशों के साथ मजबूत रिश्ते काम किए हैं। 2014 में मेरी उनकी पहली सरकार बनने के बाद सबसे पहले ओमान के सुल्तान सरकारी यात्रा पर भारत आए थे। दूसरा पहलू यह है कि भारत के लिए खाड़ी के देशों का विशेष महत्व है। खाड़ी के देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय रहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत अहम योगदान है। खाड़ी के देशों के साथ हमारे गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं।

2019 में बहुमत को लेकर आश्वस्त थे : 2019 के चुनाव से पहले बहुत लोगों ने कहा था कि आपकी सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, पीएम ने कहा, कुछ खास किस्म के लोग हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते उसके प्रति बातें गढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें हकीकत पता थी। पिछली सरकार में हमने जो काम किया था, उस पर जीत का भरोसा था। हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लोगों का भरोसा जीतने के लिए काम करते हैं। सरकार लोगों के कल्याण के काम करती है, नतीजे तो अपने आप पक्ष में चले आते हैं।

लंबित मामलों की होगी जल्दी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक पांच अगस्त को लोकसभा से और सात अगस्त को राज्यसभा से पारित हो गया है। इस नये कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 करने का प्रावधान किया गया है। शीर्ष न्यायालय में मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर न्यायाधीश के पदों की संख्या में इजाफे के लिए यह कानून बनाया गया है।

लंबित मामले

सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1 जून 2019 तक कोर्ट में 58,669 मामले लंबित थे। भारत के प्रधान न्यायाधीश ने सूचित किया है कि न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या शीर्ष अदालत में मामलों के लंबित होने के मुख्य कारणों में से एक कारण है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा न्यायाधीशों की संख्या 906 से बढ़कर 1079 हो गई है। इसके कारण हाईकोर्ट स्तर पर मामलों के निस्तारण में वृद्धि हुई है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में की जाने वाली अपीलों में वृद्धि हुई है।

ऐसे बढ़ी संख्या

शुरुआत के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में केवल आठ न्यायाधीश थे और सभी प्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए एक साथ बैठते थे। 1956 में सरकार सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम लेकर आई। इसके बाद कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। जैसे- जैसे न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई वे दो व तीन सदस्यों वाली बेंच में बैठने लगे। केवल मतभेद या विवाद का निपटारा करने के लिए पांच या उससे अधिक की बड़ी बेंचें गठित की जाने लगीं।

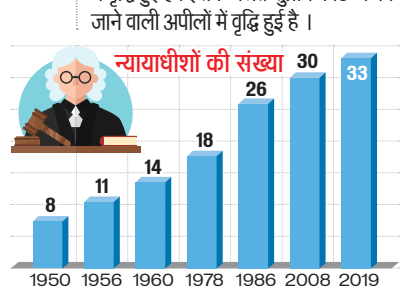

शहीद प्रकाश जाधव को कीर्ति चक्र, सात सैनिकों को शौर्य चक्र

प्रथम पृष्ठ से आगे

भारतीय सेना के एक-राष्ट्रीय राइफल्स (महार) के सैपर (तकनीकी) प्रकाश जाधव को जम्मू-कश्मीर में एक ऑपरेशन में उनकी वीरतापूर्ण भूमिका के लिए कीर्ति चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सेना के सात जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा जो शहीद हो गए हैं।

132 सैन्यकर्मी होंगे सम्मानित : तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असाधारण वीरता के लिए बुधवार को 132 सैन्यकर्मियों को वीरता पुरस्कारों से अलंकृत करने का निर्णय लिया। इनमें दो कीर्ति चक्र, एक वीर चक्र, 14 शौर्य चक्र, आठ सेना पदक बार, 90 सेना पदक, पांच नौसेना वीरता पदक, सात वायुसेना वीरता पदक और पांच युद्ध सेवा पदक शामिल हैं। इस बार 96 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार देने का फैसला किया है। इनमें 15 सीबीआइ से हैं।

वीरता के लिए छह सर्वोच्च सम्मान : वीरता पुरस्कारों के तहत छह सम्मान दिए जाते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र युद्धकाल में सर्वोच्च त्याग और बलिदान के लिए दिया जाता है जबकि अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शांतिकाल में सर्वोच्च सेवा और बलिदान के लिए दिया जाता है।

जन्मभूमि के बारे में रामलला ने रखे सुबूत

सुप्रीम सुनवाई ▶ विदेशी यात्रियों के वृतांत, गैजेटियर और पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट किए पेश

स्कंद पुराण में अयोध्या में राम के जन्म के उल्लेख का दिया हवाला

माला दीक्षित, नई दिल्ली

अयोध्या में ही भगवान राम ने जन्म लिया था और विवादित जगह ही उनका जन्मस्थान है यह साबित करने के लिए बुधवार को रामलला विराजमान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक, दस्तावेजी और पुरातात्विक सुबूत पेश किए गए। रामलला की ओर से कहा गया कि इन सुबूतों से स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विवादित जगह ही राम जन्मस्थान है। वहां पहले मंदिर था जिसे तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। मामले में शुक्रवार को भी बहस जारी रहेगी।

भगवान रामलला विराजमान की ओर से वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने स्कंद पुराण में दिए तथ्यों को उद्धृत करते हुए बहस शुरू की। उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण में भी अयोध्या में भगवान राम के जन्म का वर्णन है। हिंदुओं का विश्वास और आस्था भी यही है कि भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया था। कोर्ट आस्था पर तर्क नहीं कर सकता।

वैद्यनाथन ने सोलहवीं शताब्दी में भारत आए विदेशी यात्री विलियम फिंच के अयोध्या भ्रमण के वर्णन का हवाला दिया जिसमें अयोध्या में रामायण के हीरो रामचंद्र का महल होने और उसके अवशेष वहां मौजूद होने की बात कही गई है। वैद्यनाथन ने कुल सात विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन का हवाला दिया। उन्होंने हंस बेकर की किताब का भी जिक्र किया, जिसमें विस्तृत रूप से अयोध्या के ऐतिहासिक महत्व को बताया गया है। उन्होंने सरकारी गैजेटियर्स का भी उल्लेख किया जिसमें अयोध्या में राम जन्मस्थान होने की बात कही गई है।

पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी मंदिर : वैद्यनाथन ने भारत पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) द्वारा कराई गई खुदाई में भी वहां 10वीं और 11वीं शताब्दी के मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। यह भी कहा कि ढांचे में लगे कसौटी के पत्थरों पर आम के पत्तों, कलश, भगवान शंकर व अन्य देवताओं के चित्र अंकित मिले हैं। वैद्यनाथन ने कहा कि ये सारी चीजें किसी मुस्लिम मस्जिद में कैसे हो सकती हैं।

बाबरी मस्जिद नाम कब आया : जस्टिस एसए बोबडे ने सवाल किया कि इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद नाम कब मिला। इस पर वैद्यनाथन ने कहा कि 19वीं शताब्दी में इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। इससे पहले इसे बाबरी मस्जिद कहे जाने के कोई दस्तावेजी सुबूत नहीं हैं।

बाबरनामा में भी जिक्र नहीं : वैद्यनाथन ने कहा कि बाबरनामा में भी बाबरी मस्जिद के बारे में कोई जिक्र नहीं है। हालांकि, बाबरनामा का कुछ हिस्सा गायब है। जस्टिस बोबडे ने पूछा कि क्या बाबरनामा इस बारे में मौन है। तभी मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि बाबर नामा में सिर्फ दो पेज गायब हैं लेकिन बाबर अयोध्या आया था।

जैन, बौद्ध, इस्लाम सभी आए, पर हिंदुओं की आस्था बनी रही : जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या में बहुत घालमेल दिखता है। वहां जैन, बौद्ध, इस्लाम, हिंदू सबका प्रभाव रहा। इस पर वैद्यनाथन ने कहा कि भारत में समय-समय पर परिस्थितियों के मुताबिक अलग-अलग प्रभाव रहे लेकिन हिंदू भगवान राम के जन्मस्थान को लेकर अयोध्या के प्रति हमेशा आस्थावान रहे।

मस्जिद को लेकर शिया-सुन्नी विवाद का उठा मसला : रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन ने 1945 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से निचली अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शिया बोर्ड ने कहा था कि अयोध्या में राम जन्मस्थान पर बाबर के कमांडर मीर बाकी ने खूबसूरत मस्जिद बनाई थी। इस पर शिया बोर्ड के वकील ने कहा कि मीर बाकी शिया था इसलिए मस्जिद शियाओं की थी। कोर्ट ने पूछा कि उस मुकदमें में सुन्नी बोर्ड का जवाब क्या था, क्या उसने यह तथ्य स्वीकार कर लिया था। किसी भी पक्ष इसका सीधा जवाब नहीं दे पाए।

शिया बोर्ड ने हिंदुओं को जगह सौंपने की कही थी बात : वैद्यनाथन ने बताया कि शिया बोर्ड ने कहा था कि अगर साबित हो जाता है कि मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी तो वे मस्जिद तोड़ कर स्थान हिंदुओं को सौंप देंगे। उसका तर्क था कि किसी दूसरे पूजास्थल की जगह बनी मस्जिद इस्लाम की निगाह में वैध नहीं होती। रामलला विराजमान की ओर से वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि हाईकोर्ट के दो जजों ने माना है कि मंदिर तोड़ कर वहां मस्जिद बनाई गई थी। और तीसरे जज एसयू खान ने कहा है कि मस्जिद मंदिर के खंडहर अवशेषों पर बनी थी, उसका भी मतलब यही निकलता है कि वहां पहले मंदिर था। वैद्यनाथन ने कहा कि ऐसे में जस्टिस एसयू खान का आगे कहना कि यह साबित नहीं होता कि बाबर ने मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई थी अपने आप में विरोधाभासी बात है जो कि स्वीकार करने लायक नहीं है।

'जियो और जीने दो' के सिद्धांत पर चलता है समाज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

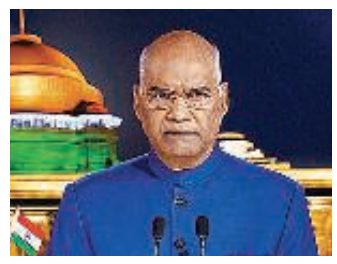

नई दिल्ली : देश की आजादी की 73वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेट्र

पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं और विवादित बयानों के बीच कोविंद ने देश की समावेशी संस्कृति की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि भारत का समाज तो हमेशा 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत पर चलता रहा है। समाज के लोग भाषा, पंथ और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं और यह हमारे इतिहास और विरासत का बुनियादी हिस्सा है।

राष्ट्रपति ने संसद के हाल में ही समाप्त हुए सत्र की कामयाबी पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि सियासी दलों के परस्पर सहयोग से कई अहम विधेयक पारित किए गए। संसद की इस सफलता के अगले पांच साल तक जारी रहने की उम्मीद के साथ कोविंद ने राज्यों की विधानसभाओं को भी संसद की इस प्रभावी कार्य संस्कृति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसद और विधानसभाओं में आदर्श, कार्य संस्कृति का उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह केवल इसीलिए जरूरी नहीं है कि निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाता के विश्वास पर खरा उतर सके बल्कि राष्ट्र निर्माण में हर संस्था और हितधारक एकजुट होकर काम कर सके।

लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी पर हर्ष जाहिर करते हुए राष्ट्रपति ने कहा,जनादेश में लोगों की आकांक्षाएं साफ दिखाई देती हैं। इन्हें पूरा करने में सरकार अपनी भूमिका निभाती है, मगर देश की 130 करोड़ की आबादी अपने कौशल, प्रतिभा, उद्यम और इनोवेशन के जरिये विकास के और अधिक अवसर पैदा कर सकते हैं। कोविंद ने इस क्रम में जनता की जिंदगी बेहतर करने की दिशा में सरकार की ओर से चलाई जा रहीं लोक कल्याण की योजनाओं और विकास के कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने गरीबों के घर बनाने, हर घर में बिजली पहुंचाने, शौचालय, सिंचाई सुविधा से लेकर ग्रामीण सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ने जैसे कामों का जिक्र किया।

राष्ट्रपति ने इस मौके पर लोगों से खास तौर पर राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के प्रति सजग होने का आग्रह किया। उनका कहना था कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा भी स्वाधीनता की रक्षा से जुड़ी हुई है और ऐसा करना देशप्रेम की भावना व संकल्प को दर्शाता है। उन्होंने जनता से राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयासों को अपनी सक्रियता के जरिये रोकने की अपील भी की।

सिक्किम में 13 विधायकों वाली पार्टी में अकेले बचे चामलिंग

- **एसडीएफ के दो विधायक सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में शामिल**
- **एक दिन पहले चामलिंग की पार्टी के 10 विधायक भाजपा में हो गए थे शामिल**

गंगटोक, प्रेट्र : सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) को बुधवार को लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका लगा। पार्टी के दो विधायक सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) में शामिल हो गए। इससे पहले मंगलवार को एसडीएफ के दस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। राज्य में 25 साल तक शासन करने वाली एसडीएफ के विधानसभा में मात्र एक विधायक पवन कुमार चामलिंग रह गए हैं। 1993 में उन्होंने ही पार्टी की स्थापना की थी। वह पिछले 26 सालों से पार्टी के अध्यक्ष हैं।

विधायक जीटी धुंगल और इम प्रसाद शर्मा ने बुधवार को पत्रकार सम्मेलन कर एसकेएम में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने कहा, 'हमने एसकेएम में शामिल होने का फैसला किया क्योंकि हम इसके नेतृत्व और नीति के साथ सहज महसूस करते हैं।' हमारा मानना है कि एसकेएम ही एकमात्र क्षेत्रीय दल है जो स्थानीय लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। खास बात यह है कि एसकेएम में शामिल होने वाले इन दोनों विधायकों ने कुछ दिनों पहले एसडीएफ नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करते हुए बजट सत्र में भाग लिया था। इन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष एलबी दास से एसडीएफ-2 के रूप अलग सीट दिए जाने की भी मांग की थी, जिसे बाद में मान लिया गया था।

पवन कुमार चामलिंग फाइल फोटो

32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा में 17 विधायक एसकेएम और 15 विधायक एसडीएफ के थे। हालांकि एसडीएफ के दो और एसकेएम का एक विधायक दो-दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए थे। इस तरह तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दो एसडीएफ विधायकों के शामिल होने के बाद सत्तारूढ़ एसकेएम के विधायकों की संख्या 18 हो गई है। वहीं अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाने वाली भाजपा एसडीएफ के 10 विधायकों के पाला बदलने के बाद विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बन गई है।

आरपीएफ के कमांडो सुनिश्चित करेंगे रेल मुसाफिरों की सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- **रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कमांडो यूनिट कोरस को देश को किया समर्पित**
- **हरियाणा के जगाधरी में कमांडो प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा**

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की कमांडो यूनिट कोरस (कमांडोज फॉर रेलवे सेफ्टी) के गठन की घोषणा की। इस यूनिट में 1200 जवान शामिल हैं जो नक्सलवाद और आतंकवाद प्रभावित इलाके में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रेल मंत्री ने कोरस के कमांडो को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिलाने और अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराने और हरियाणा के जगाधरी में आरपीएफ कमांडो प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए दलालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और आरपीएफ मैनुअल में बदलाव करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा, आरपीएफ के जवान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जान जोखिम में डालकर यात्रियों की सुरक्षा करते हैं। पिछले दिनों गुजरात में आरपीएफ जवान शिवपाल गुर्जर ने जान की परवाह किए बगैर बाढ़ में फंसे आठ लोगों की जान बचाई है। मुंबई में रेलवे स्टेशन पर हुए आतंकी हमले में भी आरपीएफ जवानों ने सामान्य राइफल से आतंकियों का मुकाबला किया था। अब कमांडो की तैनाती से यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर होगी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने कौशल का प्रदर्शन करते 'कोरस' (सीओआरएएस - कमांडोज फॉर रेलवे सेफ्टी) जवान। प्रेट्र

आरपीएफ मैनुअल में होगा बदलाव : उन्होंने आरपीएफ के महानिदेशक अरुण कुमार को तीन माह के अंदर आरपीएफ मैनुअल में बदलाव करने और इसमें तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने को कहा। इसी तरह से रेलवे मैनुअल और सर्कुलर की दस हजार किताबों को नए सिरे से संग्रहित करने का काम उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक टीपी सिंह को सौंपा गया है। पांच माह में यह काम पूरा किया जाएगा।

सभी रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे : रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिसका लिंक नजदीक के बड़े स्टेशन, आरपीएफ व जीआरपी कार्यालय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय और रेल मंत्री कार्यालय से होगा। दूसरे चरण में प्रत्येक ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। ढाई हजार से अधिक रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा है जिससे ट्रेनों में लगे सीसीटीवी कैमरे का लिंक उन स्टेशनों से किया जा सकता है।

टिकटों की कालाबाजारी को लेकर जताई नाराजगी : रेल मंत्री ने टिकटों की कालाबाजारी पर चिंता जताते हुए कहा कि जो काम ट्रैफिक विभाग को करना चाहिए वह काम आरपीएफ कर रहा है। आरपीएफ ने देशभर में अभियान चलाकर एक हजार से ज्यादा टिकट दलालों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रैफिक विभाग को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।

कमांडो दस्ते ने अपने कौशल का किया प्रदर्शन : कोरस के जवानों ने रेल मंत्री के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कोरस में पुरुष के साथ ही महिला कमांडो भी शामिल हैं। इन सभी की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है।

रतुल पुरी को 20 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **निचली अदालत में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट आया मामला**

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकाप्टर घोटाले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे 20 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत दी है। साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट में स्पष्ट होना चाहिए कि मनी लांड्रिंग की अब तक की जांच में रतुल पुरी की क्या भूमिका सामने आई है।

रतुल पुरी ने निचली अदालत द्वारा अग्रिम जमानत की मांग को ठुकराने के बाद मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। निचली अदालत ने पहले 7 अगस्त को रतुल पुरी की अग्रिम जमानत की मांग ठुकरा दी थी और फिर 9 अगस्त को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। रतुल पुरी ने इसी बीच अग्रिम जमानत पर फैसला लेने से पहले अन्य सभी आवेदनों पर सुनवाई करने के निचली अदालत को निर्देश की मांग हाई कोर्ट से की थी। इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलीकाप्टर डील मामले में पुरी की भूमिका की ईडी जांच कर रहा है। ईडी का आरोप है कि रतुल पुरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

रतुल पुरी फाइल फोटो

क्रिश्चियन मिशेल ने दायर की जमानत अर्जी

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित क्रिश्चियन मिशेल ने भी राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में जमानत अर्जी दायर की है। मिशेल ने ईडी और सीबीआइ द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांगी है। मिशेल की अर्जी पर अदालत ने दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी कर 19 अगस्त तक जवाब मांगा है।

बड़ा कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में शुरू हुई कवायद, दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की हुई समीक्षा

दिव्यांगजों के लिए जल्द बनेगा मोबाइल एप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिव्यांगजनों की मदद के लिए मोबाइल एप तैयार करने के प्रधानमंत्री के निर्देश पर काम शुरू हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुधवार को इसे लेकर एक लंबी बैठक भी की। इस बैठक में मोबाइल एप को जल्द ही तैयार करने का दावा किया है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा भी की गई।

हालांकि मंत्रालय का दावा है कि उसके पास दिव्यांग सारथी नाम का एक मोबाइल एप पहले से ही मौजूद है, लेकिन वह पीएम की सोच के मुताबिक नहीं है। पीएम ने दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसा मोबाइल एप बनाने का निर्देश दिया है, जिसके जरिये दिव्यांग अपनी समस्याओं को सीधे मंत्रालय तक पहुंचा सकें। जबकि मंत्रालय के पास मौजूदा एप में सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से जुड़ी जानकारी ही दी जाती है। इस मोबाइल एप को विभाग ने 2017 में लांच किया था। बुधवार की बैठक में दिव्यांगजन अधिकार कानून के अमल पर भी चर्चा हुई है। साथ ही उनके लिए तैयार किए जाने वाले विशेष आधार की प्रगति की भी जानकारी ली है। मंत्रालय में यह हलचल पीएम मोदी की दिव्यांगजन विभाग को लेकर किए गए जिक्र के बाद दिखी है। इसके साथ मंत्रालय ने अपने हर महीने अपने दूसरे विभागों की भी समीक्षा बैठक करने का फैसला लिया है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बैठक में नई सरकार में अगले पांच सालों की योजना पर भी चर्चा हुई है।

समर्थ में चार लाख लोगों का होगा कौशल विकास

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

टेक्सटाइल क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए चलाए जाने वाले समर्थ कार्यक्रम में चार लाख लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। इस आशय के एक करार पर केंद्र ने राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। कौशल विकास का काम 18 राज्यों में किया जाएगा।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में 16 राज्यों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए। हालांकि इसके लिए 18 राज्य सहमति दे चुके हैं। इस मौके पर कपड़ा मंत्री ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने यहां मिलकर तय कर दिया है कि चार लाख लोगों को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 'मुझे लगता है कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है।' जिन 18 राज्यों ने इस स्कीम में शामिल होने के लिए सहमति दी है उनमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, ओडिशा, मणिपुर, हरियाणा, मेघालय, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं। बुधवार को हस्ताक्षर कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

कपड़ा मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण पूरा होने पर सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यक्रम स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर टेक्सटाइल उद्योग की पूरी वैल्यू चेन में चलेगा। इनमें अपेरल, गारमेंटिंग, निटिंग, मेटल हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट व कारपेट आदि क्षेत्र शामिल हैं।

स्मृति ईरानी ने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग में करीब 75 फीसद महिलाएं हैं। इसी तरह मुद्रा स्कीम में भी 70 फीसद लाभार्थी महिलाएं ही हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को जिलावार टेलरिंग प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए।

शहीदों के बलिदान को नहीं भूलेगा देश : राजनाथ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। साथ ही पाकिस्तान की प्रवृत्ति पर भी सवाल खड़ा किया। राजनाथ ने इस मौके पर 14 फरवरी को पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में शहीद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 बहादुर जवानों को भी याद किया। उन्होंने कहा,हमारा पड़ोसी देश, जम्मू-कश्मीर पर बराबर बुरी निगाह रखता है और हमारे भूभाग में आतंकियों को भेजता रहता है ताकि कश्मीर घाटी में शांति को भंग किया जा सके, लेकिन हमारी सेनाओं ने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है।

राजनाथ ने कहा, वैश्विक परिदृश्य में रणक्षेत्र सिर्फ जल, थल और वायु तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में भी इनका विस्तार होगा। इसलिए भारत को किसी भी संभावित घटना के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, तिरंगे की आन बान और शान सदा कायम रहेगी। देश के लिए बलिदान करने वाले महान वीरों को याद करते हुए उन्होंने कहा, इस वर्ष सरकार ने लंबे अरसे से लंबित पड़े वॉर मेमोरियल का काम पूरा किया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

40 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में अब तक। यहां सात व आठ नवंबर को राइजिंग हिमाचल इनवेस्टर्स हैवन, समिट का आयोजन किया जाना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 15 अगस्त 2019

कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी भाजपा में शामिल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- तृणमूल विधायक की महिला मित्र बैशाखी ने भी थामा भगवा झंडा
- तृणमूल ने शोभन को किया पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित
- मुकुल राय और अरुण सिंह की मौजूदगी में शामिल हुए पार्टी में

कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर व तृणमूल कांग्रेस विधायक शोभन चटर्जी अपनी महिला मित्र बैशाखी बनर्जी के साथ बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली में भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के वरिष्ठ नेता मुकुल राय और महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में दोनों ने भाजपा का दामन थामा। दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद राय ने कहा कि वह उन नेताओं में से एक हैं, जिसने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है। शोभन कभी ममता के काफी करीबी नेताओं में माने जाते थे।

मुकुल ने दावा किया कि शोभन के आने के बाद से राज्य में भाजपा और मजबूत होगी और कोलकाता नगर निगम के लिए यदि चुनाव कराए जाते हैं तो निश्चित तौर पर जीत भाजपा की होगी। मुकुल ने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत मिलेगा और तृणमूल 30 सीटों पर सिमट जाएगी। बुधवार को तृणमूल की एक और विधायक देवश्री राय को भी दिल्ली भाजपा मुख्यालय में देखा गया। सूत्रों ने बताया कि शोभन की आपत्ति के कारण देवश्री को भाजपा में शामिल कराने को लेकर सहमति नहीं बनी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने भाजपा में शामिल होने के बाद शोभन चटर्जी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया।

> किसी भी पार्टी को चलाने के लिए एक स्वच्छ गणतांत्रिक प्रणाली की आवश्यकता होती है जो कि भाजपा में है, लेकिन जिस तृणमूल को हमने अथक प्रयास से सींचा था वहां अब प्रणाली नहीं रही है।
> -शोभन चटर्जी

तृणमूल विधायक और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी ने अपनी महिला मित्र बैशाखी बनर्जी के साथ बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रेट्र

पिछले वर्ष छिन गई थी कुर्सी : शोभन चटर्जी के निजी जीवन में परेशानियों के चलते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले साल नवंबर में उनसे पर्यावरण, अग्निशमन के मंत्री पद और कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। चटर्जी पिछले कुछ महीनों से भाजपा के संपर्क में थे। लोकसभा चुनाव में हैरानी भरे नतीजों के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल ने चटर्जी को मनाने की कोशिशें कीं, लेकिन परिणाम सिफर रहा। चटर्जी को उनके संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से तृणमूल के छह और कांग्रेस तथा माकपा के एक-एक विधायक भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

खुद हैं अनैतिक, पढ़ा रहे हैं नैतिकता का पाठ : रत्ना

शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी ने शोभन के भाजपा में शामिल होने को लेकर उन पर हमला बोलते हुए कहा कि शोभन खुद इतने अनैतिक हैं कि उन्हें अपने बच्चों तक का खयाल नहीं है। रत्ना ने कहा कि यद्यपि उन्होंने तलाक का मामला दायर किया है, लेकिन उन्हें यह भी खयाल नहीं है कि अपनी बीवी बच्चों को छोड़ कर किसी पराई महिला के साथ अनैतिक तरीके से रह रहे हैं। रत्ना ने कहा कि शोभन को ममता बनर्जी ने एक पार्षद से मंत्री बनाया था और आज उन्होंने दीदी को ही छोड़ दिया।

दहशत में जी रहे हैं सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित : प्रियंका

जागरण संवाददाता, सोनभद्र

- सोनभद्र के उभ्भा गांव का दौरा करने के बाद किए दो ट्वीट

उप्र के सोनभद्र स्थित उभ्भा गांव नरसंहार पीड़ितों का दुख-दर्द सुनने और घटनास्थल देखने के बाद लौटीं प्रियंका वाड्रा ने दिल्ली पहुंचकर बुधवार को ट्वीट कर पीड़ितों से हुई बातचीत को सार्वजनिक किया। कहा कि गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं।

उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल से कुल पांच फोटो के साथ दो ट्वीट किया है। उसमें लिखा- उभ्भा के आदिवासी भाइयों-बहनों से बात करके स्पष्ट हुआ कि उन्हें अपनी जमीन का मालिकाना हक जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वह असुरक्षित रहेंगे। आरोपित प्रधान द्वारा गांव की महिलाओं और पुरुषों पर दर्ज कराए गए मुकदमे और उन पर प्रशासन द्वारा लगाया गया गुंडा एक्ट हटाया जाना चाहिए। अभी तक गांव में पुलिस चौकी नहीं खुली। प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पर जिलाधिकारी सोनभद्र ने भी अपने ट्विटर हैंडल से जवाब दिया कि उभ्भा गांव के लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत गांव में पीएसी तैनात है। एसपी ने कहा कि उभ्भा में पुलिस चौकी 30 जुलाई को ही खुल चुकी है।

प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, सोनभद्र : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित उभ्भा गांव में मंगलवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे के समय एक मीडियाकर्मी का प्रियंका के निजी सचिव से विवाद हो गया। मीडियाकर्मी की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को प्रियंका के निजी सचिव संदीप सिंह पर धारा 323 व 506 के तहत मारपीट व गाली-गलौज का मामला दर्ज कर लिया। मीडियाकर्मी (टीवी चैनल) नीतिश कुमार पांडेय के मुताबिक, वह समाचार कवरेज व प्रियंका से बातचीत करने के लिए काफिले के पीछे जा रहे थे। एक स्थान पर प्रियंका के रुकने पर धारा 370 के संबंध में पूछने का प्रयास किया। इस दौरान उनका निजी सचिव संदीप सिंह भड़क गया और मारपीट करने लगा।

न्यूज गैलरी

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की हालत नाजुक

भोपाल : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है। दवाओं का असर कम हो रहा है। निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें भोपाल के नर्मदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोशल मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर बुधवार को कई तरह की अफवाहें चलती रहीं। उनका इलाज कर रही डॉ. रेणु शर्मा ने बताया कि गौर की हालत चिंताजनक जरूर है पर उनके शरीर में हलचल है। स्वास्थ्य में जैसा सुधार होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। (नईदुनिया)

छग में सरकारी दफ्तरों में नजर आएगी इंदिरा-राजीव की तस्वीर

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब सरकारी दफ्तरों का नजारा बदल रहा है। प्रादेश सरकार ने सरकारी दफ्तरों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। प्रदेश में पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार होने के कारण इन नेताओं की तस्वीरें सरकारी दफ्तरों में नजर नहीं आ रही थीं। सरकारी दफ्तरों में अभी श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें लगी हैं। अब भूपेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यह फैसला करके सरकारी दफ्तरों में कांग्रेस से जुड़े महापुरुषों की तस्वीर को जगह दिया है। (नईदुनिया)

ओडिशा में सीएम व मंत्रियों को नहीं मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर

भुवनेश्वर : स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले ओडिशा में मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं सरकारी अधिकारियों को दिए जाने वाले औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। साथ ही राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेने से पहले मान्यवर कहकर संबोधन करना होगा। यह घोषणा बुधवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकायुक्त, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश के क्षेत्र में पहले से चली आ रही व्यवस्था कायम रहेगी। (जासं)

अवैध नियुक्ति मामले में सदानंद पर चार्जशीट दाखिल

पटना : बिहार विधानसभा में बहाली के करीब 15 वर्ष पुराने मामले में निगरानी ब्यूरो ने विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह, पूर्व सचिव झौरी प्रसाद पाल समेत 42 के खिलाफ बुधवार को कोर्ट में आरोपपत्र दायर कर दिया। मामला बिहार विधानसभा में अफसरों कर्मियों की मिली भगत से अवैध तरीके से 31 लोगों की बहाली का है। निगरानी ब्यूरो ने आरोपपत्र में कोर्ट को जानकारी दी है कि 2000-2005 के बीच बिहार विधानसभा में क्लर्क के पदों पर बहाली हुई थी। बहाली में नियमों की घोर अनदेखी की गई। यहां तक कि बहाली में राज्यपाल के अध्यादेश तक की गलत तरीके से व्याख्या की गई। (राब्यू)

कानून बनाकर आदिवासियों का कर्ज माफ करेगी मप्र सरकार

राहत ▶ 1982 के बाद अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति समुदाय के लिए लाया जाएगा कानून

साहूकारी अधिनियम में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ब्याज दर तय करने का अधिकार सरकार के पास रहेगा

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार 37 साल बाद कानून बनाकर आदिवासियों द्वारा गैर लाइसेंसी साहूकारों से लिए कर्ज को माफ करेगी। 1982 में इस तरह का कानून एक बार के लिए लाया गया था। यही प्रक्रिया अब अपनाई जा रही है। इसके लिए राजस्व विभाग ने मसौदा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है। इसी के साथ सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में ब्याज की दर तय करने का अधिकार अपने हाथ में लेगी। इसके लिए साहूकारी अधिनियम में अध्यादेश के जरिये बदलाव किया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इन बदलावों के लिए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों (89 आदिवासी विकासखंड) में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर गैर लाइसेंसी साहूकारों ने ब्याज पर जो कर्ज (15 अगस्त, 2019 तक) दिया, वो माफ होगा। इसके लिए अनूसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 में नई धारा जोड़ी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक,

कमलनाथ फाइल फोटो

इसके लिए अध्यादेश मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। इसके लागू होने पर बिना लाइसेंसधारी द्वारा ब्याज पर जो भी राशि दी गई है, वो शून्य हो जाएगी। यदि इसकी वसूली के लिए जोर-जबरदस्ती की जाती है तो वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा। दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। अभी तक गैरकानूनी तरीके से ब्याज का धंधा करने पर छह माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही लाइसेंस देने का अधिकार एसडीएम (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) के पास रहेगा। ब्याज की दर भी राज्य सरकार तय करेगी। मौजूदा प्रावधान सात से लेकर 12 फीसद तक ब्याज दर लिए जाने का है।

मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि राजस्व महकमे के पास मौजूद जानकारी के हिसाब से प्रदेश में आज की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्रों में एक भी साहूकारी लाइसेंस क्रियाशील नहीं है। लाइसेंस की अवधि एक साल रहती है और इसका नवीनीकरण कराना होता है।

गिरवी रखी चल-अचल संपत्ति भी होगी वापस

राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर चढ़े कर्ज को माफ करने के लिए नए कानून से 15 अगस्त, 2019 तक गैरकानूनी तरीके से दिया कर्ज शून्य घोषित हो जाएगा। 1975 और 1982 में तत्कालीन सरकारें एक बार के लिए इस तरह का प्रावधान कर चुकी हैं। इस अधिनियम के प्रभावी होने के बाद न तो कर्ज की वसूली के लिए दबाव बनाया जा सकेगा और न ही लेनदार पर कोई बाध्यता होगी। यदि कोई जबरदस्ती करता है तो एसडीएम को शिकायत करने पर तत्काल कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति यह शिकायत करता है कि किसी व्यक्ति ने कर्ज के एवज में चल या अचल संपत्ति गिरवी रखी है तो उसकी भी वापसी कराई जाएगी। इसे न देने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

सपा के दो एमएलसी की मौजूदगी में नीरज ने किया राज्यसभा के लिए नामांकन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर का नामांकन-पत्र बुधवार को जमा होते ही राज्यसभा के लिए उनका पुनः निर्वाचित होना तय हो गया है। उपचुनाव के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह समेत प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में नीरज ने विधानभवन के सेंट्रल हाल में अपना पर्चा दाखिल किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि नामांकन में सपा के दो विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह 'पप्पू' व सीपी चंद भी उपस्थिति रहे।

इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी सीट : राज्यसभा की यह सीट नीरज द्वारा सपा छोड़ने के साथ इस्तीफा देने पर रिक्त हुई थी। इस सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन कराने को दोपहर 12 बजे से ही भाजपा मुख्यालय पर नेता जुटने लगे थे। लगभग एक बजे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा नेता विधानभवन की ओर जुलूस की शक्ल में निकले और 1:20 बजे पार्टी के विधानमंडल दल कार्यालय में पहुंचे। ज्योतिष परामर्श के अनुसार दोपहर 1:30 बजे उन्होंने चार सेट में नामांकन कराया। नामांकन-पत्र की जांच 16 तरीख और नाम वापसी 19 अगस्त को होगी। इसी दिन निर्वाचन की औपचारिक घोषणा होगी।

लखनऊ में बुधवार को राज्यसभा के लिए नामांकन करते नीरज शेखर साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा। जागरण

पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र के पास न गाड़ी न हथियार

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर यूं तो करोड़पति हैं लेकिन उनके पास न अपनी गाड़ी है और न ही उनके नाम से किसी हथियार का लाइसेंस है। उनके पास सोने के जेवरात भी नहीं हैं। बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी निवासी नीरज शेखर ने राज्यसभा सदस्य के लिए बुधवार को भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही अपनी संपत्तियों का ब्योरा दिया है। उनके पास एक करोड़ 84 लाख 94 हजार 646 रुपये की चल संपत्ति है जबकि उन्होंने दो करोड़ 65 लाख 50 हजार रुपये की स्वार्जित संपत्ति बनाई है। नीरज को विरासत में 71 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति मिली है।

उपराष्ट्रपति ने की कैप्टन की तारीफ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 खत्म करने पर पाकिस्तानी मंत्री के बयान पर पलटवार व देश के साथ खड़े होने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की है। पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे उप राष्ट्रपति ने कहा, 'अनुच्छेद-370 को लेकर अलग-अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आईं। कई राजनीतिक पार्टियों ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह धर्म और राजनीति से ऊपर उठ कर देश के साथ खड़े हुए।'

नायडू ने कहा, 'मैंने आज कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक ट्वीट पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि कैप्टन का स्टैंड देश के साथ है। बता दें कि पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट कर पंजाबियों को भड़काने की कोशिश की थी। इस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के मंत्री को आड़े हाथों लिया। कैप्टन ने अपने जवाब में पाकिस्तान के मंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि उनके फूट डालने के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।

नीतीश ही कर सकते हैं मोदी का मुकाबला : शिवानंद

अरविंद शर्मा, पटना

- कभी बिहार के मुख्यमंत्री के बहुत खास थे शिवानंद, आज लालू के साथ हैं

राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हुए उन्हें विपक्ष का सबसे मजबूत पीएम प्रत्याशी बताया है। उनका मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की क्षमता केवल नीतीश कुमार में है। विपक्षी दलों के पास नेतृत्व करने के लायक चेहरे की कमी है। कांग्रेस में शून्यता है। ऐसे में नीतीश को विपक्षी एकता की पहल करनी चाहिए। सत्ता का मोह छोड़कर नीतीश को नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा होना चाहिए। जदयू से राजद में आए समाजवादी शिवानंद को कभी नीतीश कुमार से अपार प्रेम था। इसी प्रेम के बूते वह राज्यसभा की दूरी भी तय कर आए, लेकिन वक्त के साथ दोस्ती पर सियासत का मुलम्मा चढ़ गया। वह फिर से लालू प्रसाद के हो गए और उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य तलाशने लगे।

यह भी कहा : जदयू ने अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे विवादित मुद्दों पर जो स्टैंड लिया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। बिहार की भलाई के लिए भाजपा का साथ छोड़कर देश के सभी विपक्षी दलों का नेतृत्व कीजिए। बस आपमें ही ये क्षमता है कि आप नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकते हैं और अब समय आ गया है कि आप राष्ट्रीय पटल पर आगे बढ़ें।

तलाशे जा रहे मायने : बहरहाल, शिवानंद की नीतीश कुमार पर अचानक मेहरबानी के मायने तलाशे जा रहे हैं। सवाल भी कि 2017 में बिहार में महागठबंधन के बिखरने के बाद नीतीश कुमार को खरी-खोटी सुनाने वाले शिवानंद का हालिया हृदय परिवर्तन का कारण क्या है? उन्होंने अपने बयान में 2013 में भाजपा और जदयू के अलगाव के कारणों का उल्लेख करते हुए नीतीश कुमार को पुराने दिनों की याद दिलाई है। शिवानंद ने विपक्षी दलों को शून्य की ओर बढ़ता बताया है। कांग्रेस को कोसा है। राजद की बेचैनी का भी जिक्र किया है। उन्होंने माना है कि राजद के हालात अभी ठीक नहीं। किंतु तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उन्हें सबकुछ ठीक हो जाने की उम्मीद है।

महागठबंधन को नेता की दरकार

शिवानंद की सदाशयता में साफ झलकता है कि भाजपा और जदयू की रणनीतियों से पस्त महागठबंधन को बिहार में एक नेता की दरकार है। अभी तक यह कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन जिस तरह से वह पिछले तीन महीने से पटना छोड़कर दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं, उससे महागठबंधन के घटक दलों में निराशा का भाव है। यहां तक कि राजद के शीर्ष नेता भी सदमे में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि नेता विहीन राजद को बिखरने से कैसे बचाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अलग राह पकड़ ली है। कांग्रेस भी बिहार में धीरे-धीरे एकला चलो के फार्मूले की ओर बढ़ती दिख रही है। जाहिर है, शिवानंद को आभास है कि अगर स्थिति कुछ दिन और ऐसी ही बरकरार रही तो महागठबंधन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।

रूस की जमीन और उप्र के मैन पावर से होगा विकास : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैंने रूस को प्रस्ताव दिया है कि आपके पास जमीन और हमारे पास मानव संसाधन तथा तकनीक है। दोनों मिलकर एक नया प्रयोग कर सफलता हासिल कर सकते हैं। इस पर सहमति बनी है। वहां कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपार संभावना है। निवेश और व्यापार के जरिये संबंधों को और मजबूत करेंगे।

रूस दौरे से लौटने के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। योगी ने दौरे का पूरा ब्योरा दिया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल निर्देशन में 11 से 13 अगस्त तक भारत के एक बड़े प्रतिनिधि मंडल ने सुदूर पूर्वी रूस का दौरा किया और निवेश व निर्यात की संभावना तलाश की। इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के लिए सात एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। योगी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल पूर्वी रूस के जिस व्लादिवोस्तोक क्षेत्र में गया था वह क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का 35 प्रतिशत और आबादी के लिहाज से सिर्फ पांच फीसद है। वहां बेहद विशाल कृषि योग्य भूमि का उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए वहां भारत के संसाधन और तकनीक के जरिये कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी रूस के उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है।

लखनऊ में बुधवार को अपने सरकारी आवास में रूस यात्रा की जानकारी देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जागरण

तैयारी

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमित शाह का पहला प्रदेश दौरा, बीरेंद्र सिंह के बुलावे पर शुक्रवार को जींद की आस्था रैली में गरजेंगे

हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकेंगे शाह

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हरियाणा आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जींद दौरा खास होगा। वह राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह के बुलावे पर हरियाणा आ रहे हैं। शुक्रवार को बीरेंद्र सिंह को भाजपा में शामिल हुए पूरे पांच साल हो जाएंगे। जींद की धरती से शाह कोई बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकते हैं, जिसकी गूंज पड़ोसी मुल्कों तक सुनाई देगी। इसका असर हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ना तय है। वह जाट-बांगर बेल्ट से प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकेंगे।

पांच साल पहले अमित शाह ने ही बीरेंद्र सिंह को जींद में भाजपा में शामिल कराया था। अब पांच साल बाद बीरेंद्र सिंह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व खासकर मोदी और शाह की जोड़ी के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए रैली कर रहे हैं। इसके पीछे उनका राजनीतिक एजेंडा भी है। आइएएस बेटे बृजेंद्र सिंह को हिसार से चुनाव लड़ाने के लिए बीरेंद्र सिंह ने खुद के राजनीतिक कॅरियर तक की परवाह नहीं की। केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने के साथ ही उन्होंने बेटे को टिकट दिलाने के लिए राज्यसभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र देने की पेशकश कर दी थी। उनका त्याग काम आया और बेटे ने हिसार से जीत दर्ज कराते हुए बीरेंद्र सिंह की राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाल लिया है।

बीरेंद्र सिंह अब चाहते हैं कि उनके राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहते-रहते बृजेंद्र पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंग जाएं। इसके लिए बीरेंद्र भाजपा संगठन व सरकार में लगातार अपने बेटे की पैरवी कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने बेटे को मोदी कैबिनेट में जगह दिलाने की भरसक कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई।

बीरेंद्र सिंह दीनबंधु सर छोटू राम के नाती और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिश्ते में भाई हैं। उनकी पत्नी प्रेमलता जींद जिले के उचाना हलके से भाजपा की विधायक हैं। बीरेंद्र सिंह का अकेला ऐसा परिवार है, जिसमें खुद मुखिया राज्यसभा सदस्य, पत्नी विधायक और बेटा सांसद है।

भाजपा की आस्था रैली के जरिये अमित शाह लगे हाथ हरियाणा में चुनावी बिगुल बजाकर जाएंगे। रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी पांच साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद चल रही प्रतिक्रियाओं के बीच शाह जींद की धरती से कोई बड़ा राजनीतिक संदेश भी दे सकते हैं, जिस पर पूरे देश की निगाह रहेगी।

अमित शाह फाइल फोटो

मोदी को रोहतक बुलाकर सर छोटू राम की प्रतिमा लगवा चुके बीरेंद्र सिंह

इससे पहले बीरेंद्र सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोहतक बुलाकर अपने नाना दीनबंधु सर छोटू राम की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करा चुके हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जब सरकार में अस्थिरता का दौर चल रहा था, तब बीरेंद्र सिंह ने आंदोलनकारियों के साथ बातचीत कर मामले को निपटाने में अहम भूमिका निभाई थी।

झारखंड में अब 57 लाख परिवारों को सुकन्या, कन्यादान योजना का लाभ

राज्य ब्यूरो, रांची

- अभी 30 लाख परिवारों को ही मिल रहा था लाभ
- उज्ज्वला योजना के तहत दूसरा रिफिल भी मुफ्त देगी रघुवर सरकार

झारखंड कैबिनेट ने लोकलुभावन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के मार्ग खोल दिए हैं, तो वर्तमान लाभार्थियों के लिए भी तोहफों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब सभी प्रकार के राशनकार्ड धारी लाभार्थियों की श्रेणी में होंगे। इस तरह अब राज्य के 57 लाख परिवार अब इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। पूर्व में 30 लाख परिवार भी इसके लाभार्थी थे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभुकों को एक और रिफिल मुफ्त देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जिन्हें पूर्व में पांच किलो का सिलेंडर मिला है उन्हें दो रिफिल मिलेगा। वहीं, जिनके पास 14.2 किलो का सिलेंडर है, उन्हें एक रिफिल मुफ्त मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट (डीएमएफटी) से तीन जिलों हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम एवं बोकारो में 13 जलापूर्ति योजनाएं ली गई हैं तो 13 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को भी कैबिनेट की सहमति मिली है।

क्या है सुकन्या योजना : सुकन्या योजना के तहत बेटी की शिक्षा-दीक्षा से लेकर उसके विवाह तक की चिंता की गई है। बेटी के जन्म के साथ, पहली कक्षा में दाखिला, छठी, नौवीं, दसवीं और बारहवीं पास करने पर छह बार में पांच-पांच हजार रुपये उसके खाते में दिए जाते हैं। 18 वर्ष पूरी होने पर एकमुश्त दस हजार रुपये। इस तरह कुल 40 हजार रुपये देने का प्रावधान है।

यह है कन्यादान योजना : पहले यह योजना गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों की बेटियों के लिए ही थी। इस मद में दस हजार रुपये का सामान शादी के वक्त बेटियों को दिया जाता था। अब एकमुश्त 30 हजार रुपये इस मद में देने का प्रावधान किया गया है। 57 लाख परिवारों की बेटियों को इसका लाभ मिलेगा।

उज्ज्वला योजना के तहत 2019-20 में दूसरा रिफिल कराने वालों को लाभ : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर की पहली रिफिल मुफ्त मिल रही है। वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत जो लाभार्थी दोबारा गैस रिफिल कराएंगे उन्हें रिफिलिंग के बाद सिलेंडर की कीमत के बराबर राशि खाते में दी जाएगी।

डीसी बिल के बगैर भी एकमुश्त निकल सकेगी विधायक मद की राशि : कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधायक योजना अंतर्गत डीसी विपत्र लंबित होने के बावजूद आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दे दी है। नियम के अनुसार डीसी बिल के अभाव में फंड की निकासी नहीं की जा सकती है।

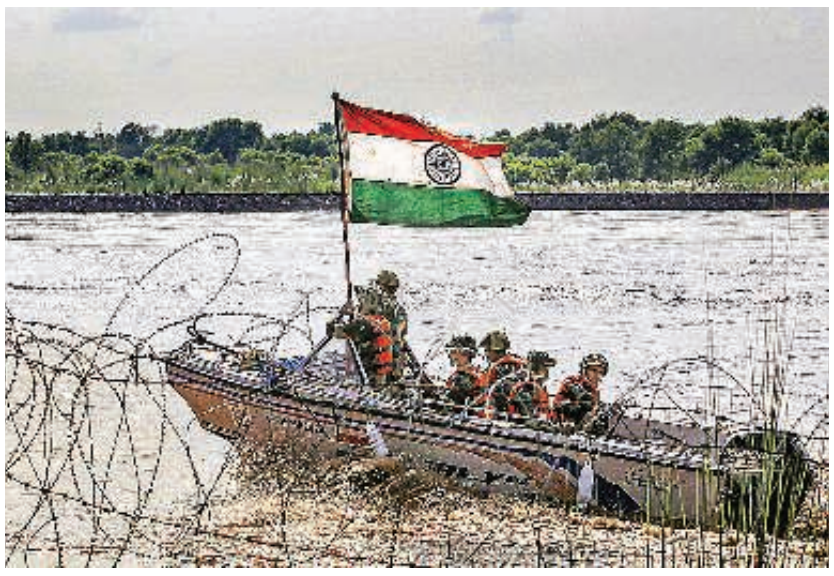

देश के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को जम्मू-कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान की सीमा से लगे इलाके में चिनाब नदी में निगरानी करते बीएसएफ के जवान। प्रेट्र

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को जम्मू में राष्ट्रीय राजमार्ग, संवेदनशील इलाकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। प्रेट्र

वादी में मनेगा आजादी का जश्न, सीमा तक अलर्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- गृह मंत्री शाह नहीं आएंगे कश्मीर, राज्यपाल फहराएंगे तिरंगा
- पाक की नापाक हरकत से निपटने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा
- एनएसए अजीत डोभाल खुद ले रहे हैं सुरक्षा हालात का जायजा

आजादी के 72 साल बाद पहली बार गुरुवार को नए माहौल में स्वतंत्रता दिवस मनेगा। तमाम अटकलों के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर नहीं आ रहे हैं। मुख्य समारोह श्रीनगर के शेरे कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जिसमें राज्यपाल सत्यपाल मलिक तिरंगा फहराएंगे। सब डिवीजनल स्तर पर ध्वजारोहण समारोह होंगे। उधर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सीमा पार से किसी दुस्साहस का जवाब देने के लिए बीएसएफ और सेना पूरी तरह अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिकबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और आसमान पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता और राज्यपाल के प्रमुख सचिव वित्तायुक्त रोहित कंसल ने गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर आगमन के बारे में किसी तरह का जिक्र किए बगैर कहा कि पूरे राज्य में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रत्येक पंचायत और गांव के स्तर पर तिरंगा फहराने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि कश्मीर में या फिर जम्मू में प्रत्येक पंचायत में ध्वजारोहण समारोह किया जा रहा है। सब डिवीजनल स्तर पर समारोह होंगे। उन्होंने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। निषेधाज्ञा में लगातार ढील दी जा रही है, लेकिन गुरुवार को वादी में निषेधाज्ञा को जारी रखेंगे। कई दिनों से यहां डेरा डाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चिनार कोर मुख्यालय में सुरक्षा एजेंसियों के आलाधिकारियों के साथ बैठक की। वह खुद सुरक्षा हालात का जायजा ले रहे हैं।

जिला मुख्यालयों में जहां भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होंगे, वहां की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एहितयातन श्रीनगर, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम में आने-जाने के कई रास्तों को भी एहतियातन बंद रखा जाएगा। जम्मू प्रांत में भी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की लगातार निगरानी की जा रही है। विभिन्न जगहों पर विशेष नाके भी लगाए गए हैं।

कंसल ने कहा कि स्थिति पूरी तरह शांत है। कुछेक जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन स्थिति पर जल्द काबू पा लिया है। जरूरी वस्तुओं का कहीं अभाव नहीं हैं। आवश्यक सेवाओं को पूरी तरह बहाल रखा गया है। इंटरनेट और फोन सेवा की बहाली संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही हालात के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। एडीजीपी सिक्योरिटी मुनीर अहमद खान ने कहा कि शांति और काननू व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी है, सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

कश्मीर में पास के तौर पर इस्तेमाल हो सकेंगे सीएपीएफ परीक्षा के प्रवेश पत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : अभ्यर्थी अखिल भारतीय सीएपीएफ परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र का इस्तेमाल कश्मीर में अपने परीक्षा स्थल तक पहुंचने के लिए पास की तरह कर सकेंगे। यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी। बता दें कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा 18 अगस्त को श्रीनगर सहित देश के 41 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ से जारी बयान में कहा गया, '18 अगस्त, 2019 को सीएपीएफ (सहायक कमांडेंट) परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को मिलने वाले प्रवेश पत्र का प्रयोग वह परीक्षा स्थल तक पहुंचने में कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाए हैं वे परीक्षा में बैठने के लिए वैध आइडी प्रूफ/कार्ड लेकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें।' पांच अर्धसैनिक बलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआइएसएफ, आइटीबीपी और एसएसबी में सहायक कमांडेंट के पद पर इंट्री लेवल के अधिकारियों की भर्ती के लिए संघ लोकसेवा आयोग परीक्षा आयोजित करती है।

अब पाक के लिए दुष्प्रचार ही बना अंतिम सहारा

नापाक हरकत ▶ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से लेकर सेना तक ने शुरू किया कश्मीर पर जबरदस्त दुष्प्रचार अभियान

उकसावे वाले बयानों पर भारत ने अपनाई संयम बरतने की कूटनीति

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

कश्मीर पर दुष्प्रचार करना पाकिस्तान की कूटनीति का हमेशा से हिस्सा रहा है, लेकिन अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के भारत के फैसले के बाद यह कूटनीति पूरे शबाब पर है। हालत यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से लेकर वहां की सेना तक ने कश्मीर के हालात को लेकर भारत के खिलाफ जबरदस्त झूठा अभियान चालू कर दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को जैसे-जैसे यह पता चल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में अनुच्छेद 370 पर उनके रोने-धोने का कोई असर नहीं पड़ रहा, वैसे-वैसे उनका दुष्प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की दूसरे विदेश मंत्रियों के साथ होने वाली बातचीत की सूचना भी तोड़-मरोड़ कर दी जा रही है।

पाकिस्तान सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से कश्मीर पर झूठी खबरें प्रसारित की जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता सोशल मीडिया के जरिये इस तरह का माहौल

शाह महमूद कुरैशी फाइल फोटो

पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे दोनों देशों के बीच अब युद्ध की स्थिति बन चुकी है और युद्ध अवश्यमभावी हो गया है। बुधवार को पाक सेना के प्रवक्ता ने बेहद उकसाने वाला ट्वीट किया, 'कश्मीर पर कोई समझौता नहीं होगा... कश्मीर के लिए पाकिस्तान की सेना हर दायित्व निभाने को तैयार है।' भारतीय विदेश मंत्रालय के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, 'पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो झूठ बोला जा रहा है वह उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वह दुनिया के सामने यह तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। यह जमीनी हकीकत से काफी दूर है।' दूसरी तरफ भारत शुरू से ही बेहद नपे तुले अंदाज में संयम के साथ इसका जवाब दे रहा है।

बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के दुष्प्रचार की कलई तब एक बार और खुली जब विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई टेलीफोन वार्ता की प्रेस रिलीज जारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से जारी रिलीज में इस वार्ता को इस तरह से पेश किया गया है जैसे रूस ने पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया हो। दूसरी तरफ रूस के विदेश मंत्रालय के रिलीज से साफ है कि कश्मीर पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और वह दोनों देशों को आपसी बातचीत से मसले को सुलझाने को कह रहा है। सनद रहे कि कुरैशी ने जब पिछले दिनों चीन की यात्रा की थी तब भी कई तरह का झूठ चलाया था। उनकी बहुत किरकिरी हुई थी जब उन्होंने चीन के होटल के कर्मचारियों से हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाये थे और इसे पाकिस्तान में इस तरह से पेश किया गया था जैसे चीन के अधिकारी उनका स्वागत कर रहे हों। इमरान खान सरकार के रेल मंत्री शेख रशीद अहमद कश्मीर पर झूठी तस्वीरों को भी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से साझा कर रहे हैं। सनद रहे कि भारतीय प्रशासन ने दो दर्जन पाकिस्तान आधारित ऐसे ट्विटर हैंडल की पहचान की है जो कश्मीर पर दुष्प्रचार को चलाने में जुटे हैं। इनको समय-समय पर जम्मू व कश्मीर सरकार की तरफ से भी उजागर किया जा रहा है।

सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान

इस्लामाबाद, एजेंसियां : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मसले पर पाकिस्तान ने तुंरत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बैठक बुलाए जाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएनएससी के अध्यक्ष जोन्ना रोनेक्का को पत्र लिखा है।

पत्र में कुरैशी ने लिखा है, 'मैं आपसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तुरंत बैठक बुलाने का आग्रह करता हूं... ताकि भारत द्वारा की उन हालिया उग्र कार्रवाइयों पर विचार किया जा सके जिनसे अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान संघर्ष के लिए नहीं उकसाएगा, लेकिन भारत को उसके संयम को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए।

पाक राष्ट्रपति बोले, एक हैं कश्मीरी और पाकिस्तानी : पाक के स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार को कहा कि कश्मीरी और पाकिस्तानी एक हैं और उनका देश कश्मीर के लोगों का साथ देता रहेगा।

इस महीने पोलैंड है सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष

इस महीने पोलैंड सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। पोलैंड के विदेश मंत्री जसेक सीजापुटोविज ने पाकिस्तान का पत्र मिलने की पुष्टि की। उन्होंने मतभेद सुलझाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत की पैरवी करते हुए कहा कि पोलैंड के स्थायी प्रतिनिधि जोन्ना रोनेक्का संभवत: पाकिस्तान के अनुरोध पर परिषद के अन्य सदस्यों से विचार-विमर्श शुरू करेंगे।

बिना शर्त कश्मीर जाने को तैयार राज्यपाल बताएं कब आऊं : राहुल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बीच घाटी के हालात को लेकर जारी वाकयुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्यपाल का न्योता कुबूल करने के बाद राहुल गांधी ने बुधवार को सतपाल मलिक से कहा कि वे बिना शर्त कश्मीर आने को तैयार हैं और इसीलिए अब गर्वनर यह बता दें कि वे कब वहां आ सकते हैं।

राहुल ने मंगलवार को न्योता स्वीकार कर विपक्षी नेताओं के साथ कश्मीर आने और वहां लोगों, जवानों और राजनीतिक नेताओं से मिलने और खुले तौर पर घूमने की आजादी सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल से कहा था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की इस टिप्पणी को राजभवन ने जब राजनीतिक करार दिया तब उन्होंने जवाबी दांव चलते हुए बिना शर्त घाटी जाने की बात कही।

राहुल ने बुधवार को राज्यपाल को संबोधित अपने ट्वीट में कहा, 'प्रिय मलिक जी मैंने अपने ट्वीट पर आपका जवाब देखा, मैं जम्मू-कश्मीर की यात्रा करने और लोगों से मिलने के आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। इसमें अब कोई भी शर्त नहीं है। मैं कब आ सकता हूं।' इस ट्वीट के जरिये राहुल ने विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की शर्त छोड़ अकेले भी कश्मीर जाने के लिए तैयार रहने का राज्यपाल को संदेश दिया। कांग्रेस भी घाटी में राजनीतिक नेताओं के आने जाने पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि घाटी के मौजूदा

सत्यपाल मलिक फाइल फोटो

राहुल गांधी फाइल फोटो

उपयुक्त समय पर राहुल से संपर्क करेगा प्रशासन : राजभवन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : राहुल गांधी के बिना शर्त कश्मीर आने का ट्वीट करने के बाद राजभवन ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सांसद ने मामले पर जवाब देने में चार दिन का समय लगा दिया है। यह मामला पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। विभिन्न भारतीय न्यूज चैनलों ने कश्मीर के हालात पर सही स्थिति स्पष्ट कर दी है। मामला निपट चुका है। इस समय पूरा राज्य प्रशासन स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्यपाल ने मामले को पहले ही स्थानीय प्रशासन को भेज दिया है। स्थानीय प्रशासन उपयुक्त समय पर सांसद राहुल गांधी के साथ संपर्क करेगा। राज्यपाल ने इस मामले पर अब तक कोई बयान नहीं दिया था। सनद रहे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया था कि कश्मीर से हिंसा की रिपोर्ट आ रही है। प्रधानमंत्री को पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए। इसपर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गत सोमवार को कहा था कि वह राहुल गांधी के लिए एयरक्राफ्ट भेजेंगे, ताकि वह वास्तविकता को जान सकें। इसपर राहुल गांधी ने कहा था कि वह विपक्षी नेताओं के साथ कश्मीर आने को तैयार हैं। इसपर राजभवन की ओर से बयान आया कि ऐसा कहकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं।

हालात में संचार नेटवर्क पर लगी पाबंदी हटाकर राजनीतिक संवाद शुरू करने से ही स्थिति सामान्य होगी।

प्रेट्र के अनुसार इस बीच कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने राज्यपाल मलिक पर तंज कसते हुए कहा कि उनका राहुल गांधी को निमंत्रण दिखावा मात्र था। वह इस बात को लेकर कभी गंभीर नहीं थे।

विदेश जाने की कोशिश में शाह फैसल गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : नौकरशाही छोड़ रियासत की सियासत में अपना कैरियर संवारने का प्रयास कर रहे पूर्व आइएएस डॉ. शाह फैसल को विदेश जाने से पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाह बुधवार को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया और वापस श्रीनगर भेज दिया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि शाह फैसल इस्तांबुल में होने वाले एक सेमीनार में हिस्सा लेने के लिए तुर्की जा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि उन्हें पीएसए के तहत बंदी बनाया गया है। एडीजीपी आर्म्ड एसजेएम जिलानी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही यह कार्रवाई की गई है।

हालांकि उन्होंने शाह फैसल पर पीएसए लगाने की कोई पुष्टि नहीं की है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद फैसल आखिरी राजनेता हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इनसे पूर्व जम्मू कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कई कश्मीर केंद्रित सियासी दलों के नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी लागू किया जाएगा ईपीएफ एक्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- जेकेईपीएफओ के ईपीएफओ में विलय के साथ ईएसआइसी तंत्र का होगा विस्तार
- केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के विस्तार की तैयारी शुरू

अगले महीने से मोदी सरकार के सारे महकमे केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के विकास की मुहिम छेड़ देंगे। योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में बैठकों के दौर शुरू हो गए हैं। इस क्रम में श्रम मंत्रालय भी सक्रिय हो गया है। जहां नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का लाभ प्रदान करने के लिए वहां ईपीएफ एक्ट लागू करने और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ढांचे का विस्तार करने के बारे में मंथन शुरू हो गया है।

दोनों राज्यों में निवेश तथा औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की रूपरेखा बनाई जा चुकी है। इसी के साथ वहां कर्मचारियों व मजदूरों के वेतन व सामाजिक सुरक्षा के बारे में भी नए सिरे से विचार-विमर्श हो रहा है। इस क्रम में केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के साथ आने वाले समय में इनके विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। फिलहाल जम्मू एवं कश्मीर व लद्दाख में केवल कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 (ईएसआइ एक्ट) के प्रावधान ही लागू हो सके हैं। जिन्हें श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना के जरिये एक अप्रैल, 2017 से प्रभाव में लाया गया था। जबकि कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 वहां लागू नहीं था।

अक्टूबर तक शुरू होगा श्रीनगर में आइआइएम का कैंपस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद फिलहाल कश्मीर घाटी को जो बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है, वह श्रीनगर में आइआइएम कैंपस का खुलना है, जो अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले इसे सितंबर में ही शुरू होना था, लेकिन किराए पर लिए गए भवन की मरम्मत में हो रही देरी के चलते समय को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल यह आइआइएम जम्मू की ही एक शाखा होगी, जो ऑफ कैंपस कहलाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछले दिनों श्रीनगर में आइआइएम के इस कैंपस को खोलने की मंजूरी के साथ ही इसके लिए करीब 52 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद श्रीनगर में इसके लिए किराए पर भवन भी खोज लिया गया है। आइआइएम जम्मू के निदेशक बीएस सहाय के मुताबिक, यह भवन श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब ही लिया गया है। फिलहाल तीन महीने और छह महीने के कुछ प्रबंधन और पेशेवर कोर्स शुरू किए जाएंगे। बाद में इसे और विस्तार दिया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमें दोनों नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों में ईएसआइ की डिस्पेंसरियों के विस्तार एवं नए अस्पतालों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करना शामिल है। जहां तक ईपीएफ एक्ट को लागू करने का प्रश्न है तो इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित किए जाने की संभावना है, जो शीघ्र से शीघ्र अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगा।

उसकी सिफारिशों के आधार पर जेकेईपीएफओ का ईपीएफओ में विलय करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ईपीएफ एक्ट के साथ ही इससे जुड़ी ईडीएलएस, ईपीएफएस तथा ईपीएस जैसी स्कीमें भी जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में लागू हो जाएंगी।

यहां लागू होगा ईएसआइ एक्ट

दो वर्ष पहले जारी अधिसूचना के अनुसार, अविभाजित जम्मू एवं कश्मीर के 14 जिलों में केवल नगरीय सीमाओं के भीतर ईएसआइ एक्ट के चुने हुए प्रावधानों को लागू किया गया है। इनमें जम्मू व घाटी के डोडा, अनंतनाग, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबान, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गंदरबल, कुलगाम व शोपियां जिले तथा लद्दाख के लेह और कारगिल जिले शामिल हैं।

फारूक को नहीं मिली मस्जिद जाने की इजाजत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर की सियासत पर कभी एकछत्र हुकूमत करने वाले डॉ. फारूक अब्दुल्ला को को बकरीद पर मस्जिद जाने की इजाजत नहीं मिली। तीन बार मुख्यमंत्री रहे चुके श्रीनगर के सांसद डॉ. अब्दुल्ला एहतियातन घर में ही नजरबंद हैं। उनके पुत्र व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भाई मुस्तफा कमाल, बहन साफिया और भांजा मुजफ्फर शाह सभी पुलिस हिरासत में अलग-अलग जगहों पर बंद हैं।

सूत्रों ने बताया कि सोमवार को बकरीद के मौके पर नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक रिश्तेदार के जरिये संबंधित प्रशासन को संदेश भेजा कि उन्हें नमाज-ए-ईद के लिए सईद साहब की जियारतगाह में जाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि वह वहां कोई भाषण नहीं करेंगे। किसी से कोई बात भी नहीं करेंगे। मगर अधिकारियों ने उनका आग्रह ठुकरा दिया और उन्होंने अपने घर पुलिस की नजरबंदी में अकेले ही नमाज-ए-ईद अदा की। उन्हें बेटे

फारूक अब्दुल्ला फाइल फोटो

उमर अब्दुल्ला और भाई मुस्तफा कमाल से फोन पर बात करने का भी मौका नहीं दिया गया।

हो सकता था हंगामा : अधिकारियों का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला को मस्जिद में जाने दिया जाता तो हंगामा हो सकता था। शरारती तत्व उनकी जान के लिए संकट पैदा कर सकते थे। सुरक्षा व कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें इजाजत नहीं दी गई। पुलिस के आलाधिकारियों ने कहा कि सेंतूर होटल में कुछ सियासी नेताओं को एहतियातन हिरासत में रखा है, नमाज-ए-ईद के लिए मौलवी भी उपलब्ध करवाया गया था।

भारतीय ट्विटर यूजर्स ने पाकिस्तान का उड़ाया मजाक, हैपीबर्थडेबेटा

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय ट्विटर यूजर्स ने बुधवार को 73वां आजादी दिवस मना रहे पाकिस्तान को जमकर ट्रोल किया है। पड़ोसी देश के लिए हैशटैग हैपीबर्थडेबेटा इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर देश में पांचवें स्थान पर ट्रेंड किया। ध्यान रहे कि 14 अगस्त को ही भारत का विभाजन करके पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। हालांकि, पाकिस्तान इस दिन को ब्रिटिश शासन से आजादी के तौर पर मनाता है। गरीबी और नकदी संकट की मार से जूझ रहा पाकिस्तान बुधवार को 'कश्मीर एकजुटता दिवस' मना रहा है। ऐसा वह भारत के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में कर रहा है। इसके चलते खिसियाए पाकिस्तान ने एक विशेष लोगो भी जारी किया है जिस पर लाल रंग में लिखा है, 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान'।

इसके जवाब में अंकिता श्रीवास्तव नाम की एक ट्विटर यूजर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पोस्ट की है, जिस पर लिखा है, 'हम तुम्हें न दूध देंगे न खीर, अगर कश्मीर मांगोगे

- माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर देश में पांचवें स्थान पर ट्रेंड किया यह हैशटैग
- हैशटैग बलूचिस्तानसोलिडेरिटीडे और हैशटैग 14अगस्तब्लैकडे भी किए ट्रेंड

तो लाहौर भी ले लेंगे।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हैपी बर्थडे बेटा, मेरे जैसा बाप होने पर गर्व महसूस करो।' एक अन्य ट्विटर यूजर

बलूचिस्तान के लोग कर रहे आजादी के लिए संघर्ष

कश्मीर के ताजा घटनाक्रम पर पाकिस्तान के हायतौबा करने के बाद ट्विटर पर अब हैशटैग बलूचिस्तानसोलिडेरिटीडे और हैशटैग 14अगस्तब्लैकडे भी क्रमश: एक लाख ट्वीट से अधिक और 54 हजार ट्वीट के साथ ट्रेंड करता दिखा। पाकिस्तान के सबसे अशांत प्रांत बलूचिस्तान अवैध कब्जे के खिलाफ पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए वर्ष 1948 से संघर्ष कर रहा है। बलूच लोग कहते हैं कि उन्हें ब्रिटिश शासन से आजादी 11 अगस्त, 1947 को मिली थी।

पटेल विनय ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कई देशों से धन के लिए भीख मांगने पर पाकिस्तान की खिंचाई की। खबर लिखे जाने तक 11 हजार ट्वीट्स के साथ हैशटैग हैपीबर्थडेबेटा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था।

ओवैसी ने कहा, मुझे गोडसे के अनुयायी गोली मार देंगे

हैदराबाद, एएनआइ/आइएएनएस : एआइएमआइएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नाथूराम गोडसे के अनुयायी उनकी हत्या कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने का विरोध कर रहे हैं। एआइएमआइएम प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

हैदराबाद में ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा, 'उन्हें कश्मीर से प्रेम है, कश्मीरियों से नहीं। वे केवल सत्ता की चिंता कर रहे हैं, न्याय एवं सेवा के बारे में नहीं। क्या अनुच्छेद 19 वहां लागू नहीं होता है? क्या यह आपातकाल है? जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं उन्हें इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है और आवाजाही के लिए हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जा रहा है। क्या आप 80 लाख लोगों को टेलीफोन पर संपर्क की अनुमति नहीं दे सकते?'

कश्मीर का जनसंख्या अनुपात बदलना चाहते हैं मोदी : ओवैसी ने कहा कि विधानसभा परिसीमन के जरिये मोदी सरकार कश्मीर के जनसंख्या अनुपात में हेराफेरी करने के प्रयास में जुटी है। जम्मू में विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव कर मोदी सरकार भाजपा नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे राजनीतिक विवेक का अभाव होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनसंघ का एजेंडा लागू करने का प्रयास कर रही है।

जनमत
मुद्दा

क्या भारत को अब गुलाम कश्मीर पर दावेदारी की सक्रिय पहल शुरू कर देनी चाहिए?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हैं। **MUDDA** लिखें, स्पेस देकर **YES** या **NO** लिखकर 57272 पर भेजें।

10 लाख रुपये बतौर परफॉरमेंस गारंटी जमा कराने का निर्देश दिया है एनजीटी ने मथुरा नगर निगम को। एनजीटी ने वृंदावन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की धीमी गति पर नाराजगी भी जताई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 15 अगस्त 2019

दुष्कर्म मामले में सेंगर के खिलाफ अलग धाराओं के तहत आरोप तय

उन्नाव कांड ▶ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 सी व 6 लगाई गईं, 10 साल तक की हो सकती है सजा

आरोपित के जन सेवक होने के चलते चलेगा अलग धाराओं के तहत मुकदमा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव कांड में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ धाराएं बदलकर फिर से आरोप तय कर दिए हैं। सेंगर पर अब पॉक्सो एक्ट की धारा 5 सी और 6 के तहत मुकदमा चलेगा, जबकि पहले धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय किए गए थे। कुलदीप सिंह सेंगर जन सेवक है तो ऐसे में अलग धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा।

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने धाराओं में बदलाव करने का आदेश दिया। पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज) एक्ट की धारा 5 सी और 6 के तहत दोष साबित होने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि पहले जिन धाराओं में आरोप तय हुए थे, उनमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है। शुक्रवार से मामले में गवाहों की गवाही शुरू होगी। इस दौरान गवाह और न्यायाधीश के अलावा अदालत में कोई अन्य मौजूद नहीं रहेगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और शशि सिंह पर पिछले सप्ताह आरोप तय हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तीस हजारी अदालत में स्थानांतरित करते हुए 45 दिनों में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था।

आरोप है कि नौकरी देने का वादा करके विधायक सेंगर ने पीड़िता के साथ अपने आवास पर 4 जून 2017 को दुष्कर्म किया था। मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब पीड़िता और उसकी मां ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। पीड़िता के पिता के खिलाफ 3 अप्रैल 2018 को शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और पुलिस हिरासत में अत्यधिक पिटाई के कारण उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में भी मंगलवार को अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।

पीड़िता के घर इज्जतघर का निर्माण शुरू

जागरण संवाददाता, उन्नाव

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के घर इज्जतघर बनाने का काम बुधवार से शुरू हो गया। दैनिक जागरण ने बीते दो अगस्त को यह मामला उठाया था। इसमें गांव की प्रधानी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर होने की बात भी लिखी गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने जांच के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की।

एक ओर प्रधानमंत्री देश को खुले में शौच से मुक्त कराने का बीड़ा उठाए हुए हैं और उनकी पार्टी के विधायक की बहू ने पीड़िता के परिवार को इज्जतघर तक नहीं दिया जबकि गांव में 1114 इज्जतघर बनवाए गए हैं। ध्यान रहे कि बांगरमऊ विधायक के भाई की पत्नी गांव की प्रधान है। जागरण ने मामला उठाया तो डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने सीडीओ को इज्जतघर बनवाने का निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि बुधवार को पीड़िता के घर इज्जतघर का निर्माण शुरू हो गया है।

पीड़िता की दूसरी चाची ने मांगा पीएम आवास : दुष्कर्म पीड़िता की दूसरी चाची ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है। पात्रता जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के दूसरे चाचा की 23 जनवरी 2006 को हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी दो पुत्रों और एक पुत्री के साथ फतेहपुर चौरासी क्षेत्र स्थित गांव मायके जाकर रहीं। यहां दो साल रहने के बाद उन्होंने बांगरमऊ में किराये पर कमरा लिया। पीड़िता की चाची ने सीडीओ को प्रार्थना-पत्र में बताया कि भतीजी के साथ अन्याय का विरोध करने पर आरोपित और उसके करीबियों को उनकी जानकारी हो गई। अब सुरक्षा के मद्देनजर अन्य स्थान पर आवास उपलब्ध कराया जाए। मुख्य विकास अधिकारी प्रेमरंजन सिंह ने परियोजना निदेशक को इस संबंध में जांच के निर्देश दिए हैं।

अनिल के भाग्य का फैसला करेगा भाजपा विधायक दल

राज्य ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के राजनीतिक भविष्य का फैसला पार्टी विधायक दल की बैठक में होगा। भाजपा पुख्ता प्रमाणों के साथ अनिल शर्मा की विधानसभा सदस्यता को चुनौती देकर उन्हें विधानसभा से बाहर करना चाहती है। इस मामले में बुधवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मंत्रणा की। अनिल शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के बेटे हैं।

मानसून सत्र 19 अगस्त को शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में अनिल शर्मा के मामले में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। यदि अनिल शर्मा के खिलाफ आरोप साबित हुए तो उनकी विधायक की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है।

अनिल ने मंडी सदर से भाजपा टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। इस बार लोकसभा चुनाव में उनके पुत्र आश्रय शर्मा को कांग्रेस ने

अनिल शर्मा फाइल फोटो

- हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और मंडी सदर से विधायक हैं अनिल शर्मा
- आरोप साबित हुए तो खतरे में पड़ जाएगी विधायक की कुर्सी

मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। अनिल पुत्र आश्रय के लिए चुनाव प्रचार करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आश्रय की हार के बाद अनिल शर्मा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

मुझे अनिल शर्मा के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर है कि सरकार में मंत्री पद छोड़ने के बाद उनकी वरिष्ठता को देखते हुए सीट तय की गई है।
-डॉ. राजीव बिंदल, विधानसभा अध्यक्ष

मैं घर पर हूं। मेरी अनिल शर्मा के मामले में किसी से कोई बात नहीं हुई है। इस मामले में संगठन की ओर से निर्णय तय होगा।
-नरेंद्र बरागटा, विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक

इस मामले पर पार्टी की बैठक में चर्चा होगी। उसके बाद अनिल शर्मा के मामले में जो उपयुक्त होगा, कार्रवाई की जाएगी।
-सतपाल सत्ती, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष

भीम आर्मी प्रवक्ता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज

जासं, सहारनपुर : फेसबुक पर आपत्तिजनक बयान देकर लोगों को उकसाने के मामले में भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत सिंह नौटियाल के खिलाफ मंगलवार रात सहारनपुर के थाना बेहट में राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की विवेचना शुरू हो गई है।

थाना बेहट के मोहल्ला खालसा निवासी भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत सिंह नौटियाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़े गए संत रविदास मंदिर को लेकर मंगलवार सुबह फेसबुक लाइव कर आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि न्यायालय 21 अगस्त से पहले मामले का संज्ञान लेकर मंदिर में पुनः प्रतिमा स्थापित कराए। यदि देश का माहौल खराब होता है तो इसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। नौटियाल ने भीम आर्मी से जुड़े लोगों को अपने लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए भी उकसाया था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर पूर्व पीएम स्व. इंदिरा गांधी की हत्या के प्रकरण से भी सबक लेने की बात कही थी। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार रात 1.45 बजे थाना बेहट में मंजीत के खिलाफ धारा 124-ए, 153-ए, 505 (1), 505 (1) (बी), 505 (1) (सी), 505 (2) तथा 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। मंजीत नौटियाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फेसबुक लाइव के वीडियो की भी जांच शुरू कर दी गई है।

जांच में फंस रहे हैं आजम खां के चहेते कई अफसर

मुस्लेमीन, रामपुर : प्रशासन ने एक माह में सांसद आजम खां के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। अब सपा शासनकाल में आजम के करीबी रहे कई अफसर भी फंसते नजर आ रहे हैं।

अब तक आजम के खिलाफ जमीन कब्जाने के 29 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी की 140 बीघा जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने आजम को भू-माफिया भी घोषित किया दिया है। उनके करीबी यूनिवर्सिटी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आलेहसन खां पर भी जमीन कब्जाने, मकान तोड़ने और लूटपाट के 38 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उनका लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। अजीमनगर में थाना प्रभारी रहे कुशलवीर के खिलाफ भी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के लिए लोगों को धमकाने व हवालात में बंद करने के मुकदमे लिखवाए गए हैं। इसके अलावा सपा शासनकाल में और भी कई अधिकारी ऐसे रहे हैं, जो कई मामलों में फंस सकते हैं। ये अधिकारी आजम के करीबी माने जाते रहे हैं। डीएम का कहना है कि जांच कमेटी ने अभी तक जो पड़ताल की है, उसमें

- नदी क्षेत्र की जमीन मुहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने, सर्किल रेट कम करने का आरोप

कई अफसर फंसते नजर आ रहे हैं।

लीज पर दे दी नदी क्षेत्र की जमीन : जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए नदी क्षेत्र की जमीन ही लीज पर दे दी गई, जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं किया जा सकता है। साथ ही बहाव क्षेत्र में पक्का निर्माण भी नहीं कराया जा सकता है। पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि लीज पर लेने के लिए शासन को जो रिपोर्ट भेजी गई, उसमें कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस जमीन को नदी क्षेत्र के बजाय नवीन परती बता दिया। नदी क्षेत्र की जमीन यूनिवर्सिटी में मिलाने की शिकायत एनजीटी में भी की गई है, उसमें भी जांच के आदेश हुए हैं। जलनिगम की सीएंडडीएस (कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज) द्वारा भी घपले सामने आ रहे हैं। करीब दो करोड़ रुपये बिना काम कराए ही एक फर्म को दे दिए गए। इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है।

धोखाधड़ी के मामले में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने दर्ज कराए बयान

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद

धोखाधड़ी के मामले में बयान दर्ज कराने फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा बुधवार को मुरादाबाद पहुंचीं। उनके साथ आए भाई कुश ने कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया। सोनाक्षी के अधिवक्ता मुनेश प्रेम का कहना कि वादी प्रमोद शर्मा इंडिया फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड नाम से इवेंट कंपनी चलाते हैं। प्रमोद ने सोनाक्षी जैसी बड़ी अभिनेत्री को बदनाम करने की साजिश रची है। हम फिर भी उसकी रकम वापस करने को तैयार हैं लेकिन, इसके लिए उन्हें कोर्ट में माफी मांगनी होगी।

सुबह करीब 11:30 बजे सोनाक्षी अपनी टीम के साथ प्रेमवंडर लैंड स्थित एक होटल में पहुंचीं। दस दिन पहले विवेचक कोतवाली कटघर के वरिष्ठ उप निरीक्षक अजय पाल सिंह ने सोनाक्षी और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी को नोटिस भेजकर बयान देने के लिए बुलाया था। सोनाक्षी ने लिखित में अपना बयान दिया। विवेचक के मुताबिक सोनाक्षी ने बयान में कहा है कि दिल्ली के शो में आने के लिए 24 लाख

- अभिनेत्री के वकील ने कहा, वादी कोर्ट में माफी मांगे तो हम पैसा लौटाने को तैयार
- सोनाक्षी ने पुलिस को लिखित में अपना बयान दिया

सोनाक्षी सिन्हा फाइल फोटो

रुपये प्लस जीएसटी में उनका एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के मुताबिक उन्हें 28 लाख 32 हजार रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन आयोजकों ने 1.90 लाख कम दिए। पेमेंट भी शर्तों के मुताबिक निर्धारित तिथि में नहीं मिली। एयर टिकट बुक कराकर नहीं भेजे गए। एयर टिकट नहीं कराने पर उन्हें एयरपोर्ट से लौटना पड़ा। स्टाफ को अलग से पैसा दिया जाता है, वह भी नहीं मिला। आयोजकों ने उनके ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं की थी। सीओ कटघर सुदेश गुप्ता ने बताया कि सोनाक्षी आयोजक की रकम वापस करने को तैयार हैं, लेकिन उनके अधिवक्ता का कहना है कि इसके लिए वादी को माफी मांगनी होगी।

प्रमोद ने कहा-मैं क्यों माफी मांगू : सोनाक्षी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाने वाले प्रमोद शर्मा का कहना है कि मैं क्यों माफी मांगू। पहले तो सोनाक्षी और उनकी टीम के लोग रकम लेने की बात ही नहीं स्वीकार कर रहे थे। कम से कम अब स्वीकार तो किया। कार्यक्रम रद होने के बाद मेरी लोगों ने जो पिटाई की, उसका हर्जाना कोई दे सकता है क्या? मैंने कार्यक्रम के दिन सुबह 10 बजे के एयर टिकट बनवा कर भेजा था।

ऐसी नारी समाज के लिए धब्बा, जो रुपये हड़पने के लिए किसी हद तक जाए : कोर्ट

विनीत तोमर, रोहतक

- मामला संज्ञान में आने पर कोर्ट ने की टिप्पणी, महिला पर दिए केस दर्ज करने के आदेश
- दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई

ऐसी नारी समाज के लिए धब्बा है, जो रुपये हड़पने के लिए किसी भी हद तक जाकर इल्जाम लगा सकती है। ऐसी नारी पीड़िता कहलाने लायक नहीं है। बुधवार को दुष्कर्म के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए महिला के खिलाफ ही केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिस व्यक्ति पर महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उसकी अग्रिम जमानत को भी कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

यह था मामला : जिले के एक गांव में रहने वाली महिला ने जून में आइएमटी थाने में शिकायत दी थी। आरोप लगाया कि नौकरी का झांसा देकर जसिया के धर्मबीर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

कोर्ट में कुछ ऐसे पलटा केस : अग्रिम जमानत याचिका दायर करने वाले आरोपित ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में महिला का पुराना रिकार्ड सबूतों के साथ पेश कर दिया। बताया कि महिला ने 2017 में भी झज्जर के तीन आरोपितों पर तीन दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस की जांच में सामने आया कि जिन तीन दिनों में महिला खुद को झज्जर में बंधक होना बता रही है, उसमें उसकी लोकेशन एक दिन रोहतक में मिली और एक दिन की लोकेशन किसी परिचित के यहां शादी की।

आरोपितों ने कोर्ट में सबूत के तौर पर महिला के शादी में शरीक होने के 19 फोटो भी पेश कर दिए थे। जिसके बाद वह मुकदमा रद कर दिया गया था। वहीं महिला की शादी वर्ष 2002 में हुई थी। जिससे उसकी शादी हुई थी उससे उसके दो बच्चे हैं। लेकिन वर्ष 2017 में उसने गुरुग्राम के आर्य समाज मंदिर में दूसरे युवक से शादी कर ली थी। महिला के पहले पति ने भी उस पर केस दर्ज कराया था कि बिना तलाक दिए दूसरी शादी कैसे कर ली।

नक्सलियों के वेश में लूटते थे पुलिसवाले

नईदुनिया, नारायणपुर

नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में नक्सली बनकर पुलिस के जवान ही लोगों से लूटपाट कर रहे थे। पुलिस नक्सली वारदात मानकर जांच करती रही। मामला तब खुला जब लूटे गए मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस को कामयाबी मिली।

नायायणपुर पुलिस पिछले कुछ दिनों में हुई ताबड़तोड़ लूट की वारदात से हैरान और परेशान थी। वह जांच तो कर रही थी, मगर उसको कोई कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। इसी बीच गत मंगलवार रात बेनूर थाना के पास कोकोड़ी गंगामुंडा में बस्तर ट्रैवल्स की एक यात्री बस को आग लगा दी गई। वारदात को अंजाम इस तरह दिया गया जैसा नक्सली करते रहे हैं। चार नकाबपोशों ने मंगलवार की रात सड़क पर मोटरसाइकिल आड़ी-तिरछी खड़ी कर दी। यात्री बस (सीजी-17 एफ-0930) सड़क पर रुक गई, तभी नकाबपोश हथियारबंद कथित नक्सलियों ने बस को कब्जे में ले लिया। उन्होंने यात्रियों और चालक-परिचालक के मोबाइल लूट लिए। फिर सभी को नीचे उतारकर बस में आग लगा दी।

एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि बस जलाये जाने की घटना के दौरान लूटे गए एक मोबाइल की लोकेशन जिले के ग्राम बम्हनी थाना जिला कोंडागांव में मिली। टीम कोंडागांव गई। वहां बस्तर और कोंडागांव पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर पुलिस ने बम्हनी गांव से आत्मसमर्पण कर पुलिस विभाग में सहायक आरक्षक पद पर भर्ती माधव कुलदीप (35) को उसके घर में दबोच लिया। उसके पास से दो एयर पिस्टल, लूट की चार मोबाइल, बाइक और नगद राशि बरामद की। उसकी निशानदेही पर हिरदूराम कुमेटी और डोलेंद्र बघेल को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें हिरदूराम पुलिस विभाग का बर्खास्त आरक्षक है, जबकि आरक्षक माधव काफी समय से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहा था।

तहकीकात

- लूटे हुए मोबाइल का लोकेशन ट्रेस करने पर चढ़े हत्थे, कई मामले खुले
- आत्मसमर्पण कर पुलिस विभाग में शामिल जवान भी कारनामे में शामिल

इन वारदात में भी रहे शामिल

31 जुलाई : ओरछा मार्ग पर दो गाड़ी वालों को रोककर 11500 रुपये लूटे।

02 अगस्त : दंडवन-फरसगांव के सीसी मार्ग पर तीन लोगों को रोककर रुपये और मोबाइल लूटे।

04 अगस्त : मारडूम-बारसूर मार्ग पर गाड़ी वालों को रोककर 17500 रुपये, मोबाइल लूटे। गुप्ता ट्रैवल्स से पांच लाख रुपये की मांग की।

11 अगस्त : कोकोड़ी कैंप के पहले रास्ता रोककर गाड़ी वालों से 11 हजार रुपये लूटे।

एक लाख के इनामी नक्सली ने किया समर्पण

नईदुनिया, दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ में बीजापुर के करकावाड़ा निवासी जनमिलिशिया कमांडर बामन ने दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। वह नक्सलियों के इंद्रावती एरिया कमेटी का सक्रिय नक्सली था। कई वारदात में शामिल रहा, लेकिन अब मुख्यधारा में जिंदगी जीना चाहता है। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बीजापुर के बांगापाल थानांतर्गत ग्राम करकावाडा निवासी बामन नक्सलियों की विचारधारा से ऊबकर नई जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए समर्पित नक्सलियों के जरिये एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव से फोन पर बात करने के बाद बुधवार को दंतेवाड़ा पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया।

आरएसएस संस्थापक को श्रद्धांजलि

आरएसएस के संस्थापक और प्रथम सर संघचालक डॉ. केशव राव बलिराम हेडगेवार की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करने अभिनेता और भाजपा सांसद सनी देयोल बुधवार को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। प्रेट्र

मुजफ्फरनगर में महिला थाने की प्रभारी समेत सभी लाइन हाजिर

जासं, मुजफ्फरनगर : उप्र के मुजफ्फरनगर में दारोगा सीमा यादव के जहर खाने के घटनाक्रम के बाद एसएसपी अभिषेक यादव ने मंगलवार देर रात सीमा यादव के अलावा महिला थाने की प्रभारी निरीक्षक सहित पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया।

महिला थाने में तैनात दारोगा सीमा यादव ने अपने आवास पर मंगलवार शाम करीब चार बजे जहर खा लिया था। सीमा ने बयान में कहा था कि उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। सीओ सिटी हरीश भदौरिया ने बताया था कि महिला थाने में दहेज उत्पीड़न व अन्य संगीन धाराओं में दर्ज एक मुकदमे में आरोपित पक्ष की ओर से शिकायत की गई थी कि प्रभारी निरीक्षक ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाने के लिए ढाई लाख रुपये की रिश्वत ली थी। सीओ ने बताया था कि जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे, जिसके बाद एसएसपी के आदेश पर की गई जांच के बाद एसएचओ प्रीता रानी, एसआइ ज्योति तोमर, विजयपाल सिंह अत्री, निधि चौधरी, संतोष चौधरी, महिपाल सिंह, संतोष कुमार गौतम, एसआइ तारा ढिल्लन के अलावा हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी, हेड मोहर्रिर इंदिरा नेगी व 38 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया।

प्रयास

दस साल पहले दिखने जैसा चेहरा किया गया तैयार, फेसबुक और वाट्सएप के जरिये किया गया वायरल

फेसएप की मदद से खोजा जा रहा गीता का परिवार

नईदुनिया, इंदौर

पाकिस्तान से भारत आई मूक-बधिर गीता के परिवार को तलाशने के लिए फिर कोशिश शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ द्वारा 'फेसएप' के जरिये गीता के माता-पिता को ढूंढा जा रहा है। फेसबुक की एप्लीकेशन से गीता का 10 साल पहले का चेहरा तैयार किया गया है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है।

गौरतलब है कि 27 वर्षीय मूक-बधिर गीता को 2016 में पूर्व विदेश मंत्री स्व. सुषमा स्वराज द्वारा पाकिस्तान से भारत लाया गया था। तीन साल में गीता के परिजन का पता नहीं चला। देशभर से करीब 24 दंपतियों ने उसको अपनी बेटी होने का दावा किया, लेकिन एक से भी उसका डीएनए सैंपल नहीं मिला। न गीता ने किसी दंपती के उसके माता-पिता होने की हामी भरी। इसके बाद से लगातार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि क्या गीता को उसका परिवार मिल सकेगा। उधर, सालभर से तलाश का सिलसिला लगभग बंद

फेसएप से तैयार गीता की फोटो।

था। न शासन, प्रशासन और न ही सामाजिक स्तर पर परिवार को तलाशने की कोशिश की गई। इस बीच, हाल ही में सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र पुरोहित द्वारा फेसबुक के फेसएप का उपयोग करते हुए गीता के 10 साल पहले का 'फेस' तैयार किया गया है। इसे फेसबुक और वाट्सएप के जरिये देश-विदेश में वायरल किया गया है। पुरोहित का कहना है कि यह गीता को उसके परिवार से मिलाने की कोशिश है। अगर यह सफल रही तो उन्हें काफी खुशी होगी।

मिलने लगे हैं संकेत

फेसएप के जरिये तैयार फोटो वायरल होने के बाद देशभर से गीता की पहचान के संबंध में संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। कुछ मूक-बधिर युवतियों ने गीता को उनकी सहेली होने के संकेत दिए हैं, लेकिन उस बिंदु पर अभी जांच चल रही है। पुरोहित के मुताबिक, इस पर अभी काम चल रहा है। जल्द ही चेहरे को और ज्यादा स्पष्ट और पीछे की उम्र में ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। गीता करीब 10 साल की उम्र में गायब होने की बात कहती है, जबकि अभी उसकी उम्र करीब 27 साल है।

शासन को भेज रहे प्रस्ताव

पुरोहित के मुताबिक, तीन साल में गीता का परिवार नहीं मिल सका और न ही उसका पुनर्वास हुआ है। वे शासन, प्रशासन को गीता के पुनर्वास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। उनका कहना है कि वे कई मूक-बधिर बच्चों को विशेष तकनीक के जरिये परिवार से मिलवा चुके हैं। अगर गीता को भी कुछ दिन विशेष लड़कियों के शासकीय छात्रावास में रखा जाएगा तो वह परिवार तलाशने में सफल हो सकते हैं। उन्हें शासन से इसके लिए अनुमति की प्रतीक्षा है।

व्यक्तियों को आतंकी घोषित करने वाला नया आतंक विरोधी कानून लागू

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि एक नया आतंकवाद विरोधी कानून लागू हो गया है जिसके तहत व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कानून को आठ अगस्त को अनुमोदित किया था। लोकसभा इसे 24 जुलाई एवं राज्यसभा दो अगस्त को पारित कर चुकी है।

गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, 'केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 2019 (2019 का 28) के खंड 1 के उप खंड (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 14 अगस्त 2019 को वह तिथि नियत की जिस दिन से उक्त कानून के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे।'

इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। इस कानून से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को आतंकवाद से अर्जित की जाने वाली संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिलेगा।

पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा बॉलीवुड

जेएनएन, नई दिल्ली

- सीआरपीएफ ने जारी किया 'तू देश मेरा' श्रद्धांजलि गीत का पोस्टर
- आज जारी होगा टीजर, शाहरुख सहित कुछ अभिनेताओं ने दी है आवाज

पुलवामा शहीदों को की याद में एक वीडियो 'तू देश मेरा' तैयार किया जा रहा है। इसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, आमिर खान, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन और रणबीर कपूर इन वीरों को श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने श्रद्धांजलि गीत 'तू देश मेरा' के पोस्टर का अनावरण किया। बता दें कि 14 फरवरी को आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद द्वारा सीआरपीएफ काफिले पर किए गए आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे।

सीआरपीएफ ने ट्विटर पर गाने का पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'यह पुलवामा के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि गीत 'तू देश मेरा' का आधिकारिक पोस्टर है। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बॉलीवुड एक साथ आया है।' ट्वीट में पोस्टर में नजर आने वाले सितारों को भी टैग किया गया है। पोस्टर में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन और रणबीर कपूर जवानों को सैल्यूट करते नजर आ रहे हैं।

इस गीत को मुख्य तौर पर जावेद अली, जुबिन नौटियाल, शाबाब साबरी और कबीर सिंह ने गाया, लेकिन शाहरुख के अलावा कुछ अभिनेताओं ने भी इसमें अपनी आवाज दी है। वीडियो की शूटिंग में 150 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे हैं। मीत ब्रदर्स ने इसका संगीत तैयार किया है जबकि इसकी रचना कुमार ने की। वीडियो का प्रोडक्शन हैप्पीप्राडइंडिया ने किया है। अभी तक इस गाने की लांच होने की तारीख सुनिश्चित नहीं हुई है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर इस गाने का टीजर रिलीज किया जाएगा।

स्वतंत्रता के स्वर्णिम सात दशक

सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत का करीब तीन सौ साल तक दोहन करने के बाद जब अंग्रेज यहां से गए तो आर्थिक, सामाजिक दुश्वारियां छोड़ गए। हमने वहीं से नई शुरुआत की। देश को दिलोजान से सींचा और संवारा। आज फिर हम शीर्ष शक्तियों में शुमार हैं। यह सफलता धीमे लेकिन मजबूत कदमों के बूते मिली। कामयाबियों की अनंत कहानी है। ऐसे में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सात दशकों के ऐतिहासिक क्षणों को याद करके गर्वानुभूति होना लाजिमी है।

1948 हॉकी में ओलंपिक गोल्ड
आजादी के अगले वर्ष देश की पुरुष हॉकी टीम ने लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। यह आजाद देश का पहला गोल्ड मेडल था।

1950 लागू हुआ संविधान
लागू संविधान ने देश को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया।

1952 पहले चुनाव
गणराज्य बनने के बाद लोगों के सामने अपनी सरकार चुनने का अवसर था। 1952 में पहले लोकसभा चुनाव हुए। देश के तकरीबन 17 करोड़ लोगों ने इसमें मतदान किया। जवाहर लाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए। अब तक 14 बार केंद्र में सरकारें बदल चुकी हैं।

1954 भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर की स्थापना
मुंबई के उपनगर ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। 1967 में इसे भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर नाम दिया गया।

मौजूदा समय में यहां आठ परमाणु संयत्र काम कर रहे हैं।

1966 रीता बनीं मिस वर्ल्ड
मुंबई की रहने वाली रीता फारिया विश्व सुंदरी का खिताब अपने नाम करने वाली देश की पहली महिला बनीं। इसके बाद 1994 में सुष्मिता सेन ब्रह्मांड सुंदरी और ऐश्वर्या राय ने विश्व सुंदरी का खिताब जीता।

1970 श्वेत क्रांति
इस क्रांति को दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम कहा जाता है। इसने दूध की कमी से जूझ रहे हमारे देश को सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले देश में बदल दिया। अमूल के संस्थापक वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं।

1974 पहला परमाणु परीक्षण
देश का पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ। इसे बुद्ध मुस्कुराए नाम दिया गया।

1975 आर्यभट्ट का प्रक्षेपण
इसरो ने पहले भारतीय स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा।खगोलविद्ध आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया। लागत तकरीबन तीन करोड़ रुपये थी। इसके सफल प्रक्षेपण ने भारत को दुनिया के उन देशों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया, जिनके पास अपना उपग्रह था।

2005 सूचना का अधिकार
देश के नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। यह नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार उन सवालों के जवाब दे।

2008 चंद्रयान
अक्टूबर में इसरो ने चंद्रमा पर मानवरहित यान भेजा। इसी से नासा को चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता चला।

2013 मंगलयान
पहले ही प्रयास में मंगल पर कदम रखने वाला चौथा देश बना। महज 450 करोड़ की लागत अमेरिका, रूस और यूरोप के मंगल अभियानों से कई गुना कम रही। भारत की इस उपलब्धि को दुनिया की सलामी मिली।

2014 पोलियो से मुक्ति
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। 1995 से लगातार अभियान के बाद यह मुकाम मिला। पहले सालाना पचास हजार से अधिक बच्चे पोलियो से ग्रस्त हो जाते थे।

2017 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण
फरवरी में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का रिकॉर्ड बनाया। रूसी एजेंसी का एक बार में 37 उपग्रह भेजने का रिकॉर्ड इसरो ने ध्वस्त किया।

2019 चंद्रयान-2
14 जुलाई को लांच हुआ चंद्रयान 2 भारतीय चंद्र मिशन है, जो चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। इसका मकसद, चंद्रमा के प्रति जानकारी जुटाना और ऐसी खोज करना जिनसे भारत के साथ ही पूरी मानवता को फायदा होगा।

अनुच्छेद 370
सत्तर साल से जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं।

लगातार तीसरे हफ्ते औसत से ज्यादा बारिश, दक्षिण भारत में बाढ़ से तबाही

प्रकोप ▶ महाराष्ट्र समेत दक्षिण-पश्चिम भारत के राज्यों में मरने वालों की संख्या 270 हुई

उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में सूखे की आशंका हुई कम

कोल्हापुर में बाढ़ का पानी उतरने पर लोग खाना बनाने के बर्तनों को साफ करने में लग गए। प्रेट्र

मुंबई, रायटर : देश में लगातार तीसरे हफ्ते औसत से ज्यादा मानसूनी बरसात हुई है। इससे कुछ हिस्सों में सूखा पड़ने की आशंका तो कम हुई है, लेकिन दक्षिण और पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और केरल में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 270 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 12 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं।

सबसे बुरा हाल केरल में है। मंगलवार रात से शुरू हुई दक्षिण पश्चिम मानसूनी बारिश बुधवार को भी जारी रही, जिससे हालात और बदतर हो गए। राज्य में मरने वालों की संख्या 102 हो गई है और 27 लोग अभी भी लापता हैं। 1200 से ज्यादा राहत शिविरों में हजारों लोग शरण लिए हैं। राज्य को अभी बारिश से राहत भी नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

पुणे बाढ़ से बेहाल : बारिश और बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों में हालात में तो धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन पुणे मंडल में हाल बेहाल हो गया है। अकेले पुणे मंडल में 48 लोगों की जान जा चुकी है। पुणे के साथ ही सांगली, कोल्हापुर, सतारा और सोलापुर जिलों में लगभग पांच लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 46 गांव पूरी तरह से कट गए हैं। वहीं, कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित हासन जिले में चार और लोगों के शव मिलने से मरने वालों की संख्या 58 हो गई है। हालांकि, नदियों और जलाशयों में पानी कम होने से स्थिति पहले से बेहतर हुई है। आला अधिकारी प्रभावित इलाकों में डेरा डाले हुए हैं।

आरबीआइ गवर्नर को राहुल का खत : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावित केरल के किसानों को कृषि कर्ज अदायगी की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। राहुल केरल के वायनाड से सांसद हैं, जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शामिल है। राहुल ने कहा है कि केरल सदी की सबसे भीषण बाढ़ की चपेट में है। फसलों और अन्य संपत्तियों के नुकसान के चलते किसानों को इस समय कृषि कर्ज को चुकता करना मुश्किल होगा। राज्य स्तरीय बैंक समिति ने कर्ज चुकाने की समयसीमा को बढ़ाने से इन्कार कर दिया है।

भारत में बाढ़ से मौतों पर यूएन अध्यक्ष दुखी

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र(यूएन) महासभा की अध्यक्ष मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा ने भारत में भयंकर बाढ़ से हुई मौत की घटनाओं पर दुख व्यक्त किया है। यूएन महासभा की अध्यक्ष की प्रवक्ता मोनिका ग्रेलेय ने बताया कि एस्पिनोसा ने भारतीय सरकार और वहां के लोगों को संदेश भेजकर बाढ़ से हुई मौतों पर सहानुभूति प्रकट की है। ग्रेलेय ने आगे कहा कि अध्यक्ष ने इस कठिन परिस्थिति में प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता प्रकट की है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में मानसून की तेज वर्षा से उत्पन्न बाढ़ से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अकेले केरल से 91 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में भी तेज बारिश से जुड़ी आपदाओं ने कहर बरपाया है। राहत व बचाव कर्मी बाढ़ में फंसे लाखों लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। उनके घरों तक राहत व खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है।

दैनिक जागरण के भारत रक्षा पर्व के तहत बुधवार को नई दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत को राखियां और संदेश भेंट करते दैनिक जागरण के प्रधान संपादक और सीईओ संजय गुप्त, साथ में हैं राजनीतिक संपादक प्रशांत मिश्र। दैनिक जागरण रक्षा बंधन त्योहार के पहले भारत रक्षा पर्व का आयोजन करता है। लगभग एक महीने तक यह पर्व चलता है जिसमें देश के 30 शहरों से फौजी भाइयों के लिए राखी एकत्र की जाती है। जागरण

सरहद पर तैनात जवानों को देश की बहनों ने भेजीं राखियां

जेएनएन, नई दिल्ली

▶ महीने भर तक चला दैनिक जागरण का भारत रक्षा पर्व

29 लाख से अधिक राखियां व 11 लाख से अधिक संदेश सीमा तक पहुंचे

देश की रक्षा में सीमा पर तैनात हमारे देश के फौजी भाइयों को रक्षा बंधन के पावन अवसर पर कैसे भूला जा सकता है। 'दैनिक जागरण' डेढ़ दशक से ज्यादा समय से हर साल रक्षा बंधन के मौके पर प्यार के इस धागे को सीमा पर तैनात फौजी भाइयों की कलाइयों तक पहुंचाता है।

'दैनिक जागरण' रक्षा बंधन त्योहार के पहले भारत रक्षा पर्व का आयोजन करता है। लगभग एक महीने तक 'भारत रक्षा पर्व' चलता है जिसमें देश के अलग-अलग 30 शहरों से फौजी भाइयों के लिए राखी जमा की जाती है। इस वर्ष भारत रक्षा पर्व 15 जुलाई से 14 अगस्त तक मनाया गया। इस दौरान 29 लाख से अधिक राखियां जमा की गईं। इन राखियों को जमा करने के लिए भारत रक्षा पर्व के विशेष रथों ने 6000 किलोमीटर की यात्रा की और 1100 स्थानों पर जाकर राखियां जमा की। राखियों के अलावा 11 लाख से अधिक पोस्टकार्ड संदेश भी एकत्र किए गए। इन राखियों और पोस्टकार्ड संदेशों को जम्मू, अमृतसर और सिलीगुड़ी में फौजी भाइयों के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों को सौंप दिया गया।

'भारत रक्षा पर्व' में 'दैनिक जागरण' के पाठकों के अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने हिस्सा लिया और अपने हाथों से राखियां बनाकर अपनी भावनाओं के साथ सीमापर भेजा। भारत रक्षा पर्व के फेसबुक पेज पर भी लोगों ने सैनिक भाइयों के लिए अपने प्यार का इजहार किया। भारत रक्षा पर्व का उद्देश्य है कि सीमा पर तैनात देश के प्रहरियों का यह अहसास मजबूत हो कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इस वर्ष दैनिक जागरण के भारत रक्षा पर्व को अभिनेता विनय पाठक और अनूप सेठी के अलावा मिस ग्रांड इंडिया अनुकृति गोसाईं का साथ भी मिला।

बर्खास्त आइपीएस संजीव से मिलने जा रहे हार्दिक को हिरासत में लिया गया

पालनपुर (गुजरात), प्रेट्र : बर्खास्त आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को बुधवार को हिरासत में ले लिया गया। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के साथ पार्टी के दो विधायक महेश पटेल एवं किरीट पटेल और 27 समर्थक भी हिरासत में लिए गए हैं। यह लोग पालनपुर जिला कारागार जा रहे थे। हिरासत में मौत के एक मामले में भट्ट को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह अभी पालनपुर जिला कारागार में कैद हैं।

बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक प्रदीप सेजुल के मुताबिक कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते हार्दिक पटेल, दोनों विधायकों एवं उनके समर्थकों को पालनपुर में प्रवेश करते ही हिरासत में ले लिया गया।' उन्होंने बताया कि बर्खास्त आइपीएस अधिकारी भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने मंगलवार को कहा था कि वह अपने पति के उन समर्थकों का साथ देगी, जो उन्हें पालनपुर जेल में राखी बांधना चाहती हैं।

भट्ट को जून में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। उस समय वह जामनगर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात थे। गुजरात कैडर के इस आइपीएस अधिकारी को 2011 में निलंबित कर दिया गया था और सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर अगस्त 2015 में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था।

खुला था फाटक, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ (झज्जर)

▶ सीटों से गिरकर कई यात्री जख्मी, रेलवे की ओर से की जा रही जांच, किससे हुई गलती अभी साफ नहीं

हरियाणा के बहादुरगढ़ स्टेशन के पास सिरसा एक्सप्रेस की क्रॉसिंग के समय फाटक खुला रह गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी तो इससे ट्रेन में ऊपर की सीटों पर सवार कई यात्री नीचे गिरकर जख्मी हो गए। करीब आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रही। पीछे आ रही ट्रेनों को भी दूसरे स्टेशनों पर रोकना पड़ा। घटना के बाद लोको पायलेट और गेटमैन के बीच बहस भी हुई।

बुधवार की सुबह सिरसा एक्सप्रेस दिल्ली की तरफ जा रही थी। करीब साढ़े आठ बजे यह बहादुरगढ़ पहुंचती है, मगर स्टेशन से पहले बराही फाटक खुला था। ट्रेन अंदर आ चुकी थी। फाटक खुला होने के कारण वाहन क्रॉस हो रहे थे। यह देख लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए। इससे ट्रेन क्रॉसिंग के पास आकर रुक गई। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया, मगर इमरजेंसी ब्रेक लगते ही ट्रेन के अंदर ऊपर की सीटों पर सो रहे कई यात्री नीचे आ गिरे। इससे उन्हें हल्की-फुल्की चोट भी लगी। उधर, इस घटना की सूचना कुछ ही मिनट में रेलवे मुख्यालय तक पहुंच गई। ट्रेन को यहां से नौ बजे के बाद रवाना किया गया। वहीं पीछे आ रही जाखल पैसेंजर को करीब 25 मिनट तक आसौदा स्टेशन पर रोका गया।

> इस बारे में रेलवे के उच्चाधिकारी ही स्थिति साफ कर सकते हैं। इस मामले में कुछ भी कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं।
> **-बीएस मीणा, बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन अधीक्षक**

रेलवे कर रहा जांच
बताया जा रहा है कि गेटमैन ने तो फाटक बंद करने के लिए मैसेज न मिलने की बात कही। वहीं लोको पायलेट ने पीछे से सिग्नल मिलने के बाद ही ट्रेन अंदर लाने की बात कही। इधर, स्टेशन मास्टर की तरफ से बताया गया कि जब तक फाटक बंद नहीं होता, तब तक सिग्नल देने का सवाल ही नहीं। लोको पायलट को बिना सिग्नल देखे ट्रेन अंदर लाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसे में मामला उलझ गया कि आखिर इस पूरी घटना के लिए किसकी गलती रही।

एलेक्स को छोड़ने के समझौते का असर क्या कर्मा की सुरक्षा पर पड़ा!

नईदुनिया, रायपुर

▶ झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए सरकार ने बढ़ाए बिंदु

छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी नक्सली हमले की जांच के लिए सरकार ने न्यायिक जांच आयोग के बिंदु तय किए हैं। सरकार ने झीरम घाटी हमले की राजनीतिक साजिश की जांच के लिए नए सिरे से पहल की है। अब न्यायिक जांच आयोग इस बात की पड़ताल करेगा कि सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण और रिहाई में किस तरह के समझौते नक्सलियों के साथ किए गए थे। क्या उनका संबंध कांग्रेस के कद्दावर नेता और बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा की सुरक्षा से था।

यही नहीं, आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि नक्सली किसी बड़े आदमी को बंधक बनाने के बाद उन्हें रिहा करने के बदले क्या अपनी मांग मनवाने का प्रयास करते रहे हैं। कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल के बंधक होने के समय ऐसा नहीं करने का क्या कारण था।

न्यायिक जांच आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो झीरम घाटी हमले में कांग्रेस के बड़े नेताओं की हत्या हुई। उस समय यह बात सामने आई थी कि नक्सलियों ने काफिले को घेरने के बाद महेंद्र कर्मा की खोज की। उनकी खोज के बाद नक्सलियों ने कर्मा को गोली मारी। यही नहीं, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और दिनेश पटेल को नक्सलियों ने पहाड़ी के पीछे बंधक बनाया। कर्मा की मौत के काफी समय बाद नक्सलियों ने पटेल की हत्या की। ऐसे में अब जांच आयोग इसकी पड़ताल करेगा कि पटेल को बंधक बनाने और बाद में हत्या करने के पीछे क्या साजिश थी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में महेंद्र कर्मा को पर्याप्त सुरक्षा दी गई कि नहीं, इसकी भी जांच होगी।

सात सवालों की अब शुरू हुई तलाश : आयोग के सामने सात सवाल रखे गए हैं। इसमें नवंबर 2012 में महेंद्र कर्मा पर हुए हमले के बाद क्या उनकी सुरक्षा की समीक्षा प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप ने किया था। हमले के बाद कर्मा की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग पर किस स्तर पर विचार किया गया। उस पर क्या कार्रवाई की गई। गरियाबंद में जुलाई 2011 में नंदकुमार पटेल के काफिले पर हुए हमले के बाद क्या पटेल और उनके काफिले की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। क्या उन अतिरिक्त सुरक्षा मानकों का पालन झीरम घाटी घटना के दौरान किया गया।

परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा की होगी जांच : आयोग परिवर्तन यात्रा के दौरान उपलब्ध कराई गई सुरक्षा की भी जांच करेगा। 25 मई 2013 को बस्तर जिले में कुल कितना पुलिस बल मौजूद था। क्या परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम की अवधि में बस्तर से पुलिसबल दूसरे जिलों में भेजा गया। यदि भेजा गया, तो किस कारण से और किसके आदेश से। क्या इसके लिए सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई। नक्सलियों की टीसीओसी के दौरान यूनिफाइड कमांग किस तरह अपनी भूमिका निभाती थी। यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष के कर्तव्य क्या थे और क्या यूनिफाइड कमांड के तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने उप कर्तव्यों का उपयुक्त निर्वहन किया।

क्या सुरक्षा के निर्देशों का पालन हुआ?
आयोग सुरक्षा के निर्देशों के पालन की भी जांच करेगा। क्या राज्य में नक्सलियों के द्वारा पूर्व में किए बड़े हमले को ध्यान में रखते हुए नक्सली इलाकों में यात्रा के लिए किसी निर्धारित संख्या में उससे अधिक बल प्रदान करने के कोई दिशा-निर्देश थे। यहां हां तो उनका पालन किया गया। यदि नहीं, तो क्या पूर्व के बड़े हमलों की समीक्षा कर कोई कदम उठाए गए।

माओवादी नेता की उम्रकैद 10 साल की कैद में बदली

जागरण संवाददाता, कोलकाता : माओवादी नेता छत्रधर महतो को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 2009 में हुए बारुदी सुरंग विस्फोट मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को हाई कोर्ट ने कम करते हुए इसे 10 साल जेल में बदल दिया। हाई कोर्ट ने यह फैसला बुधवार को सुनाया। वहीं सुबूतों को अभाव में कोर्ट ने छत्रधर के दो साथियों राजा व प्रसून को बरी कर दिया। साथ ही तीन अन्य साथियों सुख शांति बास्के, शंभू सोरेन और शगुन मुर्मू की उम्रकैद की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया।

2009 में पश्चिम बंगाल में जंगलमहल के काटापहाड़ी इलाके में एक बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के मुख्य आरोपित के रूप में सितंबर 2009 में बीरकांड़ गांव से छत्रधर महतो को गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ शगुन मुर्मू, शंभू सोरेन, सुख शांति बास्के, राजा सरखेल, प्रसून चटर्जी व रंजीत मुर्मू को भी गिरफ्तार किया था। मई 2015 में मेदिनीपुर जिले के सत्र न्यायालय ने छत्रधर महतो समेत छह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसी समय इन लोगों ने हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पाया कि सुबूत पर्याप्त नहीं हैं इसलिए सजा में कमी की जानी चाहिए।

प्रयास

इंदौर के समीप बेटमा के दशहरा मैदान में सेना भर्ती कैंप जैसा नजारा, सैनिक विजय यादव युवाओं को देते हैं सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण

छुट्टियों में सेना के लिए तैयार कर रहे जवानों की नई खेप

उमेश सोलंकी, बेटमा

एक सैनिक जब छुट्टी लेकर घर आता है तो वह आराम करना चाहता है, लेकिन दो माह की छुट्टी पर आए मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप बेटमा के विजय यादव यहां भी अपनी सैन्य दिनचर्या को ही जी रहे हैं। उनका मकसद अपने गांव के युवाओं को काबिल बनाना है और इसीलिए वे उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे हर साल छुट्टियों में आकर युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देते हैं। उनकी एक ही शर्त है-अनुशासन और इसका नतीजा भी सामने है। पिछले सात साल में उनके 50 से अधिक शागिर्द सेना में भर्ती हो चुके हैं।

बेटमा के दशहरा मैदान पर इन दिनों सेना भर्ती कैंप जैसा नजारा है। यहां सुबह छह बजे से ही युवा दौड़, लंबी कूद, बीम आदि करते हैं। ये सभी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं और विजय यादव इन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। जामनगर में तैनात विजय रोजाना सुबह दो घंटे युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं। वे भर्ती के दौरान अधिकारियों से बातचीत करने के लहजे और लिखित परीक्षा के टिप्स भी देते हैं।

चार सौ मीटर का ट्रैक बनवाया : विजय ने प्रशिक्षण के लिए यहां कुछ अस्थायी तैयारियां भी की हैं। उन्होंने चार सौ मीटर दौड़ के लिए एक ट्रैक, जबकि लंबी कूद के लिए दस फ ट लंबा गड्ढा खुदवाया है। रस्सी चढ़ने के साथ दूसरे कई शारीरिक अभ्यास के लिए उन्होंने इंतजाम किए हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में बेटमा सहित आसपास के करीब 70 युवा आ रहे हैं।

2007 से शुरू किया प्रशिक्षण देना | **2012** में पहली बार हुआ प्रशिक्षित युवक का सेना में चयन | **70** युवा वर्तमान में ले रहे प्रशिक्षण | **50** युवा अब तक पा चुके हैं नौकरी

बेटमा में युवाओं को सेना में भर्ती होने के टिप्स देते विजय (सफेद हाफ पेंट में)। नईदुनिया

ट्रेनिंग के समय मिले पुरस्कार
विजय अब तक सेना के साझा युद्धाभ्यासों में चीन और अमेरिका की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर चुके हैं। वे कुपवाड़ा, बारामुला, असम आदि स्थानों पर भी तैनात रह चुके हैं। सेना में उन्हें ट्रेनिंग के दौरान कई बार बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार भी मिला। ट्रेनिंग देने के पीछे विजय का एक ही मकसद है कि वे जिन कारणों से दो बार चूक गए, उसका सामना किसी और को न करना पड़े।

तीसरी बार में हुए सफल
विजय के मुताबिक नियमों की जानकारी के अभाव में वे दो बार सेना भर्ती में चूके। इसके अलावा वे सिर्फ दौड़ते थे। यह पता नहीं था कि सीने का माप भी जरूरी है। उन्होंने इन सबकी तैयारी की और तीसरी बार में सफल हो गए। उन्होंने वर्ष 2007 से युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया, जबकि वर्ष 2012 में पहली बार उनके द्वारा प्रशिक्षित एक युवक का सेना में चयन हुआ। उनका अभियान धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

अफीम तस्करी में सेना के जवान सहित पांच बरेली से गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, रांची

▶ झारखंड पुलिस की सूचना पर किए गए गिरफ्तार, दो चतरा के रहनेवाले

झारखंड पुलिस की सूचना पर क्राइम ब्रांच बरेली की टीम ने बरेली रेलवे स्टेशन के पास अफीम के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में जम्मू-कश्मीर में पदस्थापित भारतीय सेना का जवान भी है, जो झारखंड के तस्करों के साथ मिलकर अफीम की तस्करी करता था। गिरफ्तार तस्करों में दो आरोपित झारखंड के चतरा जिले के हैं। तस्करों के पास से डेढ़ किलोग्राम अफीम, 90 हजार रुपये नकद और ओमनी वैन की बरामदगी की गई है। इनके विरुद्ध बरेली के कोतवाली थाने में एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई और सभी आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

झारखंड पुलिस ने यूपी के बरेली क्राइम ब्रांच को सूचना दी कि झारखंड से अफीम तस्कर अफीम लेकर बरेली के बहेड़ी की ओर जाने वाले हैं। इसी सूचना पर मंगलवार की शाम बरेली क्राइम ब्रांच ने बरेली रेलवे स्टेशन के पास चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान ही मारुति वैन के साथ पांचों पकड़े गए। गिरफ्तार भारतीय सेना के जवान ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में बताया कि दो दिनों की छुट्टी थी। इसी दरम्यान उसने अपने भाई के साले जयपाल के साथ मिलकर झारखंड से अफीम धनंजय व उदय से मंगवाई थी। इसके एवज में उसे 90 हजार रुपये देने थे। उस अफीम को बहेड़ी व रूद्रपुर में ऊंचे दाम पर बेचने की योजना थी।

जिनकी हुई है गिरफ्तारी
सुरेंद्र (भारतीय सेना का जवान, जम्मू-कश्मीर में पदस्थापित) : पिंडारी, थाना बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश।
शेर सिंह : रतनगंज, थाना बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश।
भंवरचंद्र गंगवार : ग्वारी, थाना बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश।
धनंजय कुमार : बाघाकोला, गजवा, प्रतापपुर, चतरा, झारखंड।
उदय गंझू : जगन्नाथपुर, कुंदा, चतरा, झारखंड।

Downloaded from:
www.iascgl.com

दैनिक जागरण

स्वतंत्रता के समान कोई और सुख नहीं

राष्ट्रीय संकल्प का वक्त

देश की एकता-अखंडता को मजबूत करने वाले ऐतिहासिक कदम के रूप में अनुच्छेद-370 की समाप्ति के बाद आजादी के जश्न का आकर्षण और उत्साह बढ़ जाना स्वाभाविक है। ऐसे फैसले देशवासियों को एकजुट करने के साथ उनमें अपने राष्ट्र के प्रति गौरव, समर्पण और प्रेम को बढ़ाने वाले होते हैं। इस परिदृश्य में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रति लोगों की रुचि और उत्सुकता बढ़ गई है। कई बड़े निर्णयों के साथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कर मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नए भारत के निर्माण के अपने संकल्प के प्रति समर्पित है और उसकी दिशा सही है। मोदी सरकार के साथ एक सकारात्मक बात यह है कि उसने अपने पहले कार्यकाल में सुधार और परिवर्तन की जमीन तैयार कर ली थी। सुधारों का सिलसिला तेज कर अब इसे एक नया आयाम देने का वक्त है। एक बड़े बहुमत से शासन में आई सरकार अपने मजबूत इरादों के साथ ऐसा कर सकती है।

स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्र को अपने भावी पथ पर दृष्टि डालने का अवसर देता है। यह अवसर हम सबको यह स्मरण भी कराता है कि भारत सरीखे देश का वांछित कायाकल्प लोगों के सहयोग से ही हो सकता है। यह आवश्यक है कि आज जब भारत अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब देश के सभी लोग अपने हिस्से की जिम्मेदारी का न केवल अहसास करें, बल्कि निर्वाह भी करें। यह सही समय है जब लोग अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी सचेत और सक्रिय हों। उनमें छोटे-बड़े नियमों के पालन का अनुशासन और परस्पर सद्भावना बढ़े। वे राष्ट्र को कुछ देने के भाव से लैस हों। इस तथ्य को समझें कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है। स्वच्छता जैसे अभियान लोगों की सक्रियता से ही सफल होंगे। ये कोई बड़े काम नहीं हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा अपेक्षा यदि किसी से है तो वह देश के युवाओं से है। वे न केवल खुद को और लोगों को दिशा देने का काम कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्रीय भावना को बल देने में भी सहायक बन सकते हैं। निःसंदेह उन्हें अपने बेहतर भविष्य की चिंता करनी होगी, लेकिन उनकी चिंताओं का सही तरह से समाधान तभी होगा जब राष्ट्र का भविष्य भी निखरता हुआ दिखाई देगा। आज आवश्यकता इसकी है कि हम यह समझें कि एक नागरिक के तौर पर राष्ट्र उत्थान में हर किसी का योगदान होता है। दुनिया के जिन भी देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में मिसाल कायम की है वे ऐसा तभी कर सके हैं जब वहां के लोगों ने राष्ट्रीय संकल्प को स्वयं के संकल्प के रूप में अंगीकार किया है।

कांगड़ा घाटी रेल

पठानकोट-जोगेंद्रनगर रेललाइन करीब 90 साल पूरी कर चुकी है। अंग्रेजी शासन में बनी इस रेललाइन का आजादी के बाद एक इंच भी विस्तार नहीं हुआ है। अंग्रेजों ने बिजली परियोजना के निर्माण के लिए यहां पर रेलवे लाइन बिछाई थी, लेकिन अब यह कई गांवों की जनता के लिए लाइफलाइन है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र भी है। इस ट्रैक पर चलने वाली रेलगाड़ी में अन्य राज्यों के हजारों श्रद्धालु हर साल देवी दर्शन के लिए भी आते हैं। रेलगाड़ी में हमेशा भीड़ रहती है। वर्षों से इसे ब्रॉडगेज करने की मांग भी की जाती रही है। इस रेलवे ट्रैक पर करीब 14 रेलगाड़ियां चलती हैं, लेकिन बरसात में कई जगह भूस्खलन के कारण ट्रैक बाधित हो जाता है। इस कारण कई रेलगाड़ियों का परिचालन बंद भी कर दिया जाता है। बरसात में गुलेर से पठानकोट एवं कोपरलाहड़ से जोगेंद्रनगर के बीच ही कुछ रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं। इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई बार शिकायत रही है कि यहां पर चलने वाली रेलगाड़ियों के इंजन काफी पुराने हैं जो कई बार हांफ जाते हैं। इनकी गति भी संतोषजनक नहीं है। यह राहत की बात है कि करीब 35 साल बाद इस ट्रैक पर नए इंजन आ रहे हैं। वैसे भी इंजन की लाइफ 36 वर्ष बताई जाती है। पांच इंजन 1981 में निर्मित हुए हैं। नए इंजनों को मुंबई की परेल वर्कशॉप में अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेड़े में शामिल होने वाले 12 इंजनों में से चार इंजन अगले महीने पठानकोट वर्कशॉप पहुंच जाएंगे। नए इंजन आने से लोगों को सफर में राहत मिलने की उम्मीद है। यह सही है कि करीब 14 साल पहले बेड़े में दो इंजन शामिल किए गए थे, लेकिन ये नए नहीं थे। बार-बार इंजन खराब होने से रेलवे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था वहीं यात्रियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन का यह फैसला सराहनीय है। इससे जहां सफर में सुविधा मिलेगी वहीं रेलवे बोर्ड को नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। इस रेलवे लाइन पर निर्भर लोगों की मांग के अनुसार इसका विस्तार किया जाना भी जरूरी है। यदि यहां से ब्रॉडगेज रेललाइन का निर्माण होता है तो पर्यटन को भी पंख लगेंगे, साथ ही सामरिक दृष्टि से भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा।

कांगड़ा घाटी रेल को लंबे समय बाद नए इंजन मिलने से ट्रेनों के संचालन को मजबूती मिलेगी और यात्रियों की दिक्कतें कम होंगी

तिरंगा और आजादी का उत्सव

गोपालकृष्ण गांधी

हमारा राष्ट्रीय ध्वज मात्र एक कपड़े का थान नहीं। वह हमारे देश की जान है, उसमें हमारी आत्मा रहती है। हम उसके आशीर्वाद के योग्य बनें

पंद्रह अगस्त हमारे लिए अद्भुत मायने रखता है। उसके मुकाबले का कोई और दिन नहीं। जब इस दिन सुबह लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री आते हैं और जिंदादिली से हमारा प्रिय तिरंगा लहराते हैं, तब जो गर्व उभरता है, उसकी तुलना किसी और अनुभव से नहीं हो सकती। हर पंद्रह अगस्त, हम सभी का होते हुए, एक खास मायने में हमारे प्रधानमंत्री का दिन होता है। इस दिन पर हमारे प्रधानमंत्री की छाप होती है, उनके लाल किले के भाषण की मुहर लगी होती है। तो इस शुभ दिन के अवसर पर सर्वप्रथम हमारा अभिनंदन, हमारी मुबारकबाद हमारे प्रधानमंत्री को जाती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवसर पर अपनी शुभेच्छा देता हूं।

हमारे वीरों और वीरांगनाओं के साथ, पांच लोगों की याद मुझे हर पंद्रह अगस्त को आती है। इत्तेफाक से, पांचों के पांचों बंगाल से हैं। इनमें सबसे पहले आती है ऋषि बंकिम की याद। उनका वंदे मातरम जो है, वह एक गान नहीं, एक आह्वान है। वह एक गीत नहीं, एक गाथा है। उसके हर शब्द में, हर वाक्य में, उसमें निहित हर छवि में हमारी, हमारी भारत माता की अभिलाषा भरी है, आकांक्षा भरी है। वंदे मातरम में भारत की महानता भरी है।

फिर याद आती है गुरुदेव रबिंद्रनाथ ठाकुर की। उनके जन-गण-मन की खूबी भी क्या खूबी है! वैसे हम उसे गाते हुए कविगुरु की प्राथमिकताएं भूल जाते हैं। जरा गौर करें-'जन' यानी लोग, हम भारत के लोग। यह शब्द सबसे पहले आता है उसमें। हम उसमें सबसे पहले आते हैं, जैसे संविधान में आते हैं-'हम भारत के लोग'। फिर दूसरा शब्द है 'गण'। 'गण' यानी, फिर से, लोग। 'जन' और 'गण' में कोई अंतर? नहीं भी है और है भी। 'जन' व्यक्ति का सूचक है, 'गण' व्यक्तियों के समूह का। 'जन' में आप आते हैं, मैं आता हूं। 'गण' में हम सब आते हैं-एक साथ। और फिर 'मन'। क्या बात है यहां! कविगुरु संकेत कर रहे हैं हमारे सबके, व्यक्तिगत और सामूहिक मन का, हमारे मानस का, हमारी सोचों का, हमारे अंतस का। क्या बात है! हम सोचने वाले, सुख-दुख अनुभव करने वाले लोग हैं। हां, रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में उलझे हुए हैं जरूर, लेकिन हम इतने खुदगर्ज नहीं कि उससे उठकर सोच न सकें।

तीसरा नाम जो याद आता है वह है नेताजी सुभाषचंद्र बोस का। नेताजी ने ही सर्वप्रथम लाल किले पर लहराते तिरंगे की परिकल्पना की थी। 'दिल्ली चलो' का जो आह्वान था उनका, वह लाल किले से मतलब रखता था। और उसी को केंद्रबिंदु बनाए आजाद हिंद फौज को उसकी ओर वह लिए आ रहे थे। क्या गति थी उनमें, क्या ऊर्जा! क्या देशप्रेम, क्या समर्पण! कदम-कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जो कौम से मिला तुझे वो कौम पर लुटाए जा...। 'लुटाए जा' का अनुवाद अंग्रेजी में तो समझिए, सर्वथा नामुमकिन है। खुद को, अपनी जिंदगी को, नेताजी ने हिंद की आजादी के लिए लुटा दिया। काश वह पंद्रह अगस्त, 1947 के दिन हमारे साथ होते! पंडित नेहरू ने लाल किले पर कहा कि हमारा झंडा नेताजी ने विदेश में कई जगहों में हमारे राष्ट्र को याद करते हुए लहराया है और आज नेताजी को यहां होना चाहिए था, यह दिन उनका है...। तकदीर के तरीकों को तकदीर ही जाने! आज बहुत लोग यह भूल जाते हैं कि बापू को 'राष्ट्रपिता' की संज्ञा और किसी ने नहीं, नेताजी ने सिंगापुर से प्रसारित अपने उद्घोष में अंग्रेजी में दी थी-'फादर ऑफ अवर नेशन...।'

चौथा नाम याद आता है द्विजेंद्रलाल रॉय का। उनका गान 'धनो-धान्य पुष्प भरा' वंदे मातरम का पूरक है। उसमें भारत की उर्वरा भूमि का उल्लेख तो है ही, साथ में उस भूमि के भविष्य, उसके एजेंडे के लिए एक गहरी सोच, एक चिंता का अहसास भी है। वह गान सूखी आंखों के साथ न कभी गाया जाता है, न सुना।

पांचवां नाम जो है, उसको हाथ जोड़कर, नमस्कार और प्रणाम की मुद्रा में लिया जा सकता है। वह नाम है श्री अरविंद। बहुत लोग यह जानते नहीं हैं कि श्री अरविंद का जन्म 1872 में हुआ था-पंद्रह अगस्त को। क्या सुखद संयोग! स्वतंत्रता दिवस के दिन, अपने जन्मदिन पर, श्री अरविंद अपने निवास पुदुचेरी में थे। तिरुचिरापल्ली के ऑल इंडिया रेडियो ने चौदह अगस्त को उनका लिखित संदेश प्रसारित किया। उस संदेश जैसा संदेश प्रायः सुनने को नहीं आता। उसमें आशीर्वाद है, चिंताएं भी। साधुवाद है, चेतावनियां भी। मूल अंग्रेजी में है वह संदेश, तो उसका एक वाक्य अंग्रेजी में ही दिए देता हूं। भारत के दलितों के बारे में वह सहर्ष कहते हैं कि हमारी संविधान सभा ने एक 'वाइजली ड्रास्टिक पॉलिसी अपनाई है, जिससे दलितों की समस्याओं का अंत हो, उन्हें सुकून मिले।' श्री अरविंद का संकेत आरक्षण नीति से है। श्री अरविंद उस संदेश में भारत-पाकिस्तान के विभाजन के बारे में भी बहुत कुछ गंभीरता से कहते हैं।

पंद्रह अगस्त के उपलक्ष्य में लोकमान्य तिलक की भी याद आती है। उन्होंने कहा-'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा! चिरस्मरणीय है यह वाक्य!

अवधेश राजपूत

और यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत और भारत माता हमारी पताका में निहित हैं। वे हम सबकी हैं। उनसे हमें आत्मबल मिलता है। उनसे कोई किसी भारतवासी, किसी हमवतनी को डराने का हक नहीं रखता है।

इस रोज शहीद भगत सिंह की याद आती है। सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद की भी। उनकी हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक फौज नेताजी की आजाद हिंद फौज की अग्रणी थी। वीर सावरकर का फ्रांसीसी समुद्रतट में अंग्रेजी सिपाहियों के जाल में न फंसने के लिए स्टीमर से फिसलकर भाग निकलना और फिर तैरते, भागते हुए पकड़े जाना, यह उद्यम हमारे स्वाधीनता संग्राम की श्रृंखला की एक सुनहरी कड़ी है। उनकी विचारधारा से गंभीर मतभेद रखते हुए भी गांधीजी ने उनके इस उद्यम को उनकी राष्ट्रीयता का परिचायक माना और उसका उल्लेख उन्होंने बुलंद शब्दों में किया।

मैडम भीकाजी कामा महान पारसी महिला थीं। उन्होंने ही हमारे तिरंगे की डिजाइन के एक आकर्षक प्रारूप को श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ बनाया और उसे 'स्वतंत्र भारत का झंडा' नाम देते हुए 2 अगस्त, 1907 के दिन जर्मनी में फहराया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय बंगाली वीरांगना मतंगिनी हाजरा ने हमारे तिरंगे को उठाकर आंदोलन किया। गोलियां चलीं, वह भी चलती रहीं। गोलियां रुकी नहीं, वह भी रुकी नहीं। गोली उन्हें लगी। वह गिरीं, लेकिन झंडा उनके हाथ में से हिला नहीं, वहीं का वहीं टिका रहा। मतंगिनी अमर हैं।

हमारा राष्ट्रीय ध्वज कपड़े का थान नहीं। वह हमारे देश की जान है, उसमें हमारी आत्मा रहती है। उसको लहराने वाले, उसको उठाकर चलने वाले हम, उसके बालक हैं। हम उसके आशीर्वाद के योग्य बनें।

(पूर्व राजनयिक-राज्यपाल लेखक वर्तमान में अध्यापक हैं)

response@jagran.com

स्वतंत्रता दिवस पर अनमोल उपहार

डॉ. एके वर्मा

मोदी सरकार ने कश्मीर एवं शेष भारत के बीच अवरोध हटाकर इस स्वतंत्रता दिवस को और खास बना दिया है

देश आज 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बार यह अवसर बेहद खास है, क्योंकि 'एकता और अखंडता' के संवैधानिक संकल्प को प्राप्त करने के लिए देश ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। गत 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच विभाजक-रेखा खींचने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। तमाम विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया। फिर भी कुछ दलों, नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसे 'लोकतंत्र का सबसे काला दिन' या 'लोकतंत्र की हत्या' करार दिया। कश्मीरी नेताओं को ऐसा लगना लाजिमी था, क्योंकि इससे उनकी तो राजनीतिक जमीन ही खिसक गई। उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्रावधान एक झटके में खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन कर लद्दाख व जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएंगे। कुछ ने इसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रतिपादित 'कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत' वाली अवधारणा के विरुद्ध बताया। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि प्रत्येक मुद्दे, निर्णय और तरीके पर सहमति-असहमति बनी रहे और असहमतियों का भी उचित सम्मान किया जाए।

बहरहाल इस कदम से देश को कश्मीर और कश्मीरियों से जोड़ने की अद्भुत पहल हुई है। अनुच्छेद 370 से कश्मीरियों की आजादी अधूरी थी। उनका एक तबका न तो देश से पूरी तरह जुड़ पा रहा था, न ही पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा खत्म कर पा रहा था। शेख अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद सईद के परिवारों ने राज्य की जनता के असमंजस को भांपकर उसे भावनात्मक रूप से राजनीतिक बंधक सा बनाकर जम्हूरियत का नाम दे दिया था। इसीलिए दोनों परिवारों के नेताओं ने अनुच्छेद 370 और 35-ए को हटाए जाने पर देश को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। पिछले 70 वर्षों से लाखों कश्मीरी 'स्थायी निवासी' न होने के कारण विधानसभा और पंचायत चुनावों में न तो वोट डाल पा रहे थे और न ही प्रत्याशी बन पा रहे थे। किसी लोकतंत्र में स्वतंत्रता के प्रति इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? लद्दाख की बौद्ध-बहुल जनसंख्या की उपेक्षा और घाटी के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा न देना कैसे सेक्युलरिज्म से मेल खाता है?

और क्या है कश्मीरियत? कुछ बुद्धिजीवी और नेता कश्मीरियत को 'इस्लामियत' से भ्रमित करते हैं। वे भारतीय समाज के स्वरूप को तो 'मेल्टिंग-पॉट' की जगह 'सलाद-पॉट' के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन स्वयं जम्मू-कश्मीर में 'सलाद-पॉट' की उपेक्षा पर मूक-दर्शक बने रहते थे। 'मेल्टिंग-पॉट' सामाजिक-समरूपता का यूरोपीय सिद्धांत है जो इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे मुल्कों में दिखता है। वहीं 'सलाद-पॉट' विविधता में एकता का सिद्धांत है जिसे भारत, कनाडा और बेल्जियम आदि देशों में देखा जा सकता है। 'सलाद-पॉट' के हिमायती लोगों ने कभी जम्मू-कश्मीर के दलितों, कश्मीरी पंडितों और लद्दाखी बौद्धों का पक्ष लिया होता तो आज उनकी बात में कुछ वजन होता, लेकिन बीते कुछ वर्षों में जिस कश्मीरियत को अलगाववाद और आतंकवाद का पर्याय बना दिया गया, जनता उसे कैसे स्वीकार करे?

'इंसानियत' एक द्विपक्षीय भावना है। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की जनता कश्मीर के प्रति इंसानियत का प्रदर्शन करती रहे और बदले में उसे हिंसा, अपमान, जवानों की शहादत और पाकिस्तान के प्रति निष्ठा देखने को मिले। क्या यही इंसानियत है कि अपनी सेना के जवानों को हम पत्थर मारें? क्या यही इंसानियत है कि असंख्य निरीह लोगों की हत्या करने वाले पाक-प्रायोजित आतंकियों को शरण दें? देश ने कश्मीर के साथ हमेशा इंसानियत का व्यवहार किया, लेकिन बदले में क्या मिला? आतंक और अलगाव की बलवती होती प्रवृत्तियां? मुट्ठी भर लोगों की स्थानीय राजनीति पर पकड़ होने के कारण उनके गलत कार्यों का खामियाजा पूरे राज्य के लोगों को भुगतना पड़ता है। कोई नहीं चाहता कि वहां सेना हमेशा बनी रहे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो जम्मू-कश्मीर की जनता को ही उठानी पड़ेगी। कश्मीर सीमावर्ती राज्य है जहां हमारी सरहद दो शत्रु देशों से लगती है तो फिर अन्य राज्यों की अपेक्षा वहां सेना की मौजूदगी तो रहेगी। निःसंदेह जम्मू-कश्मीर के बहुसंख्यक लोग और भारत की जनता आज भी 'कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत' के लिए प्रतिबद्ध हैं। मगर इसके साथ ही भारत की प्रतिरक्षा, एकता व अखंडता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और समेकित विकास सुनिश्चित करना कश्मीरियों सहित देश के सभी नागरिकों और केंद्र एवं जम्मू-कश्मीर सरकारों का संवैधानिक दायित्व भी है।

5 अगस्त, 2019 का दिन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में इसलिए भी लिखा जाएगा, क्योंकि अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता का नया युग देखने को मिलेगा। अभी वहां 'आतंकवाद की इंडस्ट्री' ही थी, लेकिन अब देसी-विदेशी निवेशक वहां कई उद्योग लगा सकेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। बाहर से योग्य पेशेवर और उद्यमी बिना भेदभाव के आ सकेंगे, क्योंकि अब मौलिक अधिकारों तथा सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु 'स्थायी नागरिकता' की बंदिश खत्म हो गई है।

अभी कश्मीर को भारत से विलग करने वाले संवैधानिक-कानूनी प्रावधानों को खत्म किया गया है, पर राज्य की आबादी के एक हिस्से के दिलों में पिछले 70 वर्षों में जो दूरियां आई हैं, उन्हें खत्म होने में वक्त लगेगा। कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य होने और नजरबंद नेताओं की रिहाई के बाद कैसे हालात होंगे? अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र से इस मुद्दे पर अपेक्षित समर्थन न मिलने के बावजूद पाकिस्तान राज्य में आगे किस तरह उपद्रवियों को भड़काएगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं किया है, बल्कि उसे 'भस्मासुर' बना उसी के द्वारा उसके प्रभाव को भस्म कर दिया है। अगस्त 1947 में एक स्वतंत्रता की कीमत देश को बंटवारे के रूप में चुकानी पड़ी थी। ऐसे में सभी देशवासी ईश्वर से प्रार्थना करें कि अगस्त 2019 में प्राप्त इस नई स्वतंत्रता की कीमत हमें दिलों के बंटवारे के रूप में न चुकानी पड़े।

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसायटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आजादी यानी जिम्मेदारी

आजादी की चाह किसे नहीं होती? नदी, वृक्ष, आकाश, पंछी अपने आजाद होने का उत्सव मनाते हैं। मुक्त प्रवाह में कल-कल के स्वर उत्पन्न कर बहती नदी अपने तेज प्रवाह के साथ अपनी गतिशीलता की आजादी को महसूस करती है। बीज के रूप में अंकुरित पौधा मिट्टी, खाद, पानी, वायु के संपर्क से वृक्ष बन हवा के वेग में झूमता हुआ आजादी का अनुभव प्राप्त करता है। पिंजरे की जालियों में से आसमान में कलरव करते पंछियों के झुंड को देख रहा पंछी जब स्वयं पिंजरे से मुक्त होता है तब अपनी आजादी की एक लंबी उड़ान भर आसमान में अपनी आजादी का प्रमाण देता है। बादल जल वर्षा कर अपनी आजादी के आनंद में खो जाते हैं। धरती हरी चादर ओढ़े सुंदर नजर आने लगती है। प्रकृति तो अपनी आजादी का उत्सव अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर मनाती है, किंतु हम मनुष्य अपनी आजादी को किस रूप में स्वीकार करते हैं?

आजादी सोशल मीडिया पर बधाई के संदेश डालने का नाम नहीं है, न ही देशभक्ति के गीतों को अपने फोन की धुन बनाने का प्रमाण है। आजादी वह है जो नागरिकों को कर्तव्यों का बोध करा सके। उनके मन में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना का विकास कर सके। एक-दूसरे के प्रति जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की संकीर्णता जैसे मलिन भावों से मुक्त कर सके। यदि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध के भाव नहीं हैं तो ऐसी आजादी औचित्यहीन है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों की आजादी को मौलिक अधिकारों के रूप में प्रमाणित करता है। किंतु महात्मा गांधी कहते थे कि कर्तव्यों की पूर्ति पर अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वे प्रकृति की भांति अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हों। कमियों पर विचार रखना एवं संविधान की गरिमा में बात कहना आजादी है। आजादी वह संकल्पना है जो हमें विचार एवं व्यवहार से स्वायत्त बने रहने की प्रेरणा भी देती है। अपनी बुद्धि, विवेक के आधार पर समर्थन और विरोध की शक्ति प्रदान करती है।

सौरभ जैन

बहनों की रक्षा के संकल्प का पर्व

सुधीर कुमार

रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन को एक-दूजे के सम्मान एवं सुरक्षा में खड़े रहने की शिक्षा देता है

भारत विविध धर्म, भाषा, संस्कृतियों का सुंदर गुलदस्ता है। विविधता में एकता इस देश की सबसे बड़ी खासियत रही है। समय-समय पर दस्तक देने वाले पर्व-त्योहार क्षीण होते पारिवारिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये पर्व-त्योहार मानव जीवन में विभिन्न कारणों से बनने वाली नीरसता के बादल को पीछे छोड़ने तथा खुशियों की वर्षा कराने में बड़ी सहभागिता निभाते हैं। इसके साथ ही सामाजिक संतुलन स्थापित करने तथा लोगों में सामाजिकता एवं अपनापन का भाव जगाने में पर्व-त्योहारों का बड़ा महत्व रहा है।

आज भाई-बहन के निश्छल प्रेम पर आधारित रक्षाबंधन का पावन पर्व है। बहन के हाथों से भाई की कलाई पर बंधने वाली राखी के भीतर एक-दूसरे के प्रति प्रेम, सुरक्षा एवं समर्पण के उच्च आदर्श एवं संकल्प समाहित होते हैं। यह महज धागा नहीं, अपितु विश्वास एवं सुरक्षा की डोर होती है। भाई-बहन का प्यार अटूट होता है। बचपन में साथ खेलते-खेलते दोनों कब बड़े हो जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन एक-दूसरे के प्रति प्यार दिनोंदिन बढ़ता चला जाता है। भाई-बहन का रिश्ता चिरकाल तक स्थाई रहता है। भाई की सफलता पर सबसे ज्यादा खुशी बहन को होती है तो बहन की घर से विदाई के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ भाई ही महसूस करता है। यह त्योहार भाई-बहन को प्रत्येक वर्ष एक-दूसरे के पास लाकर खुशियों की सौगात देने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।

रक्षाबंधन एक उत्सव है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों से कहीं अधिक उत्साहित नजर आती हैं। ऐसे शुभ अवसर पर भाई भी राखी बंधवाने के बाद अपनी बहनों को उपहार देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। विभिन्न कारणों से जब भाई ऐसे आयोजन में शरीक न हो पाने की विवशता व्यक्त करते हैं तो बहनें डाक द्वारा उनको राखी के साथ अपना प्यार भेज देती हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के जरिये भी राखी भेजने का चलन बढ़ गया है। देश की रक्षा को प्रतिबद्ध सैनिक जो इस अवसर पर भी अपने घर नहीं आ पाते, उन्हें भी बहनें राखी भेजने से नहीं चुकतीं।

आज महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है, इसलिए कुछ महिलाएं इस दिन अनाथाश्रम, कारागार या मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को राखी बांधती हैं। यह सभ्य समाज की बड़ी निशानी है। रक्षाबंधन के अवसर पर पेड़-पौधों को भी कच्चा धागा बांधकर उसकी रक्षा करने के संकल्प का रिवाज भारतीय समाज के अनेक हिस्सों में प्रचलित है। निश्चय ही यह कदम प्रकृति-संरक्षण की दिशा में अनूठा प्रयास है। रक्षाबंधन एक धर्मनिरपेक्ष पर्व है। धर्म कोई भी हो, रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन को एक-दूजे के सम्मान एवं सुरक्षा में खड़े रहने की शिक्षा ही देता है। अतः इस पावन अवसर पर हम सभी बहनों की सुरक्षा एवं सम्मान का संकल्प ले सकते हैं। यही इस पर्व का मूल है और इसकी सार्थकता भी इसी में निहित है।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

कितने खरे थे नेहरू के कदम?

अश्विनी कुमार का लेख 'संवैधानिक कसौटी पर कितना खरा दांव' पढ़ा। मेरा प्रश्न है कि 1954 में जो आदेश पंडित नेहरू ने राष्ट्रपति द्वारा कश्मीर पर जारी कराया था, जिसने भयंकर भेदभावकारी अनुच्छेद 35-ए को जन्म दिया, वह कितना संवैधानिक था? संसद छोड़िए उसे तो कैबिनेट की भी स्वीकृति नहीं थी। केवल पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच का वह निर्णय था। उसके पहले, कश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में ले जाना, जिस पर अंतरिम संसद अथवा कैबिनेट तक में कोई चर्चा नहीं हुई, वह किस तरह संविधान-सम्मत था? इस पर तो जम्मू-कश्मीर के महाराज हरिसिंह इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने विलय समाप्त करने तक की धमकी दे डाली थी। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की बात पंडित नेहरू कैसे कर बैठे? भारत स्वाधीनता अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, न ही कैबिनेट या अंतरिम संसद से उसकी मंजूरी ली गई थी। वस्तुतः नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी ने कश्मीर संबंधी तमाम निर्णय संविधान को ताक पर रखकर लिए। लेखक इन बातों का जवाब देंगे क्या? फिर उनका यह कहना भी अटपटा है कि राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों की सहमति क्यों नहीं ली गई। जब विधानसभा भंग है तो कौन है प्रतिनिधि? कश्मीर और भारतीय, दोनों संविधानों के अनुसार अब राज्यपाल ही वहां के प्रतिनिधि हैं। क्या तेलंगाना बनाते समय कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की सहमति ली थी? इसी तरह झारखंड निर्माण में बिहार की सहमति कहां थी? अनुच्छेद तीन में साफ लिखा है कि राज्य के बिना सहमति के राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है और होता रहा है।

अजय मित्तल, मेरठ

मेलबाक्स

कमजोर बुनियादी ढांचा

देश का आज आधा भाग बाढ़ की चपेट में है। असम व बिहार के बाद केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। देश में बाढ़ से लगभग 200 से अधिक लोग इसी साल मारे जा चुके हैं तथा लगभग करोड़ की धनराशि इस बाढ़ में बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ के कारण लाखों घर ढह गए हैं। बाढ़ पहले गांव तक सीमित रहती थी, लेकिन अब इसका क्षेत्र शहरी भी हो गया है। बाढ़ के लिए सिर्फ ज्यादा बारिश को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए सरकारी योजनाओं में भी खामी है। हम अपने देश में योजनाओं एवं बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की बात नहीं करते, बल्कि हम बाढ़ से प्रभावित लोगों पर अधिक खर्च करते हैं। अगर हम बुनियादी ढांचे को ही मजबूत कर लें तो बाढ़ आने की संभावना काफी कम हो जाएगी जिससे बाढ़ के बाद होने वाले खर्चों में भी कमी आएगी।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

अनावश्यक याचिका

सर्वोच्च न्यायालय ने कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करके सराहनीय कार्य किया है। साथ ही याचिकाकर्ता को दो टूक जवाब दिया है कि अभी हालात संवेदनशील हैं और सरकार को समय चाहिए। कैसी विडंबना है कि देश में कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कोर्ट में अनावश्यक याचिका दायर कर कोर्ट का समय तो नष्ट करते ही हैं, साथ ही यह भी नहीं समझते कि इससे देश के बाहर गलत संदेश जाएगा। वर्तमान समय में सभी राजनीतिक दलों, नेताओं, बुद्धिजीवियों को चाहिए कि सरकार के देशहित में लिए गए निर्णय का समर्थन कर एकता का परिचय दें।

विनोद चतुर्वेदी, दिल्ली

सही निर्णय

लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे पर निरंतर अड़े रहने से काफी गहमा गहमी रही और अंत में सोनिया गांधी को फिर से पार्टी की बागडोर संभालनी पड़ी। यह निर्णय सही भी है, क्योंकि बड़े लोगों के पास अच्छा ज्ञान और अनुभव होता है। लगता है पार्टी के अधिकांश वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को चुनने के पक्ष में होंगे। कांग्रेस पार्टी को अब नए सिरे से नए मुद्दों के साथ आगे बढ़ना होगा। भाजपा की राष्ट्रवाद की नीति अपनी जगह सही है। इसका विरोध करने से पार्टी को नुकसान ही होगा, इसलिए पार्टी को सही नीति से ही आगे बढ़ना होगा।

वेद मामूरपुर, नरेला

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

1975 में 19 अप्रैल को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण किया था।

आजकल

राष्ट्र निर्माण की अहम जिम्मेदारी

गिरीश्वर मिश्र
पूर्व कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

हमें इस बात को अच्छी तरह समझना होगा कि देश सिर्फ भूगोल नहीं है, और न ही यह केवल एक जनसंख्या है। देश एक मानसिक चेतना का नाम है। राष्ट्र एक ऐसी चीज है जो हमारी कल्पना में रहता हुआ भी हमारे खून में दौड़ता रहता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के पवित्र और जीवनदायी भाव को ध्यान में लाया जाए और अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक आचरण में उसके साथ संगति को प्रमुखता दी जाए

'स्वयंप्रभा' और 'समुज्वला' स्वतंत्रता की पुकार के साथ पिछली पीढ़ी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आत्मोत्सर्ग किया और इस पुकार में सुर मिलाते हुए बचपन में हम सब भी प्रभातफेरी लगाते थे। पहले अपना देश परतंत्र था, अंग्रेजों की गुलामी से छूट कर जब देश अपना हुआ तो उसके बनाने की जिम्मेदारी भी देशवासियों के कंधों पर आई। बड़े भरोसे के साथ जनता ने अपने जिन नुमाइंदों को राज-सत्ता सौंपी और जो राह उन्होंने पकड़ी उसकी कथा किसी से छिपी नहीं है। उस राह पर चलते हुए हमने राष्ट्रीय जीवन में कई पड़ाव और मुकाम पार किए। साम्राज्यवादी शोषक अंग्रेजी राज से मुक्ति पाने के बाद सात दशक की अवधि में अंदर बाहर की उलझनों से उलझते, संभलते देश ने कई कामयाबियां हासिल कीं। शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आशातीत विस्तार हुआ। साथ ही लोकतंत्र में वैचारिक विविधता को रखने और परखने की कोशिशें होती रहीं। पश्चिम बंगाल और केरल में साम्यवादी सरकारों का लंबे समय तक निर्बाध चलना इसका प्रमाण है, पर धीरे-धीरे जनता का उससे मोहभंग हुआ और परिणाम है कि साम्यवादी विचार हाशिये पर चला गया। कांग्रेस सरकार का रुझान समाजवाद की ओर था और लंबे समय तक उस मॉडल पर हम चलते रहे। समानता और सामाजिक न्याय जैसे सरोकारों तथा जन आकांक्षाओं को लेकर आंदोलन भी हुए। अतिवादी, नक्सलवादी और माओवादी तथा ऐसी ही कुछ अन्य गतिविधियों ने मुख्य धारा के प्रतिकार की कोशिशें भी कीं। इन सबके बीच देश या राष्ट्र की सोच की तुलना में अंतरराष्ट्रीयता की ओर हम कुछ ज्यादा ही आकृष्ट होते गए। यूरोप-अमेरिका के तर्ज पर विकास को हमने एक मात्र विकल्प मान लिया। हमारी विश्वयारी की कोशिशों में उलझाव भी आए और वह ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। दूसरी ओर हमारी अपनी समस्याओं की ओर ध्यान कम होता गया। बहुत सी समस्याओं से हम आंखें मूंदे रहे, मानों समय स्वतः ही उसका हल निकाल लेगा। ऐसे मौके भी आए जब सामाजिक सहिष्णुता को आघात पहुंचा। इस अवधि के बीच विभिन्न मोर्चों पर हुए हानि-लाभ का इतिहास टटोलते हुए संतोष होने के साथ-साथ कुछ घाव भी हरे होने लगते हैं और फिर हम एक-दूसरे पर दोष मढ़ने की मुद्रा में आ जाते हैं।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जिन परिस्थितियों में आधुनिक भारत देश का निर्धारण किया गया वह कठिन परिस्थितियों में एक राजनीतिक समझौते के आधार पर हुआ। निश्चय ही बड़े तनाव के बीच बंटवारा कर दो देश बनाए गए। इस बंटवारे के कारण लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, हजारों बेघर हो गए, शरणार्थी बन गए। देश-यात्रा पर आगे बढ़ते हुए उसकी परिधि में कई नए राज्य बने। रिश्तों, जल और अन्य संसाधनों के वितरण और पहचान के सवालों के साथ राज्यों और केंद्र के बीच के रिश्तों में खटास-मिठास के दौर आते रहे हैं। अभी भी हम उससे पूरी तरह से उबर नहीं सके हैं। जब तब सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर इसकी छाया पड़ती रहती है। वस्तुतः एक अंग्रेजी उपनिवेश से स्वतंत्र गणतंत्र में बदलने में कई तरह की प्रवृत्तियां पनपती रहीं, जिनमें विछिन्नता और निरंतरता दोनों ही दिखती हैं। शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी हमने अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई पद्धति को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया, चाहे सहूलियत के कारण या फिर उनकी ही तरह बनने की आंतरिक ख्वाहिश के कारण, पर हुआ कुछ ऐसा ही कि पुरानी लीक पर ही हम चलते रहे। आधुनिकता, वैज्ञानिकता और अंतरराष्ट्रीयता की कसौटियों पर बढ़त पाने की जुगत में हम अपनी समस्याओं के महंगे और संदिग्ध समाधान ढूंढते रहे और उनके अनुसार ही वरीयताएं तय करते रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भारत की समझ और उनके द्वारा सुझाए सामाजिक उपाय वर्तमान परिस्थितियों अनुसार हम प्रयोग में नहीं ला सके। सच कहें तो उन उपायों के बारे में संदेह बना रहा और सतही स्तर तक ही हमारी आस्था बनी रही। समय बीतने के साथ देश पर चर्चा पृष्ठभूमि में जाती रही। उसकी जगह निजी लाभ उठाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। राजनीति में जहां लोग देश हित के लिए आते थे वह परंपरा टूटती गई। अब तो रजनीति में आने वालों में से बहुतों ने अपने को निहित स्वार्थ साधने में ही लगाए रखा। ज्यादातर नेताओं की आय में बेतहाशा वृद्धि का चमत्कृत करने वाला ब्योरा किसी को भी चौंका सकता है। चारित्रिक दुर्बलताओं के चलते आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार नासूर सा बनता जा रहा है।

इन सबके बीच देश के प्रति हमारी मानसिकता पर फिर से गौर करना होगा। हम देश के क्या हैं? देश हमारा क्या है? इन सवालों पर गौर करना आवश्यक है। यह सोचना जरूरी है कि देश सिर्फ भूगोल नहीं है, न ही लोगों का जमघट है। देश एक मानसिक चेतना का नाम है। हमारी कल्पना में रहता हुआ भी देश हमारे खून में भी दौड़ता रहता है। जब कहा गया 'भूमि मां है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं' तो एक अद्भुत परिकल्पना की गई। इस रक्त संबंध में मां और बच्चे के बीच एक बड़ा कोमल और अटूट लगाव होता है। इसे सारे भेदों से ऊपर रखना जरूरी है। मुश्किल यह है कि हम व्यक्ति भी हैं और समुदायों के हिस्से भी और साथ ही देश के भी हिस्से हैं। जैसे फूलों की माला में भिन्न-भिन्न फूलों को गूंथने का आधार देने वाला एक सूत्र होता है, कुछ वैसे ही देश की चेतना भी सब को जोड़ती है। एकता का सबसे सुंदर उदाहरण हमारा अपना शरीर है। उसके सारे अंग एक-दूसरे से भिन्न हैं, वे भिन्न-भिन्न काम भी करते हैं, पर उनका एक संगीत है। जब लय और सुर ठीक नहीं रहता है या संगति नहीं बैठती है तो हम अवस्थ्य हो जाते हैं। शरीर के अंग स्वतंत्र हैं, पर परस्पर जुड़े भी हैं। उन सबको जोड़ने के लिए चेतना जरूरी है। उसके बिना सभी अंग बेकार हो जाते हैं। देश की अस्मिता ही चेतना है। समुदायों का अलग होना नियति है, पर उनका जुड़ना भी उतना ही जरूरी है। एकजुट होकर चलना देश की अनिवार्यता है, परंतु संकीर्ण सोच के चलते हम अपने को छोटी अस्मिताओं के साथ नत्थी कर देते हैं और देश जैसी बड़ी अस्मिताएं छोटी अस्मिताओं द्वारा संचालित होने लगती हैं। निहित और छोटे स्वार्थ हावी होते जाते हैं। सौभाग्य से भाषा, संस्कृति, ऋतुओं, पुष्पों, वृक्षों, जातियों सबकी जितनी तरह की विविधता भारत में है वह धरती पर अन्यत्र दुर्लभ है। विविधता हमारे लिए नई बात नहीं और वह समस्या भी नहीं रही। इन विविधताओं के बीच आवाजाही होती रही है और कुछ सूत्र उन्हें जोड़ कर रखते थे। जैसे केरल में जन्मे शंकराचार्य ने भारत में चारों ओर संवाद किया था।

देश की एकता के बारे में सोचते हुए नृत्य का रूपक याद आता है। नृत्य में हाथ पैर, अंगुलियां, आखें, सब एक खास गति, लय, ताल, छंद के साथ संचरित होते हैं और तब रस का प्रवाह होता है। उत्कृष्ट नृत्य के लिए अनुशासन और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। यह भी स्मरणीय है कि एकता एकाकार होना नहीं है, वह सब कुछ समेट कर अपने में समा लेना भी नहीं है। अलग अस्तित्व होने पर भी जुड़ाव हो सकता है। विविधता स्वाभाविक है और जैव विविधता की ही तरह सामाजिक विविधता भी जीवनी शक्ति की तरह काम करती है। हमारे हाथ और पैर की अंगुलिया भी बराबर नहीं हैं। इस विविधता का प्रयोजन है कि वे पूरक हैं और मिल कर बड़े बारीक कौशल और काम को अंजाम दे पाती हैं। भारत के इतिहास पर नजर डालें तो यहां अनेक संस्कृतियों की आवाजाही रही है, यहां अनेक दर्शन हैं। देवता भी अनोखे हैं। जैसे-गजानन गणेश, पंचानन ब्रह्मा, अर्ध नारीश्वर शिव, सांवले राम और कृष्ण? यहां कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है। यहां ईश्वर निराकार भी है और साकार भी। ब्रह्म का विचार द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि जाने कितने रूपों में किया गया है। यहां भाषाओं और उनके साहित्य की भी विविधता है, पर मानव स्वभाव के चित्रण में साम्य भी मिलता है और एक संबद्धता दिखती है। यहां पूरी सृष्टि को समेटने वाली दृष्टि व्याप्त है जिसमें 'अहं' (मैं) नहीं 'वयं' (हम सब) पर बल है। यहां सबकी चिंता की जाती है, क्योंकि सोच के केंद्र में व्यक्ति नहीं, मनुष्य और दूसरे मनुष्यों सहित पूरी सृष्टि के साथ रिश्ता है। अकेले की शोभा नहीं होती, एक-दूसरे के कल्याण या 'परहित' से ही सबका कल्याण संभव है।

अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती धमक

शशांक द्विवेदी

आज से 50 साल पहले यानी 15 अगस्त 1969 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के निर्देशन में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन किया गया था। जिस देश में कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर रॉकेट ले जाए जाते थे उसी देश ने आज चांद और आसमान पर कब्जा करना सीख लिया है। 19 अप्रैल 1975 को इसरो द्वारा स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसरो का सफर आज उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पांच देशों में से एक है।

पिछले दिनों अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रचते हुए अपने दूसरे चंद्र मिशन, चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। 15 फरवरी, 2017 को इसरो ने एक साथ 104 सेटेलाइट प्रक्षेपित करके अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया था। भारत में सेटेलाइट की कॉमर्शियल लॉन्चिंग दुनिया में सबसे सस्ती पड़ती है। भारत के जरिये सेटेलाइट लॉन्च करना अमेरिका, चीन, यूरोप से कई गुना तक सस्ता पड़ता है। लेकिन समय आ गया है जब इसरो व्यावसायिक सफलता के साथ साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरह अंतरिक्ष शोध और अन्वेषण पर भी ज्यादा ध्यान दे। इसके लिए सरकार ने इसरो का सालाना बजट जरूर बढ़ाया, पर अब भी यह नासा के मुकाबले काफी कम है। भारी विदेशी उपग्रहों को अधिक संख्या में प्रक्षेपित करने के लिए अब हमें पीएसएलवी के साथ साथ जीएसएलवी रॉकेट का भी उपयोग करना होगा। चंद्रयान 2 के लिए जीएसएलवी रॉकेट का ही प्रयोग किया गया है। वैसे तो भारत के पहले सफल चंद्र मिशन और मंगल मिशन के बाद से ही इसरो व्यावसायिक तौर पर काफी सफल रहा है और इसरो के प्रक्षेपण की बेहद कम लागत की वजह से दुनिया भर के कई देश अब इसरो से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करा रहे हैं। अंतरिक्ष बाजार में भारत के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं, इसने कई बड़े देशों का एकाधिकार तोड़ा है। असल में इन देशों को यह लगता रहा है कि भारत यदि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसी तरह से सफलता हासिल करता रहा तो उनका न सिर्फ उपग्रह प्रक्षेपण के कारोबार से एकाधिकार छिन जाएगा, बल्कि मिसाइलों की दुनिया में भी भारत इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है कि बड़ी ताकतों को चुनौती देने लगे।

भविष्य में अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि यह अरबों डॉलर का बाजार है। बीते 27 मार्च को भारत ने मिशन शक्ति के अंतर्गत जमीन से मिसाइल दागकर पृथ्वी की निचली कक्षा में 300 किमी की रेंज पर मौजूद एक सेटेलाइट को मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया था। बीते पांच दशकों में इसरो ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वह दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व का सबसे ताकतवर देश बन जाए।

खरी-खरी

परिवर्तन से भयभीत युवराज

शरद उपाध्याय

इतिहास में हुए एक युवराज गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन परिवर्तनशील है। मगर वर्तमान के एक युवराज ऐसा नहीं मानते। उन्हें परिवर्तन से डर लगता है। नए प्रयोग और नए परिवर्तन की बात आते ही वे घबरा उठते हैं। सांसें उखड़ने लगती हैं। हृदय जोर से धड़कने लगता है। वे मानते हैं कि चार दिन की जिंदगी है। दो दिन सत्ता में कट गए, बाकी दो सत्ता के इंतजार में काट लेंगे। मगर मन कुछ नया सोचने को राजी ही नहीं। पुरखों ने एक बार जो पौराणिक धारा बहा दी, वे उसी धारा की पूंछ पकड़कर सत्तामय वैतरणी पार करते रहना चाहते हैं।

पारिवारिक धारा में बहकर संगठन के शीर्ष तक पहुंचे वे अब धारा हटने से बेहद दुखी हैं। ये क्या हो गया, कैसे हो गया टाइप भौचक हैं। जो चल रहा है, वही उनका सर्वप्रिय है।

वे बरसों से बस बैठे हुए सत्ता का इंतजार कर रहे हैं। अलसाए हुए से पुराने पन्ने सहेजे हुए हैं। अपने उन 'अच्छे दिनों' की एलबम के फोटो देखते रहते हैं, जिन्हें 'अच्छे दिन' वाले ने छीन लिया। वे परिवर्तन विरोधी हैं। उन्हें यही गलतफहमी है कि लोग भी ऐसे ही हैं। वे देख नहीं पा रहे या देखना ही नहीं चाहते कि पीढ़ियां बदल रही हैं। समस्याएं बदल रही हैं। पुराने शब्दों के टोने-टोटके असर छोड़ चुके। सदियों पुरानी मानसिकता से जूझते लोग, पुरानी असहनीय परंपराओं के बोझ के तले कराह रहे हैं।

वे देख ही नहीं पा रहे कि समय की धारा बदल चुकी, धाराएं हटाई जा चुकीं, किंतु वे हैं कि पारिवारिक धारा-वाहिक में ही गुम्फित हैं। धाराओं की सील लगी खिड़कियां जंग खा चुकीं। विसंगतियां कराह रही हैं।

पर वे क्या करें। परिवर्तन उन्हें इतना डराता है कि पार्टी की कुर्सी पर भी सदी के सबसे दीर्घ चिंतन के बाद भी उनके श्रीमुख से यही निकला कि 'मां की गोद में ही जन्नत है।' हां, भारत मां की जन्नत में जो परिवर्तन हुआ, उससे उन्हें सरोकार नहीं। उनको पता है कि जमाना बहुत खराब है, किस पर विश्वास करें, किस पर न करें। सो वे मान बैठे हैं कि परिवर्तन उनकी नियति नहीं। और परिवर्तन को वे पार्टी की नियति भी नहीं बनने देना चाहते। वे जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। और उसी में खुश हैं। अब वे मन ही मन यह बुरा समय गुजरने, हालात में परिवर्तन होने की उम्मीद कर रहे हैं। यों उन्हें परिवर्तन पसंद नहीं, लेकिन अपने 'अच्छे दिन' देखने के लिए वे परिवर्तन की ही प्रतीक्षा में हैं।

ट्वीट-ट्वीट

आखिर पाकिस्तान ने भी मान लिया कि हमारी एयरफोर्स ने बालाकोट में उसके आतंकियों की कैसे कमर तोड़ी थी, कैसे घर में घुसकर मारा था? पाकिस्तानी पीएम पीओके में जाकर रोना रो रहे हैं कि भारत इस बार बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है।
समीर अब्बास@TheSamirAbbas

पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की दिखावटी असेंबली में इमरान ने आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला। उन पर पाक सेना का भारी दबाव है कि वह कश्मीर को हिंदू-मुस्लिम का सांप्रदायिक मुद्दा बना दें। वैसे कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेने वाला।
आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया और हमें जीवन के लिए लड़ाई लड़नी है। आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भारत की सौगात देने के लिए हमें स्वतंत्रता दिवस पर पर्यावरण बचाने की शपथ लेनी ही होगी। गौतम गंभीर@GautamGambhir

जब कश्मीरियों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है तब शाह फैसल के देश छोड़कर जाने की बात समझ नहीं आती।
मानक गुप्ता@manakgupta

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश डायरी

ओवैसी व बादल का धारा-118 पर विमर्श

संदेह नहीं कि अनुच्छेद 370 में अनिवार्य संशोधन का असर कई स्थानों और व्यक्तियों पर होना था, हुआ भी। लेकिन कुछ पक्ष या प्रतिपक्ष वालों ने हिमाचल की आड़ में निशाना लगाना चाहा। बात पंजाब ही नहीं, हैदराबाद तक पहुंची। जहरबुझी बातें करने और अच्छे भले 'क' में 'ख' की ध्वनि देने के लिए जाने जाते मुखर सांसद असदुद्दीन ओवैसी तथा हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी सांसद सुखबीर सिंह बादल का बयान काफी गूंजा कि अब हिमाचल प्रदेश का विशेष दर्जा समाप्त किया जाए। राजनीति में आने वाले जब इतिहास और भूगोल से अपरिचित हों, तो उनका राजनीतिक शास्त्र कोरे जज्बात तक या अवसरवादिता तक रह जाता है।

अनुच्छेद 370 और हिमाचल की धारा 118 की तुलना वैध है? ओवैसी को अनुच्छेद 370 में संशोधन के विरुद्ध बोलना था। बादल उसी पंजाब से हैं जिसे तब बेहद तकलीफ हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी ने हिमाचल प्रदेश को औद्योगिक पैकेज दिया था। जहां तक विशेष दर्जे की बात है, यह देखना ओवैसी या बादल का काम नहीं है। इसके लिए जो प्रावधान हैं, उनमें संविधान में ही कठिन भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और राज्य का संसाधनविहीन होना जैसे पक्ष उल्लिखित हैं। हिमाचल प्रदेश किसी भी तरह जम्मू-कश्मीर नहीं है। यहां अलगाव के स्वर नहीं, देश की संप्रभुता की नींव में मजबूत आधार है हिमाचल। यहां के युवा पत्थरबाज नहीं हैं बल्कि सेना, चिकित्सा, विज्ञान के क्षेत्र में झंडे गाड़ते हैं। पहला परमवीर चक्र विजेता यहां से था और कारगिल में भी दो परमवीर दिए। आबादी के अनुपात से देखें तो सर्वाधिक फौजी यहां से। देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख यहां से हैं।

अब आते हैं धारा 118 पर। यह है क्या। यह हिमाचल प्रदेश भू सुधार अधिनियम की वह धारा है जिसके तहत हिमाचल में कोई भी गैर हिमाचली भूमि नहीं खरीद सकता। बल्कि कोई गैर कृषक हिमाचली भी भूमि नहीं खरीद

सकता। इस धारा की परिकल्पना करने वाले थे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार। उनका ठीक ही मानना था कि प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और संस्कृति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। आशंका थी कि संसाधन संपन्न व्यक्ति जमीन खरीद लेंगे और मूल निवासी जमीन बेच कर कहीं के नहीं रहेंगे। मौजूदा मायाजाल में गरीब किसान पर यह डर और बढ़ गया है। डॉ. परमार की दूरदर्शिता पर कांग्रेस तो क्या, किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। तब से हरे-भरे हिमाचल पर टपकती लालच की लार के आड़े यह धारा तनी हुई है।

लेकिन हर प्रावधान का एक समय होता है। धारा 118 जब लागू हुई थी, समय की मांग थी। अब भी इसे हटना नहीं चाहिए, लेकिन समय की ताल पर अगर विकास का गीत गाना है तो कतिपय संशोधन भी आवश्यक होंगे। जाहिर है हिमाचल हित के लिए, किसी ओवैसी या सुखबीर बादल के लिए नहीं। केवल उनके लिए जो निवेश करने आता है, लेकिन लालफीताशाही के चक्करों में चक्कर खाकर गिर जाता है। हमारी व्यवस्था उसे आभास दिलाती है कि वह अपराधी है। अगर धर्मगुरुओं को धारा 118 में छूट मिल सकती है, उनके मंच और मठ बन सकते हैं, नेताओं के लिए छूट हो सकती है तो हिमाचल की प्रगति में सहयोग करने वाले व्यापारिक घरानों को क्यों नहीं। प्रदेश में प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट से पहले कई प्रतिष्ठित समूहों को आमंत्रित किया गया है, उनके निवेश के लिए आसानी हो, हिमाचल हितों को सुरक्षित रखते हुए तो परेशानी क्यों हो। यह भी संयोग है कि हिमाचल प्रदेश में अब तक जितने संशोधन हुए हैं, कांग्रेस के समय में हुए हैं। बात भाजपा, कांग्रेस की नहीं, बात है हिमाचल हित की। लेकिन हैरानी तब होती है जब हिमाचल कांग्रेस के नेता ऐसे मुद्दे पर शोर मचा रहे हैं जो है ही नहीं। जब अनुच्छेद 370 में संशोधन हुआ तो कई लोग मरघट सी खामोशी में थे, लेकिन अब शोर मच रहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश ने धारा 118 हटाई तो ठीक नहीं होगा। वे इसमें कोई संशोधन भी नहीं चाहते जबकि निवेश को हिमाचल हित की शर्त में ढील न देते हुए आसान बनाना हिमाचल के ही पक्ष में होगा। हिमाचल प्रदेश में जिन्हें लगता है कि प्रदेश को बेच दिया जाएगा, उन्हें यह जवाब भी देना चाहिए कि धारा 118 के उल्लंघन की शिकायतों पर जस्टिस डीपी सूद की अध्यक्षता में गठित समिति की रपट पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? ऐसे कौन लोग थे जिनके नाम आए थे? क्या किसी का जब्त होटल अदालती आदेश से आगे जाकर उसे वापस नहीं किया गया था?

बाकी जिस प्रकार कानूनों को धता बताते हुए शिमला में अवैध निर्माण को नियमित करने की मांग होती है, खनन से खौफ खाई हुई नदियां राह भूलने लगती हैं, पहाड़ों के सीनों से सुरंगें गुजारी गई हैं, वहां हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने के लिए बाहर से किसी की जरूरत क्यों हो? जहां बीट की बीट उजाड़ कर लोग बचे रहे हों, वहां क्या बाहर से किसी की जरूरत है?

जागरण जनमत कल का परिणाम

आपको लगता है कि सरकार को गुलाम कश्मीर को लेकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए?

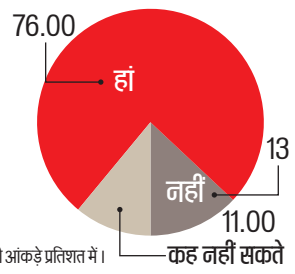

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

कश्मीरी जब ले रहे आजादी की सांस,
ओवैसी उस्ताद के गले फंसी है फांस।
गले फंसी है फांस कर रहे बिलबिल बिलबिल,
हैं निजाम अवतार उसी का पाया है दिल।
चमकाओ तुम यार मुफ्त की नेतागीरी,
ध्वज फहराकर आज जश्न करते कश्मीरी।
- ओमप्रकाश तिवारी

विश्व संस्कृत दिवस

भारत की आत्मा है संस्कृत भाषा

डॉ. कृष्ण चंद्र पांडे
सलाहकार, आकाशवाणी

संस्कृत विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। इसका साहित्य सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता आ रहा है। कुछ चुनौतियों के बावजूद इसका आकर्षण कम नहीं हुआ है

किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है। राष्ट्र की भाषा ही उसकी शक्ति होती है। भाषा ही समाज को अपने राष्ट्र के साथ जोड़ती है। भाषा के कारण न केवल संस्कृति का संरक्षण होता है, अपितु राष्ट्र के साथ अनन्य संबंध भी स्थापित होता है। विश्व के अनेक राष्ट्र जो अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के कारण विश्व में उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, वे अपनी भाषा के प्रति समर्पित हैं। अपनी भाषा के प्रति स्वाभिमान, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान को जागृत करता है।

इस संबंध में इजरायल के विषय में यह जानना आवश्यक है कि इजरायल को पुनः राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम वहां की हिब्रू भाषा ने किया है। हिब्रू भाषा मृतप्राय हो चुकी थी। केवल धार्मिक ग्रंथों की भाषा मात्र थी। हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित करने का संकल्प यहूदी समाज के मन में था और वे उस संकल्प को लेकर आगे बढ़े और उसे पुनर्जीवित भी किया। आज इजरायल विश्व के एक शक्तिशाली और समर्थ राष्ट्र के रूप में हमारे समक्ष खड़ा है। भारत के विषय में यदि हम विचार करें तो हम भारत की सांस्कृतिक विरासत और इतिहास जिस भाषा में पाते हैं वह संस्कृत है। संस्कृत भाषा का साहित्य विश्व का सबसे प्राचीन और समृद्ध साहित्य है। यह न केवल भारत को एक सूत्र में पिरोता है, अपितु संपूर्ण विश्व को मानवता की शिक्षा देता है। संस्कृत साहित्य ही भारतीय संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति हमें तेरे और मेरे के भाव से मुक्त कर विश्व को एक परिवार के रूप में मानती है।

अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम।
उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम।।

इस उदार भाव को समाज में स्थापित करने का कार्य संस्कृत साहित्य के माध्यम से हो सकता है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में स्थापित करने का कार्य यदि कोई भाषा कर सकती है तो वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत कवियों ने भारतीय एकात्मता को अपने ग्रंथों में दर्शाया है।

संस्कृत न केवल भारतीय ज्ञान विज्ञान की भाषा है, अपितु भारत की आत्मा संस्कृत ग्रंथों में निहित है। भारत की चिति को समझने के लिए भारतीय साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, धर्मग्रंथ, रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र कामसूत्र, अष्टाध्यायी आदि भारतीय ज्ञान मीमांशा के अनुपम ग्रंथ हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर हजारों वर्षों से अटूट चली आ रही है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और निरंतर बहती चली जाती है उसी प्रकार हिमालय से ही हमारे सांस्कृतिक दार्शनिक और आध्यात्मिक स्रोत उभरते हैं। संस्कृत भाषा की शक्ति से भयभीत होकर ही मैकाले ने इस भाषा को समाज से दूर करने का कुत्सित षड्यंत्र रचा और भारतीय समाज उस कुचक्र में फस गया। आज देश में जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है उसका मूल कारण हमारा अपनी भाषा से दूर होना है। इस ओर अगर हमारा ध्यान नहीं गया तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना संस्कार होता है। भाषा में उस देश की मिट्टी की खुशबू होती है। वह जहां जहां फैलती है समाज के मन मस्तिष्क को अपनी महक से आप्लावित कर लेती है और समाज अपने देश की मिट्टी की खुशबू को भूल जाता है। उसे अपने देश की मिट्टी से बदबू आने लगती है। हमारे देश में आज यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। वैश्वीकरण की दुहाई देकर भले ही हम इससे मुंह मोड़ लें, परंतु यह स्थिति समाज को देश की मिट्टी और देश की परंपराओं से दूर ले जा रही है।

ईसाई धर्म प्रचारक इस बात को शीघ्र ही समझ गए थे कि जब तक भारत में संस्कृत भाषा का प्रभाव रहेगा, तब तक इस देश में ईसाई धर्म का काम नहीं किया जा सकता। एक ब्रिटिश लेखक ने वर्ष 1815 में धर्म प्रचार संबंधी अपना अनुभव लिखा है। उससे ज्ञात होता है कि ईसाई धर्म के प्रचार में सबसे बड़ी बाधा संस्कृत भाषा और उसमें लिखा हुआ साहित्य है। वह लिखते हैं, 'पिछले तीन दशकों में हमने केवल 300 लोगों का ही धर्म परिवर्तन कराया है। यहां की शिक्षा व्यवस्था संस्कृत भाषा (अपनी मूल भाषा) में होने के कारण अपने धर्म और परंपराओं में दृढ़ आस्था है। जब तक पाश्चात्य भाषा में शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना कठिन है।' इसी को ध्यान में रखकर मैकाले ने कहा था कि थोड़ी सी अंग्रेजी शिक्षा से ही

बंगाल में कोई मूर्ति पूजक नहीं रह जाएगा। ईसाई पादरी मैकाले की इस आशा से पूर्ण रूप से सहमत थे। वर्ष 1835 में डॉक्टर डफ ने घोषणा की थी कि जिस जिस दिशा में अंग्रेजी शिक्षा प्रगति करेगी, उस उस दिशा में हिंदुत्व के अंग टूटते जाएंगे और धीरे-धीरे हिंदुत्व का कोई भी अंग साबित नहीं रहेगा।'

भारत विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्र होने के कारण ज्ञान विज्ञान का आदि राष्ट्र है। शिक्षा के प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला जैसे विशालतम विश्वविद्यालय भारत में थे। संपूर्ण विश्व के लिए ये शिक्षा के केंद्र रहे। विश्व भर से ज्ञान पिपासु यहां आकर अपनी ज्ञान क्षुधा को शांत करते रहे। आज विश्व में विविध प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की जो चमक दिखाई देती है उसके बीज भारत से ही दुनिया भर में गए। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था।

एक से नौ तक के अंक, शून्य और दशमलव की पद्धति इन सबका आविष्कार भारत में ही हुआ। दशमलव पद्धति का ज्ञान आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के समय भारत में बहुत प्रचलित था। बौद्ध धर्म प्रचारकों के द्वारा यह ज्ञान चीन पहुंचा। बीजगणित का विकास भारत में हुआ, और यहां से यूनान पहुंचा और अरब से होते हुए यह यूरोप पहुंचा। ज्योतिष और गणित के प्राचीन आचार्यों में आर्यभट्ट का स्थान भारत में ही नहीं, अपितु सारे विश्व में सबसे ऊंचा है। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले संसार को यह ज्ञान दिया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने ही ग्रहण की भविष्यवाणी करने की विधि निकाली। आर्यभट्ट के बाद दूसरे आचार्य ब्रह्मगुप्त हुए जिन्होंने भारत की ज्योतिष विद्या को संगठित रूप दिया।

वैश्विक संकेतों के दम पर शेयर बाजार में उछाल

मुंबई : बुधवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 353 .37 अंक चढ़कर 37311 .53 पर बंद हुआ। दूसरी ओर, एनएसई का निफ्टी भी 103 .55 अंक बढ़कर 11029 .40 पर बंद हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। इससे अमेरिका-चीन ट्रेड वार को लेकर निवेशकों की आशंका कम हुई और बाजार को गति मिली। महंगाई में गिरावट के आंकड़े से भी निवेशकों की धारणा को बल मिला। (प्रेट्र)

सीएसआइआर-आइआइसीटी से नई दवाओं के विकास के लिए हुआ करार हमारी ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस को नई दिशा देगा।
—दिलीप सांघवी, एमडी, सन फार्मा

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना	चांदी	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट)
37,311.53 ▲ 353.37	11,029.40 ▲ 103.55	₹ 37,945 प्रति दस ग्राम ▼ ₹425	₹ 44,310 प्रति किलोग्राम ▼ ₹690	₹ 71.27 ▼ ₹0.13	$ 58.63 प्रति बैरल

थोक महंगाई 25 माह के निचले स्तर पर

राहत ▶ मैन्यूफैक्चरिंग के आधा दर्जन से अधिक उत्पादों की थोक महंगाई दर नकारात्मक

जून के 2 .02 फीसद से घटकर जुलाई में महंगाई दर 1 .08 फीसद पर आ गई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मैन्यूफैक्चरिंग, ईंधन और खाद्य वस्तुओं की कीमतें कम रहने के चलते थोक महंगाई दर जुलाई में घटकर 1.08 फीसद पर आ गई है। यह थोक महंगाई का 25 महीनों का निचला स्तर है। खास बात यह है कि मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक उत्पादों की थोक महंगाई दर नकारात्मक स्तर पर चली गई है।

खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जुलाई में 6 .15 फीसद रही। प्रतीकात्मक फोटो

थोक महंगाई दर इस साल जून में 2.02 फीसद तथा पिछले साल जुलाई में 5.27 फीसद थी। इससे पूर्व थोक महंगाई दर का निचला स्तर जून, 2017 में 0.9 फीसद दर्ज किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जुलाई में 6.15 फीसद रही जबकि जून में यह 6.98 फीसद थी। खाद्य वस्तुओं में आलू की महंगाई दर में लगातार गिरावट आ रही है। जुलाई में आलू की महंगाई दर -23.63 फीसद रही जबकि जून में 24.27 फीसद थी। कुल मिलाकर सब्जियों की महंगाई दर जुलाई में 10.67 फीसद रही। हालांकि फलों की महंगाई दर इस साल जुलाई में बढ़कर 15.38 फीसद हो गई है, जबकि जून में यह 1.87 फीसद थी।

थोक महंगाई दर की प्रोडक्ट बास्केट में मैन्यूफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का योगदान 64.23 फीसद है। मैन्यूफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर जुलाई में 0.34 फीसद रही जबकि जून में यह 0.94 फीसद थी। मैन्यूफैक्चरिंग के आधा दर्जन से अधिक उत्पादों जैसे- चीनी (-0.94 फीसद), कपड़े (-1.08 फीसद), चमड़ा और उससे जुड़े हुए उत्पाद (-4.37 फीसद), रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद (-0.27 फीसद), बेसिक मेटल (-4.28 फीसद) और सेमी फिनिश्ड स्टील (-4.62 फीसद) की थोक महंगाई दर जुलाई में नकारात्मक रही है। मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की महंगाई दर में गिरावट इस क्षेत्र में उत्पादों की मांग की स्थिति को दर्शाती है। इसी तरह ईंधन और बिजली क्षेत्र की महंगाई दर जुलाई में -3.64 फीसद रही। सरकार ने पिछले हफ्ते खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए थे। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 3.15 फीसद रही है जो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित रखने के लक्ष्य (प्लस माइनस चार फीसद) से कम है। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति तय करते वक्त खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों को ही संज्ञान में लेता है। ऐसे में थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर दोनों में गिरावट आने से ब्याज दरों में कटौती की राह आसान हो जाएगी।

हमेशा अच्छी नहीं होती कम महंगाई : महंगाई दर घटने से आम आदमी को राहत मिलती है। खर्चे कम होते हैं और बचत बढ़ जाती है। लेकिन, यदि यह एक सीमा से नीचे आ जाए तो अर्थव्यवस्था में मांग घटने का संकेत भी होता है। महंगाई दर कम होने का एक बड़ा कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें नीचे रहना है। इसमें बहुत ज्यादा कमी आने का एक मतलब यह भी है कि किसानों की आय घट जाएगी। ऐसे में मांग सुस्त पड़ेगी, जिसका विपरीत असर अर्थव्यवस्था और रोजगार पर होगा।

दिवालिया मामलों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में नहीं लटकाने की सिफारिश

- सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिया सुझाव
- समिति ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी अपनी रिपोर्ट

स्वचालित मंजूरी के लिए ग्रीन चैनल रूट का भी है सुझाव। प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय समिति ने दिवालिया कानून के तहत आने वाले मामलों को सुलझाने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) के 'ग्रीन चैनल अप्रूवल' की सिफारिश की है। समिति ने प्रतिस्पर्धा नियामक ढांचे में ठोस बदलाव का सुझाव भी दिया है। प्रतिस्पर्धा कानून के तहत तय सीमा से बड़े अधिग्रहण सौदों में सीसीआइ की मंजूरी जरूरी है।

कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति ने कानून में कई बदलाव करने की सिफारिश की है। समिति ने कुछ मामलों में स्वचालित मंजूरी के लिए ग्रीन चैनल रूट का सुझाव दिया है। इसका मतलब यह है कि खास तरह के मामलों के लिए सीसीआइ ऐसी व्यवस्था करे, जिसके तहत उनसे जुड़ी सभी सूचनाओं का पहले से मूल्यांकन हो जाए और आयोग में वह मामला ज्यादा दिनों तक नहीं पड़ा रहे। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे मामलों से संबंधित पक्ष तय मानदंडों और सीसीआइ से परामर्श के बाद स्वमूल्यांकन कर लें कि वे ग्रीन चैनल रूट के तहत योग्यता रखते हैं। विलय की अधिसूचना और अधिकतर मामलों की मंजूरी के लिए ग्रीन चैनल रूट होना चाहिए। सरकार सीसीआइ के साथ परामर्श कर विस्तृत पात्रता मानदंड बना सकती है।

इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के तहत दिवालिया समाधान प्रक्रिया में होने वाले विलय और अधिग्रहण सौदे ग्रीन चैनल रूट से मंजूरी के पात्र होंगे। बुधवार को समिति के चेयरमैन श्रीनिवास ने वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को रिपोर्ट सौंप दी। समिति का गठन पिछले वर्ष अक्टूबर में किया गया था। पैनल ने राज्यों के कानून और नीतियों की प्रतिस्पर्धा के आधार पर रैंकिंग सिस्टम बनाने का भी सुझाव दिया है। रिपोर्ट में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) की एक बेंच बनाने का भी सुझाव दिया है, जिसमें इस कानून के तहत अपीलों की सुनवाई हो सके। समिति ने एक गवर्निंग बोर्ड का सुझाव दिया है जिसमें एक चेयरमैन और छह पूर्णकालिक और छह अंशकालिक सदस्य हों।

ऊंचे स्तर पर बिकवाली के कारण सोना-चांदी में फिसलन

- 425 रुपये फिसलकर 37,945 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया सोने का भाव
- 690 रुपये की गिरावट के बाद 44,310 रुपये प्रति किलोग्राम पर आई चांदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : ऊंचे स्तर पर सोना और चांदी में हुई बिकवाली के चलते बुधवार को सराफा बाजार में मंदी हावी रही। दिन के कारोबार में सोना 425 रुपये फिसलकर 37,945 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया। कारोबार के दौरान चांदी भी 690 रुपये टूटकर 44,310 रुपये प्रति किलोग्राम की रह गई।

विदेशी बाजारों में पिछले दो सत्रों की तरह बुधवार को भी सोने-चांदी में तेजी का रुख था। लेकिन घरेलू बाजार को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया। चांदी को चांदी को सिक्का निर्माताओं और औद्योगिक इकाईयों की तरफ से अपेक्षित मदद नहीं मिली।

न्यूयॉर्क में सोने का भाव मजबूती के साथ 1,509.09 डॉलर, और चांदी का भाव उछाल के साथ 17.22 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर था। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 37,945 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 37,575 रुपये प्रति 10 ग्राम का रह गया। आठ ग्राम सोने की गिन्नी का भाव भी 100 रुपये टूटकर 28,700 रुपये के स्तर पर आ गया। चांदी हाजिर 690 रुपये फिसलकर 44,310 रुपये प्रति किलोग्राम की रह गई। चांदी का सप्ताह आधारित डिलिवरी भाव 1,050 रुपये की गिरावट के बाद 43,230 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। चांदी के सिक्कों का भाव 1,000 रुपये प्रति सैकड़ा फिसलकर 88,000 रुपये खरीद और 89,000 रुपये बिक्री पर रह गया।

अक्टूबर से फर्जी आयकर नोटिस की गुंजाइश ही हो जाएगी खत्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- डिन के बगैर इनकम टैक्स का नोटिस नहीं भेज पाएंगे अधिकारी
- इससे आयकर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी होगी सुनिश्चित

विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने में जुटी है सरकार। प्रतीकात्मक फोटो

आयकर विभाग पर 'टैक्स टेररिज्म' के आरोपों के मद्देनजर सरकार अब विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने में जुट गई है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बुधवार को एलान किया कि इस वर्ष पहली अक्टूबर से आयकर विभाग के अधिकारी असेसी (जिसके आयकर का मूल्यांकन होना है) के साथ जो भी पत्राचार करेंगे, उन पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डिन) देना होगा। माना जा रहा है कि विभाग के इस कदम से न सिर्फ आयकर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी, बल्कि असेसी को फर्जी इनकम टैक्स नोटिस भेजे जाने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी।

सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर कहा कि टैक्स प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और सेवा में सुधार के लिए आयकर विभाग के लगभग सभी नोटिस और आदेश इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जारी किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं जहां असेसी को भेजे नोटिस या पत्र का कोई लेखाजोखा उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि अब सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पहली अक्टूबर के बाद असेसी के साथ किये जाने वाले सभी तरह के पत्र व्यवहार के लिए कंप्यूटर आधारित डिन नंबर जारी करके उसका स्पष्ट उल्लेख करें। उन्हें असेसी को नोटिस भेजने से लेकर, असेसमेंट, अपील, आदेश, छूट, जांच और जुर्माना और अभियोजन सहित सभी तरह की कार्रवाई में डीआइएन नंबर का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि अपवाद-स्वरूप कुछ मामलों में यह नियम लागू नहीं होगा। लेकिन ऐसे मामलों में असेसी के साथ पत्राचार करने के लिए महानिदेशक या कमिश्नर के स्तर के अधिकारियों से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। सीबीडीटी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब हाल ही में उद्योग जगत ने टैक्स अधिकारियों द्वारा परेशान करने की शिकायत की है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार पर टैक्स टेररिज्म का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि ईमानदार और कानून का पालन करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। सीबीडीटी का कहना है कि टैक्स अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए करदाताओं को बेहतर सेवा देने की दिशा में डिन एक और कदम है।

आरबीआइ की पूंजी पर जालान समिति की सिफारिशें तय

- सरप्लस का एक हिस्सा सरकार को किस्तों में देने की सिफारिश
- अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंपे जाने का अनुमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के लिए आरक्षित पूंजी का उपयुक्त स्तर तय करने को लेकर गठित बिमल जालान समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की ली है। इसे एक दो दिनों में ही में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनका कहना था कि रिजर्व बैंक की वर्तमान आरक्षित पूंजी से अतिरिक्त धन (सरप्लस) का सरकार को हस्तांतरण किस्तों में हो सकता है। समिति में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि और तत्कालीन आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को बिजली मंत्रालय भेज दिए जाने के बाद समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। गर्ग के स्थानांतरण के समय रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा था। गर्ग के बाद समिति में बैंकिंग मामलों के सचिव (अब वित्त-सचिव भी) राजीव कुमार को नियुक्त किया गया।

सूत्रों के अनुसार, समिति ने अपने सुझाव तैयार कर लिए हैं और अब आगे इसकी कोई और बैठक नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि हमने चर्चा पूरी कर ली है। अब यह अंतिम रिपोर्ट है। यह बताना, या इसका हिसाब देना मुश्किल होगा कि (आरबीआइ से) सरकार को कितना धन हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरण परंपरा के तहत चरणबद्ध तरीके से होगी।

2018 में बनी थी समिति : उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में यह रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सौंप दी जाएगी। रिजर्व बैंक की आर्थिक पूंजी रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए 26 दिसंबर, 2018 को इस छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। विभिन्न पूर्वानुमानों के आधार पर रिजर्व बैंक के पास नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक का सरप्लस है। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच सरप्लस के उचित स्तर तथा इसमें बेशी राशि के हस्तांतरण को लेकर विवाद होने के बाद समिति का गठन किया गया था।

पहले भी बनीं समितियां

इससे पहले भी 1997 में वी सुब्रमण्यम समिति, 2004 में उषा थोरट समिति और 2013 में वाईएच मालेगम समिति रिजर्व बैंक के भंडार की समीक्षा कर चुकी हैं। सुब्रमण्यम समिति ने इसे केंद्रीय बैंक की बैलेंसशीट (संपत्ति) के 12 फीसद भंडार का सुझाव दिया था, जबकि थोरट समिति ने भंडार को 18 फीसद के स्तर पर बनाए रखने का सुझाव दिया था।

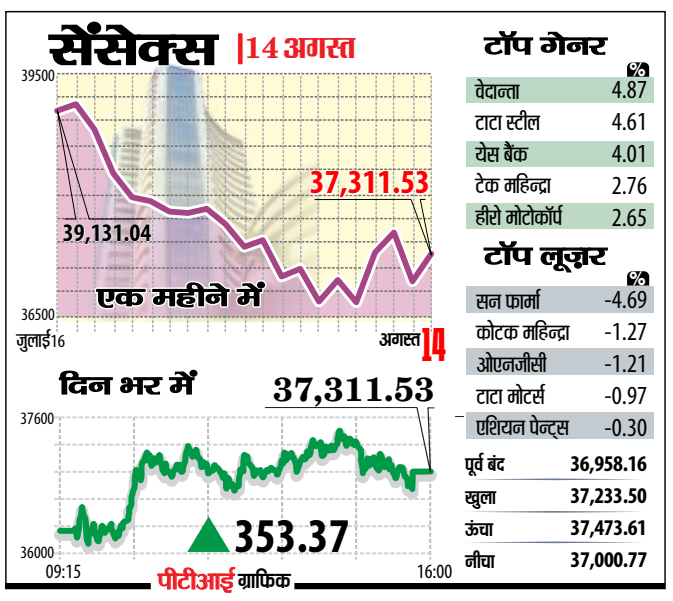

देशभर में अपनी 11 संपत्तियां बेचेगा इलाहाबाद बैंक

राजीव सक्सेना, कानपुर

खास बातें

- पहले चरण में कानपुर, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर की संपत्तियां
- मुंबई की दो, नागपुर व सोनीपत की एक-एक संपत्ति भी बेची जाएगी
- कानपुर, सोनीपत की संपत्ति के खरीदार आगे आए, ऑनलाइन बिड शीघ्र
- दूसरे चरण के लिए बैंक की कई अन्य संपत्तियां भी चिह्नित की जाएंगी

इलाहाबाद बैंक देश में अपनी 380.73 करोड़ रुपये की 11 संपत्तियां बेचने जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश की सात, महाराष्ट्र की तीन, हरियाणा की एक संपत्ति है। फिलहाल कानपुर और सोनीपत की संपत्ति खरीदने के लिए खरीदार आगे आए हैं। जल्द ही इनके लिए ऑनलाइन बिडिंग होगी। दूसरे चरण की संपत्तियों को चिह्नित करने का कार्य भी जल्द शुरू होगा। इलाहाबाद बैंक आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अपनी संपत्तियां बेचने जा रहा है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, सीतापुर, शाहजहांपुर, महाराष्ट्र में मुंबई की दो, नागपुर की एक और हरियाणा में सोनीपत की संपत्ति है। संपत्तियां बेचने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड (यूपिको) को दी गई है। 15 दिन में ऑनलाइन बिडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कानपुर में बैंक रायपुरवा का प्लाट बेचेगा।

100 वर्ष पुरानी हैं संपत्तियां : पहले चक्र में जो संपत्तियां शामिल की गई हैं, उनमें ज्यादातर सौ वर्ष से ज्यादा पुरानी हैं। ये संपत्तियां बैंक को ब्रिटिश साम्राज्य में मिली थीं।

यूपिको के प्रबंध निदेशक प्रवीण सिंह ने कहा कि यूपिको को इलाहाबाद बैंक की संपत्तियों की बिक्री की जिम्मेदारी मिली है। पहले चरण में 11 संपत्तियों की बिक्री की जा रही है। इनकी ऑनलाइन बिडिंग की प्रक्रिया 15 दिन में शुरू कर दी जाएगी।

नाकाफी वेतन और मजदूरी के कारण बढ़ रहीं अर्थव्यवस्था की दिक्कतें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- वेतन व मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने से दिख रही मांग में कटौती

प्रतीकात्मक फोटो

देश की अर्थव्यवस्था के सामने मंदी के गहराते बादल को लेकर आर्थिक शोध एजेंसियों की चेतावनी पहले से ज्यादा साफ और चिंताजनक हो गई है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआइ के आर्थिक शोध विभाग की तरफ से बुधवार को जारी अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट ने मौजूदा मंदी के लिए वैश्विक व चक्रीय तथ्यों के साथ ही संगठनात्मक तथ्यों को भी दोषी करार दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार की आर्थिक नीतियों को भी सवालों के घेरे में लिया गया है और यह चेतावनी दी गई है कि अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां अभी और गंभीर रूप ले सकती हैं। खासतौर पर रोजगार के अवसरों पर इसका बड़ा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है।

रिपोर्ट में नीति निर्धारकों से तीन सवाल पूछे गए - मांग नहीं होने के पीछे वजह क्या है, यह चक्रीय मंदी है या इसके लिए नीतियां भी जिम्मेदार हैं, और क्या बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया है जिससे मांग पर असर पड़ रहा है? बैंक कर्ज देना कम कर देते हैं। वेतन व मजदूरी के बारे में रिपोर्ट कहता है कि पिछले कुछ वर्षों से देश की 4,000 से 5,000 कंपनियों की तरफ से औसतन वेतन वृद्धि 20.5 फीसद सालाना की थी जो अब घट कर एकल अंक में रह गई है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी की दर वर्ष 2015 तक 27.5 फीसद तक की औसत थी जो अब घट कर 5 फीसद रह गई है। इसने घरेलू बचत को भी प्रभावित किया है जिससे मांग पर उल्टा असर पड़ा है। ऐसे में सरकार को मंदी से लड़ने के लिए ज्यादा समझदारी दिखानी होगी और इसके लिए कई सेक्टर पर ध्यान देना होगा।

अलग-अलग सेक्टर पर उनकी दशा के हिसाब से नीतियां बनानी होगी, कर संबंधी मुद्दों का समाधान निकालना होगा, निर्यात को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए भी कदम उठाना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ाने पर खास तौर पर ध्यान देना होगा, एनपीए की वजह से फंसी परिसंपत्तियों का समाधान निकालना होगा। रिपोर्ट ने इस मत को खारिज किया है कि बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं इसलिए मांग नहीं बढ़ पा रही है। कहा गया है कि स्थिति विपरीत है। हकीकत यह है कि मांग नही है इसलिए बैंक कर्ज नहीं दे रहे हैं। देश में अभी उद्योग अपनी क्षमता का महज 76.1 फीसद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल निवेश में निजी निवेश की हिस्सेदारी 50 फीसद से घट कर 30 फीसद रह गई है।

इंडियन ऑयल करेगी दो लाख करोड़ रुपये का निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) अगले पांच-सात वर्षों में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन क्षमता में विस्तार के लिए दो लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। आइओसी के चेयरमैन संजीव सिंह ने बताया कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने के लिए यह निवेश करेगी।

योजना के अनुसार कंपनी अपनी ऑयल रिफाइनिंग क्षमता को दोगुना कर प्रतिवर्ष 15 करोड़ टन तक बढ़ाएगी। इसके साथ ही तेल और गैस का रिटेल नेटवर्क और पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता का विस्तार कर अधिक कच्चे तेल और गैस का उत्पादन करेगी। कंपनी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस निवेश के माध्यम से वह भविष्य के लिए तैयार होना चाहती है। वर्तमान में कंपनी 8.07 करोड़ टन रिफाइनिंग की क्षमता वाली देश की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग कंपनी है। इसके साथ ही कंपनी अपने पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता को वर्तमान के 31.5 लाख से बढ़ाकर 1.3 करोड़ टन तक करना चाहती है। कंपनी गुजरात, पारादीप और पानीपत में नए केमिकल प्रोजक्ट स्थापित करने की योजना बना रही है।

जुलाई में निर्यात में सवा दो फीसद की बढ़ोतरी

बेहतर हालत

आयात में तेज गिरावट से व्यापार घाटा 13 .43 अरब डॉलर पर आया, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद समेत कई अहम उत्पाद वर्गों में आयात में कमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिका-चीन के बीच चल रही कारोबारी जंग ने पूरी दुनिया में निर्यात को प्रभावित किया है। प्रतीकात्मक फोटो

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धीमी निर्यात रफ्तार के बीच भारत ने जुलाई में निर्यात में सवा दो फीसद की मामूली वृद्धि दर्ज की है। इस महीने देश से 26.33 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। लेकिन आयात में तेज कमी के चलते देश का व्यापार घाटा कम होकर 13.43 अरब डॉलर पर आ गया। बीते साल जुलाई में व्यापार घाटा 18.63 अरब डॉलर रहा था।

अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुए कारोबारी युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होने के बाद पूरी दुनिया में निर्यात प्रभावित हुआ है। इसके चलते जून 2019 में देश के निर्यात में 9.71 फीसद की गिरावट दर्ज की गई थी। यही वजह है कि जुलाई में भी निर्यात में केवल 2.25 फीसद की वृद्धि ही दर्ज हो पाई है। जुलाई 2018 में देश से 25.75 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। जुलाई के महीने में निर्यात होने वाले 30 उत्पाद वर्गों में से 17 में वृद्धि दर्ज की गई है।

जहां तक आयात का सवाल है जुलाई में आयात में 10.43 फीसद की गिरावट हुई है। इस महीने देश में 39.76 अरब डॉलर का आयात हुआ। जबकि साल 2018 में 44.39 अरब डालर के सामानों का आयात हुआ था। आयात का कम होना कुछ मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। इस महीने ऐसे कई उत्पाद वर्गों में आयात में कमी आई है जो देश में मांग की स्थिति को दर्शाती है। मसलन ट्रांसपोर्ट उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोना, कीमती रत्न और न्यूजप्रिंट के आयात में खासी गिरावट जुलाई में आई है। सोने का आयात बीते साल के जुलाई महीने के मुकाबले 42.20 फीसद कम हुआ है। जबकि न्यूजप्रिंट के आयात में 16.50 फीसद की कमी आई है। इस वर्ष के बजट में सरकार ने न्यूजप्रिंट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर शून्य से दस फीसद कर दी थी। इसी तरह देश में टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग में कमी के चलते इनका आयात 1.70 फीसद कम हुआ। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में भी खासी कमी आई है।

निर्यात के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए निर्यात संगठनों के फेडरेशन फियो के प्रेसिडेंट शरद कुमार सराफ का कहना है कि यह वैश्विक स्तर पर मांग में कमी को दर्शाते हैं। सराफ का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच छिड़े कारोबारी युद्ध से होने वाले नुकसान की भरपाई चीन अपनी नीतियों में फेरबदल के जरिए पूरा कर रहा है। 'अमेरिका की तरफ से चीनी उत्पादों पर बढ़ी शुल्क दर के असर को चीन ने अपनी मुद्रा की कीमत को घटाकर बराबर कर लिया है। इससे चीन का निर्यात वैश्विक बाजारों में भी प्रतिस्पर्धी हो गया है। जो भारत की दिक्कतों को बढ़ा रहा है।'

निर्यात वृद्धि दहाई अंक में पहुंचेगी : वधावन

कोलकाता, प्रेट्र : वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने बाहरी और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में निर्यात वृद्धि दर 10 फीसद से ऊपर जाने की उम्मीद जताई है। उन्होंने बुधवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में निर्यात की वृद्धि दर दहाई अंकों के नीचे रही थी। उस दौरान 331 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात हुआ था। वधावन ने कहा कि पिछले तीन साल में देश ने लगातार वृद्धि को देखा है।चालू वित्त वर्ष में हमें निर्यात वृद्धि दर के दहाई अंक में पहुंचने की उम्मीद है।

वधावन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अनुमान के अनुसार वैश्विक मंदी लगभग दिखाई दे रही है। इस तथ्य को संशोधित विदेश व्यापार नीति में भी रेखांकित किया जाएगा। वर्तमान विदेश व्यापार नीति की समय-सीमा 31 मार्च 2020 तक है। हर पांच साल में नई विदेश व्यापार नीति जारी की जाती है। वधावन के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के शुरुआती कुछ महीनों में निर्यात और आयात दोनों प्रभावित हुए। हालांकि निर्यात वृद्धि किसी तरह पूर्व के स्तर पर बनी रही, लेकिन आयात में गिरावट आई है। इससे व्यापार घाटे में सुधार हुआ है।

उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में तेज गिरावट

मुंबई, प्रेट्र : घरेलू बाजार में वाहनों की बिक्री और उत्पादन में लगातार भारी गिरावट अर्थव्यवस्था कमजोर होने का बड़ा संकेत माना जा रहा है। जुलाई में पैसेंजर वाहनों का उत्पादन 17 फीसद घटा है और टाटा मोटर्स ने इस तिमाही में तीसरी बार उत्पादन में कटौती की बात कही है। इसकी वजह यह है कि बिक्री में भारी गिरावट आई है।

ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनियों का मानना है कि भारत में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग तेजी से घट रही है, जो आर्थिक मंदी का बड़ा संकेत है। पिछले कुछ महीनों में मांग घटने की रफ्तार तेज हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की बेहद कमजोर माली हालत है। उनके पास पास ऑटो डीलरों और कार ग्राहकों को कर्ज देने के लिए फंड नहीं हैं। दरअसल मुख्य धारा के बैंक केवल उन्हीं ग्राहकों को लोन देने हैं, जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। देश में ऐसे लोग कम ही हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग एनबीएफसी से लोन लेकर कार या मोटरसाइकिल खरीदते हैं। पिछले कुछ महीनों से कर्ज का यह स्रोत भी सूख गया है।

मलेशिया पर जाकिर नाइक को भारत को सौंपने का बढ़ा दबाव

कुआलालंपुर, एएनआइ : दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाने वाले विवादास्पद मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक को मलेशिया में रहने वाले हिंदुओं की निष्ठा पर सवाल उठाना महंगा पड़ सकता है। मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री एम कुलासेगरन ने जाकिर नाइक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए उसे भारत के हवाले करने को कहा है।

कुलासेगरन ने एक बयान में कहा, 'नाइक एक बाहरी व्यक्ति है, जो एक भगोड़ा है और उसे मलेशियाई इतिहास के बारे में ना के बराबर जानकारी है, इसलिए उसे मलेशियाई लोगों को नीचा दिखाने जैसा विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।' मंत्री ने कहा कि जाकिर नाइक का यह बयान किसी भी तरह से मलेशिया के स्थायी निवासी होने के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है।

इस मुद्दे को अगली कैबिनेट बैठक में उठाया जाएगा। हाल ही में जाकिर नाइक ने बयान दिया था कि मलेशिया में रहने वाले हिंदू मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद से ज्यादा नरेंद्र मोदी के वफादार हैं। कुलासेगरन ने जाकिर नाइक की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह मलेशिया के बहु-नस्लीय और बहु-धार्मिक

विवादास्पद मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक। फाइल फोटो

समाज में दरार पैदा करना चाहता है ताकि मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल कर यहां मौज करता रहे। उन्होंने कहा कि नाइक मलेशिया के कर दाताओं के पैसे पर यहां मौज कर रहा है। उन्होंने कहा, 'क्या मलेशिया के लोगों को जाकिर नाइक नामक व्यक्ति पर विभाजित होना चाहिए?' बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद एक बार पहले नाइक के प्रत्यर्पण से इनकार कर चुके हैं, पर इस बार मलेशिया में नाइक का विरोध बहुत बढ़ गया है। भारत से भागने के बाद से जाकिर नाइक मलेशिया में रह रहा है।

न्यूयॉर्क चर्च के खिलाफ एक दिन में बाल यौन शोषण के 70 मुकदमे !

न्यूयॉर्क, रायटर: अमेरिका में 70 से ज्यादा लोगों ने रोमन कैथलिक चर्च के खिलाफ मुकदमा दायर कर कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों ने याचिका में बचपन में पादरियों द्वारा किए गए यौन शोषण की आपबीती बयां की है और बताया है कि किस तरह से चर्च के बड़े पदाधिकारी पादरियों के कृत्यों पर पर्दा डाला करते थे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में बाल यौन शोषण के खिलाफ नया कानून बुधवार से ही प्रभाव में आया है। इस कानून के तहत दशकों पुरानी घटनाओं के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक मुकदमा ब्वाय स्काउट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ दायर हुआ है। यह संगठन बच्चों के यौन शोषण के लिए बदनाम है। एक महिला ने फायनेंसर जेफ्री एपस्टीन के खिलाफ भी याचिका दी है। महिला जब कम उम्र की थी तब एपस्टीन ने उसका यौन शोषण किया था। एपस्टीन पर इस तरह के दर्जनों आरोप थे। उसने हाल ही में न्यूयॉर्क की जेल में आत्महत्या कर ली है। महिला ने मुकदमे के लिए अर्जी तब दी थी जब एपस्टीन जिंदा था। लॉ फर्म विट्ज एंड एएमपी लक्जेनबर्ग ने कहा है कि उसके पास बाल यौन शोषण के 1,200 से ज्यादा मामले हैं।

हांगकांग में धीमा पड़ा आंदोलन, विमानों की आवाजाही शुरू

- हांगकांग में दस हफ्ते से चल रहे चीन विरोधी प्रदर्शनों से वहां की गतिविधियां अस्त-व्यस्त हो गई हैं
- इस आंदोलन का फिलहाल कोई नेता नहीं है, आंदोलन के एक-दो दिन बाद फिर से तेज होने की उम्मीद

हांगकांग, एएफपी/एपी : हांगकांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हालात को नियंत्रित कर लिया गया है और बुधवार सुबह से बड़ी संख्या में विमान समयानुसार रवाना हो रहे हैं। सोमवार को लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारी हवाई अड्डे में घुस गए थे और उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को ठप कर दिया था। इसके कारण वहां विमानों का आवागमन रुक गया। मंगलवार को आंदोलनकारियों के दो टर्मिनलों पर कब्जा कर लेने से सैकड़ों उड़ानें रद करनी पड़ीं। चीन ने कहा है कि आंदोलनकारी आतंकियों जैसे कृत्य कर रहे हैं। उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अनुसार हांगकांग के नजदीक चीनी अर्धसैन्य बलों का जमावड़ा हो रहा है। माना जा रहा है कि आंदोलन शांत नहीं हुआ तो चीन हांगकांग में कार्रवाई कर सकता है।

हांगकांग में दस हफ्ते से चल रहे चीन विरोधी प्रदर्शनों से वहां की गतिविधियां अस्त-व्यस्त हो गई हैं। दुनिया के इस प्रमुख आर्थिक केंद्र में पूरी रात आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलनकारी सुरक्षा बलों के साथ आंख-मिचौली करते हुए न सिर्फ रास्ते रोक रहे हैं बल्कि मौका लगने पर पुलिस पर हमला कर उन्हें दौड़ा भी रहे हैं। अपनी बात अंतरराष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाने के लिए आंदोलन रविवार से हवाई अड्डे के आसपास सक्रिय थे लेकिन सोमवार को वे हवाई अड्डे में घुस गए और तमाम यात्रियों को आगे बढ़ने

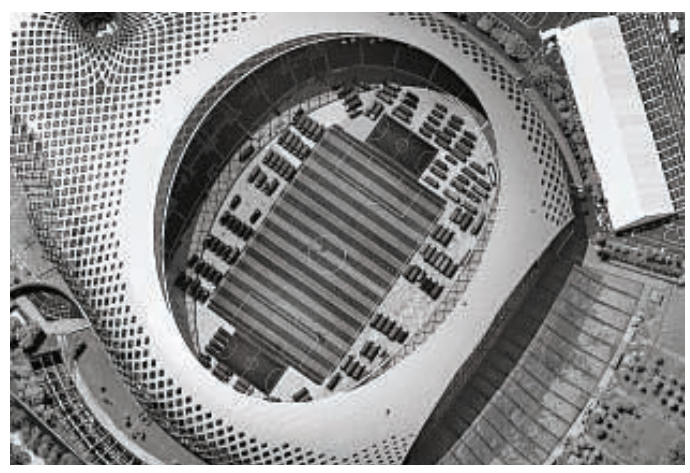
चीन के शेंझेन शहर में स्थित शेंझेन बे स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर मौजूद चीनी सैन्य वाहन और उपकरणों की सेटेलाइट तस्वीर। शेंझेन शहर की सीमा हांगकांग से लगती है। एपी

से रोक दिया। मंगलवार को दंगारोधी पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और घंटों की मशक्कत के बाद टर्मिनल खाली कराए जा सके। इसके बाद बुधवार सुबह से विमानों की उड़ान शुरू हो गई। हवाई अड्डे की ज्यादातर व्यवस्थाएं सामान्य हो गई हैं। प्रत्यक्षदर्शी यह भी बता रहे हैं कि कई दिनों के लगातार आंदोलन के बाद आंदोलनकारी युवा थक गए हैं और अब वे आराम कर रहे हैं। एक-दो दिन बाद वे फिर से एकजुट होकर आंदोलन को को तेज करेंगे। इस आंदोलन का फिलहाल कोई नेता नहीं है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पर होने वाले आह्वान से आंदोलन की रूपरेखा बनती है और हजारों युवा गुरिल्ला ढंग से सड़कों पर उतरकर सक्रिय हो जाते हैं। ये आंदोलनकारी समाज के हर वर्ग से आते हैं।

चीन के दबाव पर हांगकांग ने दो पायलटों को बर्खास्त किया

हांगकांग, एएफपी : हांगकांग के हवाईअड्डे पर लोकतंत्र समर्थकों का समर्थन करने के आरोप में विमानन कंपनी कैथे पैसिफिक ने दो पायलटों को बर्खास्त कर दिया। कार्रवाई को लेकर चीन का दबाव था। एयरलाइन की ओर से कहा गया कि एक पायलट पर वर्तमान में कानूनी कार्रवाई चल रही है, जबकि दूसरे पर अगस्त में फ्लाइट के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप है। कैथे पैसिफिक के मुख्य कार्यकारी रूपर्ट हॉग ने सोमवार को कर्मचारियों को चेतावनी दी कि विरोध-प्रदर्शन का साथ देने वालों को कंपनी से निकाल दिया जाएगा। कंपनी इससे पहले भी अपने कर्मचारियों को अलग-अलग आरोप लगाकर निकाल चुकी है।

न्यूज गैलरी

भारत ने यूएन को दिया सात करोड़ का योगदान

संयुक्त राष्ट्र : भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के निवासी समन्वय प्रणाली के लिए विशेष उद्देश्य ट्रस्ट फंड (एसपीटीएफ) में दस लाख डॉलर (करीब सात करोड़ 13 लाख रुपये) का योगदान दिया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। अकबरूद्दीन के अनुसार, 'यह एक अहम योगदान है। भारत, संयुक्त राष्ट्र की विकास प्रणाली में सुधार के लिए ठोस योगदान देकर खुश है।' संयुक्त राष्ट्र का यह फंड सभी भागीदार सदस्य देशों के योगदान, वित्तीय लेन-देन का पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से लेखा-जोखा रखने के लिए बनाया गया है। एसपीटीएफ की वेबसाइट पर भारत के इस अहम योगदान को दर्शाया गया है। (प्रेट्र)

सैयद अकबरूद्दीन की फाइल फोटो।

पाक में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दीवार गिरी, पांच मरे

पेशावर : उत्तरी पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान दीवार गिरने से बुधवार को कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना गिलगित-बाल्टिस्तान के एक हेलीपैड पर हुई जहां देश के 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पाकिस्तान सेना की निगरानी में एक कार्यक्रम चल रहा था। अधिकारियों ने कहा कि हेलीपैड परिसर की एक दीवार गिरने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को गिलगित के संयुक्त सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (प्रेट्र)

ऑस्ट्रेलिया ने कहा- भारत से रक्षा संबंध मजबूत करेंगे

मेलबर्न : ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह भारत के साथ गहरे रक्षा संबंधों को बनाने और रणनीतिक हिंद महासागर पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम करेगा। जहां चीन तेजी से अपने पैरों को फैला रहा है। सोमवार को पर्थ में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई इंडो-पैसिफिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, आष्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक खुद को प्रशांत महासागर का देश माना है। हमने प्रशांत महासागर में रणनीतियां तो बनाईं पर हिंद महासागर की ओर कभी ध्यान नहीं दिया।' उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है और एक नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहा है। जो इसके आकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत करेगा। (प्रेट्र)

ट्रंप ने कहा- भारत और चीन को नहीं लेने देंगे विकासशील देश का फायदा

बिगड़े बोल ▶ अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा - दोनों देश अब निकल चुके इस श्रेणी से

डब्ल्यूटीओ द्वारा उचित कदम नहीं उठाने पर संगठन छोड़ने की दी धमकी

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से चल रहे ट्रेड वार और अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए अधिक शुल्क की खुन्नस डब्ल्यूटीओ के जरिये निकाली है। ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भारत व चीन अब विकासशील देश नहीं हैं।

फिर भी दोनों देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से मिले इस दर्जे का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने भविष्य में ऐसा ना होने देने की बात की है। ट्रंप ने दुनिया के इस शीर्ष संगठन को धमकी भी दी कि अगर उसने भारत और चीन को विकासशील देशों को मिलने वाले फायदे लेने से नहीं रोका, तो वह डब्ल्यूटीओ से ही बाहर हो जाएगा। 'अमेरिका प्रथम' नीति के पैरोकार ट्रंप अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाने के लिए भारत की आलोचना करते रहे हैं। उधर, चीन के साथ उनके देश का व्यापार युद्ध चल रहा है। अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फाइल

पर दंडात्मक शुल्क लगाए जाने के बाद चीन ने भी ऐसा ही जवाबी कदम उठाया है। गौरतलब है कि इस वर्ष जून में अमेरिका ने अपने जीएसपी फायदे से भी इसी तर्क के साथ बाहर कर दिया था, कि जीएसपी का फायदा विकासशील देशों के लिए है और भारत अब उससे ऊपर उठ चुका है।

पेंसिलवेनिया में एक सभा को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, 'भारत व चीन डब्ल्यूटीओ से मिले विकासशील देश के दर्जे का वर्षों से फायदा उठाते आए हैं। इसका नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है।' जेनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो देशों के बीच होने वाले व्यापार को नियंत्रित करता है। जुलाई में डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ से यह बताने को कहा था कि वह कैसे किसी देश को विकासशील देश का दर्जा देता है। इस कदम का मकसद चीन, तुर्की ओर भारत जैसे देशों को इस व्यवस्था से अलग करना है जिन्हें वैश्विक व्यापार नियमों के तहत रियायतें मिल रही हैं। हालांकि उस वक्त अमेरिका ने सीधे भारत का नाम नहीं लिया था। ट्रंप ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों (यूएसटीआर) को अधिकार देते हुए कहा है कि अगर कोई विकसित अर्थव्यवस्था डब्ल्यूटीओ की खामियों का लाभ उठाती है, वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करे। ट्रंप ने पहले भी कई बार डब्ल्यूटीओ पर अमेरिका के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन को डब्ल्यूटीओ के नियमों को मानने की जरूरत नहीं।

रूस ने डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व को बताया खतरे में

मॉस्को, रायटर : रूस ने बुधवार को कहा कि अगर अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उसे छोड़कर चली जाती हैं, तो उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। रूस की सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डब्ल्यूटीओ जैसे किसी संगठन को छोड़कर चली जाए, तो संगठन के अस्तित्व का खतरे में पड़ना बेहद स्वाभाविक है। गौरतलब है कि मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ छोड़ने की धमकी दी है। पिट्सबर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वर्षों से संगठन की नाइंसाफी झेल रहा है। ऐसा अब आगे नहीं चलेगा। ट्रंप ने कहा कि यदि डब्ल्यूटीओ कुछ देशों को फायदा पहुंचाने वाली कमियों को दूर करने में विफल रहता है, तो फिर अमेरिका को उसकी जरूरत नहीं है।

सांसदों का एक वर्ग चाहता है ब्रेक्जिट को पटरी से उतारना

- विरोधी सांसदों पर बरसे जॉनसन, लगाया ईयू से मिले होने का आरोप
- कहा कि ये लोग बिना शर्त के यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का अलगाव चाहते हैं

लंदन, एएफपी रायटर : ब्रेक्जिट के सवाल पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रसेल्स में बैठे यूरोपीय यूनियन नेतृत्व और ब्रिटिश सांसदों के एक वर्ग को आड़े हाथों लिया है। कहा है कि ये लोग बिना शर्त के यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन का अलगाव चाहते हैं।

यह ब्रिटेन के खिलाफ भयानक गठजोड़ है, जो ब्रिटेन का भला नहीं चाहता। ये वही सांसद हैं जो संसद में ब्रेक्जिट का विरोध कर रहे हैं। जॉनसन ने साफ किया कि वे ऐसे लोगों के कारण ब्रेक्जिट को पटरी से नहीं उतरने देंगे, 31 अक्टूबर को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा, भले ही प्रक्रिया बिना शर्त के पूरी करनी पड़े। जॉनसन ने यह बात फेसबुक लाइव पर कही है।

जॉनसन ने कहा, ब्रेक्जिट विरोधी सांसदों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वे नहीं चाहते कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो, इसलिए वे ब्रेक्जिट के किसी भी सरकारी प्रस्ताव का विरोध करेंगे। लेकिन हर ब्रेक्जिट की प्रक्रिया को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ब्रेक्जिट से संबंधित सरकार का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में तीन बार गिर चुका है। इसी के कारण ब्रेक्जिट प्रक्रिया लंबी खिंच रही है और 2016 के बाद से देश असमंजस की स्थिति में हैं। इन्हीं परिस्थितियों में टेरीजा मे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटेन की शासन प्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने देश की राजनीतिक परिस्थिति पर अफसोस जताया है।

तीन सितंबर से बैठेगी ब्रिटिश संसद

ब्रेक्जिट के लिए दिनों उलटी गिनती शुरू हो गई है। 78 दिन बाद यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने चेतावनी दे रखी है कि अगर ब्रिटेन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया तो उससे एकतरफा संबंध विच्छेद कर दिए जाएंगे। ग्रीष्मावकाश के बाद ब्रिटिश संसद के सत्र का कार्यक्रम घोषित हो गया है। तीन सितंबर को दोबारा संसद बैठेगी, तभी ब्रेक्जिट से संबंधित प्रस्ताव पर नई सरकार का इम्तिहान होगा।

रो खन्ना 'पाकिस्तान कांग्रेशनल कॉकस' में शामिल हुए

- भारतीय-अमेरिकी सांसद सिलिकान वैली से निर्वाचित हैं
- अमेरिका-भारत कॉकस के सदस्य के तौर पर की थी कश्मीर में आतंकी हमले की निंदा

वॉशिंगटन, प्रेट्र : भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना 'कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस' में शामिल हो गए हैं। दो बार के डेमोक्रेट सांसद और सिलिकॉन वैली से निर्वाचित खन्ना कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस में शामिल होने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी हैं। इस कॉकस की सह अध्यक्षता डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद शीला जैक्सन ली और रिपब्लिकन पार्टी के जिम बैंक्स करते हैं। जैक्सल ली और खन्ना (42) दोनों भारत और भारतवंशियों पर कांग्रेशनल कॉकस के सदस्य हैं, जो अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' में किसी देश विशेष का सबसे बड़ा कॉकस है।

पिछले दो साल में हॉउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विदेश नीति और सुरक्षा मामलों पर अपनी छाप छोड़ने वाले खन्ना पिछले महीने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के अमेरिका दौरे के बाद पाकिस्तानी कॉकस में शामिल हुए हैं।

खन्ना ने कहा, 'मुझे अमेरिका-भारत कॉकस का सदस्य होने पर गर्व है। मैंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा के लिए लाए गए विधेयक और भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों को मजबूत करने का समर्थन किया। साथ ही मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान में स्थायित्व लाने के

रो खन्ना। फाइल

लिए भारत और पाकिस्तान सहित क्षेत्र के सभी देशों से संपर्क करना अहम है, ताकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो सके।' खन्ना के इस फैसले पर अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत असद एम खान ने उन्हें धन्यवाद दिया है।

ज्वालामुखी में विस्फोट...

हिंदमहासागर में स्थित अफ्रीकी द्वीप रीयूनियन के ज्वालामुखी पिटोन डी ला फोरनेइज में बुधवार को विस्फोट हो गया, जिसके बाद लावा की लपटें दूर आसमान तक फैल गईं। यह सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें पिछला विस्फोट अगस्त 2006 में शुरू होकर जनवरी 2007 में समाप्त हुआ था। एएफपी

वियतनाम के इलाके में घुसा चीन का जहाज, बढ़ सकता तनाव

हनोई, एएफपी : महासागरों में चीन अपनी पैठ बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। साउथ चाइन सी पर तो वह अपना दावा ठोकता ही है और हिंद महासागर पर भी अपनी पैठ बना रहा है। अपना प्रभुत्व जताने के लिए चीन आए दिन विवादित इलाकों में अपने जहाज भेजता रहता है। हाल ही में चीन का एक सर्वेक्षण पोत दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के इलाके में घुस गया। हाल ही के समय में दूसरी बार एसी घटना के सामने आने से बीजिंग और हनोई के बीच विवाद और भड़कने की आशंका बढ़ गई है।

चीन पर विवादित स्थल में युद्धपोतों को तैनात करने, मछली पकड़ने वाले जहाजों को तैनात करने का आरोप लगता रहा है। साउथ चाइना सी चीन और अमेरिका के बीज के विवाद का भी मुद्दा है।

अमेरिका हमेशा यहां के रास्ते से व्यापार की स्वतंत्रता की बात करता है। पिछले महीने भी एक चीनी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जहाज ने स्प्रैटली द्वीपों के पास पानी में प्रवेश किया था, जिस इलाके पर वियतनाम अपना दावा करता है। हनोई ने बताया कि विरोध के बाद भी यह जहाज काफी समय तक यहां रहा। पिछले हफ्ते इसके लौटने के बाद अब फिर से घुसपैठ की गई है।

रंग लाई मेहनत

शंघाई को नॉलेज सिटी के तौर पर उभारना है अगला लक्ष्य, हर साल दुनिया भर से करीब 80 लाख पर्यटक यहां आते हैं

अमेरिका और यूरोप के शहरों को मात दे रहा शंघाई

राजीव सचान, शंघाई

एक समय बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंबई को शंघाई जैसा बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बीच चीन की आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा यह शहर विकास के पैमाने पर इतना आगे निकल गया है कि वह न्यूयॉर्क और शिकागो के साथ यूरोप के कई नामी शहरों से होड़ ले रहा है। अनोखे शिल्प से लैस गगनचुंबी भव्य इमारतें, साफ-सुथरी सड़कें, भूमिगत रेलसेवा के सघन संजाल के साथ बेहतरीन एवं अनुशासित परिवहन व्यवस्था और देशी-विदेशी पर्यटकों को दंग करने वाले नाना केंद्रों से लैस शंघाई की छटा देखकर भारत-चीन मीडिया फोरम में शिरकत करने आए दल को मनमोहन सिंह का अधूरा वादा याद आ गया। इसके साथ ही यह जरूरत भी रेखांकित हो उठी कि चीन सरीखी तरक्की करने के लिए भारत को कितना कुछ करना बाकी है। शंघाई के चमत्कृत करने वाले विकास के बारे में बताते और इस दौरान मुंबई का उल्लेख करते हुए शंघाई पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन (एसपीडीए) के उपाध्यक्ष ताओ शूमिंग ने भारतीय मीडिया दल को बताया कि हमारा अगला लक्ष्य शंघाई को नॉलेज सिटी के तौर पर उभारना और दुनिया भर के छात्रों को अध्ययन के लिए आकर्षित करना है।

आर्थिक के साथ ही सांस्कृतिक तौर पर भी समृद्ध हो रहा शंघाई प्रतीकात्मक

शंघाई आर्थिक-व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही सांस्कृतिक तौर पर भी समृद्ध हो रहा है और इसका प्रमाण इन दिनों शंघाई में आयोजित चीन-ब्राजील विजुअल फेस्टिवल के साथ शंघाई पुस्तक मेला भी दे रहा है। प्रकाशन उद्योग का गढ़ बन चुके शंघाई के इस सालाना पुस्तक मेले में यूरोप-अमेरिका के बड़े प्रकाशन और नामी लेखक भागीदारी कर रहे हैं।

ऐसे समारोहों और स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के कारण शंघाई इन दिनों देशी-विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। ताओ शूमिंग के मुताबिक हर साल दुनिया भर से करीब 80 लाख पर्यटक शंघाई आते हैं। चीन के विभिन्न हिस्सों से आने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या भी छह करोड़ सालाना तक पहुंच जाती है।

घरेलू पर्यटकों की यह संख्या चीन में पर्यटन की बढ़ती चाह के साथ आम चीनी नागरिकों की समृद्धि को भी बयान करती है। ज्ञात हो कि दुनिया भर में चीनी पर्यटकों की हिस्सेदारी और उनकी ओर से की जाने वाली खरीदारी तेजी के साथ बढ़ रही है। इस कारण कई यूरोपीय देश चीनी पर्यटकों को लुभाने के लिए खास आयोजन करने लगे हैं।

कार से पहले नीलामी में खरीदना पड़ता है उसका रजिस्ट्रेशन

शंघाई को वायु प्रदूषण से मुक्त करने और ट्रैफिक जाम की समस्या से उबारने के उपायों की जानकारी देते हुए ताओ शूमिंग ने बताया कि निजी कारों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए कार प्लेट यानी रजिस्ट्रेशन की नीलामी होती है। इसके चलते कार वही खरीद सकता है जिसने पहले कार प्लेट हासिल कर ली हो या फिर जिसकी पुरानी कार चलाने लायक न रह गई हो। इस नियम के चलते कार प्लेट की नीलामी ऊंचे दामों पर होती है। कई साधारण कारों की तुलना में कार प्लेट की नीलामी में खरीद कहीं महंगी पड़ती है। यह नियम चीन के कई बड़े शहरों में भी लागू है। चूंकि ग्रामीण और कम ट्रैफिक वाले इलाके इस नियम से मुक्त हैं इसलिए कार निर्माता कंपनियों को भी परेशानी नहीं है।

पाकिस्तानी बहन ने की मोदी के लिए नोबेल पुरस्कार की दुआ

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी बहन चाहती हैं कि उनहें नोबेल पुरस्कार मिले। 24 साल से मोदी को राखी बांधते आ रही कमर जहां का मानना है कि मोदी दुनिया में शांति व विकास के लिए अहम कदम उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक व बाद में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में गुजरात में काम कर रहे थे तब कमर ने उन्हें राखी बांधते हुए उनके राज्य का मुख्यमंत्री बनने की दुआ की। मोदी ने हंसते हुए कहा था कि उन्हें कार्यकर्ता ही रहने दें राजकाज उन्हें रास नहीं आता है। गुजरात की राजनीति का पहिया ऐसा घुमा कि विपरीत हालात में भाजपा को बचाने के लिए मोदी को राज्य की कमान संभालनी पड़ी और मोदी ने अपने ही अंदाज में राज्य के विकास को गति दी। कमर बताती हैं कि एक रक्षा बंधन पर उन्होंने राखी बांधते हुए उनके लिए देश का प्रधानमंत्री बनने की दुआ की तो मोदी मुस्कुराने लगे। मूल रूप से कराची निवासी कमर वर्षों पहले अपने परिवार के साथ अहमदाबाद आकर बस गईं। इस रक्षा बंधन पर प्रधानमंत्री के लिए नोबेल पुरस्कार की दुआ मांगते हुए कमर ने कहा कि उनका मानना है कि जब सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है।

पाक में बसे भाईयों से मिलने के लिए तरसती हैं बहनें: भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद सिंध के चेल्लार गांव से आकर गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, पाटण में आकर बसी कई बहनें ऐसी हैं जो अपने भाईयों को राखी बांधने के लिए पाक नहीं जा सकती। थराद के शिवनगर में बसे दो हजार परिवारों की कई बहनें राखी के दिन अपने भाईयों की कलाई पर राखी नहीं बांध सकतीं। लीला शंकरलाल पुरोहित कई दशक से नहीं जा सकी हैं। दुर्गाबेन त्रिवेदी, जीवाबेन पुरोहित ऐसी कई महिलाएं हैं जो भाई का चेहरा देखने को तरस जाती हैं। 1978 में उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। पाक उन्हें वीजा नहीं देता।

गेल की धमाकेदार विदाई

- अपने आखिरी मैच में बनाए 41 गेंद में 72 रन
- विंडीज ने बनाए 22 ओवर में दो विकेट पर 158 रन

अर्धशतक पूरा करने के बाद क्रिस गेल • एपी

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क : यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने जब साल 1999 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह बायें हाथ का बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर अपनी धाक भी जमा पाएगा। लेकिन, अब इस विस्फोटक सलामी बल्लेबाज की पारियां उनके देशवासियों को देखने को नहीं मिलेगी। यह संयोग ही है कि गेल ने अपने वनडे करियर का आगाज भी भारत के खिलाफ टोरेंटो में किया था जहां वह रोबिन सिंह द्वारा एक रन पर आउट हो गए थे और अब गेल ने अपने अंतराष्ट्रीय करियर की आखिरी पारी भी भारत के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल के मैदान पर खेली। कैरेबियाई बल्लेबाज गेल ने अपने विदाई मैच में 41 गेंदों में विस्फोटक 72 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने आठ चौके और पांच छक्के भी जड़े। उनकी इस पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने बुधवार को सीरीज के तीसरे वनडे में खबर लिखे जाने तक 22 ओवर में दो विकेट पर 158 रन बनाए। गेल का अच्छा साथ लुइस ने निभाया और उन्होंने 29 गेंदों का सामना करते हुए 43 रन बनाए जिसमें पांच चौके और तीन शानदार छक्के जड़े। शाई होप (नाबाद 19) और शिमरोन हेटमायर (नाबाद 18) क्रीज पर मौजूद थे। हालांकि बारिश ने इस मैच में भी अपना साया नहीं छोड़ा और दो बार बारिश ने इस पारी में अपना खलल डाला।

गेल जैसा कोई नहीं: गेल ने वनडे विश्व कप के दौरान कहा था कि भारत के खिलाफ सीरीज उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की आखिरी सीरीज होगी लेकिन वह दुनिया भर की टी-20 लीग में खेलना जारी रखेंगे। गेल भारत के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में 300 वनडे खेलकर अपने देश के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने वाले क्रिकेटर बने थे। इसके साथ ही वह हमवतन ब्रायन लारा (10348 रन) को पीछे छोड़ते हुए अपने देश के लिए वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे।

जैसा वनडे, वैसी जर्सी : हालांकि गेल ने जब दूसरे वनडे में अपने करियर 300वां वनडे खेला था तो उन्होंने जर्सी 300 नंबर की जर्सी पहनी थी। अब तीसरे वनडे में उन्होंने 301वां वनडे मैच खेला तो उन्होंने इसी नंबर की जर्सी पहनी।

छह ओवर 101 रन : वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने सीरीज बचाने और मौसम की आंख मिचौली को देखते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अपने अंतिम एकादश में शेल्डन कॉटरेल और ओशाने थॉमस को बाहर कर कीमो पॉल और फेबियन एलेन को शामिल किया। वेस्टइंडीज के दोनों सलामी बल्लेबाजों गेल और लुइस ने भारतीय गेंदबाजों को संभलते हुए खेला और शुरुआती चार ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए, जिसमें दो मेडन ओवर फेंके थे। इसके बाद गेल और लुइस ने गियर बदला और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों ने अगले छह ओवर में ही में 101 रन जोड़ दिए और टीम ने पावरप्ले के शुरुआती 10 ओवर में 114 रन कूट डाले। इस दौरान दोनों ने मिलकर आठ छक्के भी जड़े। 11वें ओवर में युजवेंद्रा सिंह चहल (1/21) ने लुइस को पवेलियन भेजकर इस साझेदारी को तोड़ा। दोनों ने पहले विकेट के लिए 66 गेंदों में 115 रनों की विस्फोटक साझेदारी निभाई। इसके बाद अगले ओवर में गेल तेज गेंदबाज खलील अहमद (1/43) की गेंद को उठाने के चक्कर में कोहली को सीधा कैच दे बैठे।

दोस्त गेल को खास विदाई : गेल जब आउट हुए तो भारतीय टीम के कप्तान कोहली ने अपने दोस्त गेल को उनके अंदाज में गले मिलकर विदाई दी। कोहली के अलावा भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों ने भी तालियों के साथ इस दिग्गज खिलाड़ी को मैदान से बाहर भेजा जबकि स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों ने उन्हें खड़े होकर उनका अभिवादन किया।

वनडे में एक वर्ष में सर्वाधिक छक्के

छक्के	खिलाड़ी	वर्ष
58	एबी डिविलियर्स	2015
56	क्रिस गेल	2019
49	शाहिद अफरीदी	2002

वनडे में भारत के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले कैरेबियाई बल्लेबाज

रन	खिलाड़ी
1357	डेसमंड हेंस
1334	क्रिस गेल
1319	शिवनारायण चंद्रपॉल

गेल का वनडे करियर

मैच	301
नॉटआउट	17
रन	10480
सर्वश्रेष्ठ	215
गेंदें खेलीं	12019
शतक	25
अर्धशतक	54
चौके	1128
छक्के	331
कैच	124
विकेट	167
सर्वश्रेष्ठ	5/46

क्रिकेटर व इंसान के रूप में सुधार करना चाहता हूं : पंत

नजरिया

- कहा, मेरे लिए प्रत्येक मैच महत्वपूर्ण है
- हर बार बड़ी पारी खेलना चाहता हूं

पोर्ट आफ स्पेन, प्रेट्र : रिषभ पंत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सीखने के दौर से गुजर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वह प्रत्येक दिन खुद में क्रिकेटर और इंसान के रूप में सुधार करना चाहते हैं।

भारत का अगले छह महीने का कार्यक्रम काफी व्यस्त है और पंत से पूछा गया कि वह इस समय को कैसे देखते हैं तो उन्होंने कहा, 'मेरे लिए प्रत्येक मैच महत्वपूर्ण है और यह सिर्फ अगले छह महीने का मामला नहीं है। मेरे जीवन का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है और मैं खिलाड़ी और इंसान के रूप में सुधार करना चाहता हूं। मैं इसे लेकर उत्सुक हूं।' पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में आकर्षक अर्धशतक जड़ा, लेकिन क्रीज पर पैर जमाने के बावजूद विकेट गंवाने के उनके तरीके के कारण उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा है। पंत ने कहा, 'व्यक्तिगत रूप से मैं हर बार बड़ी पारी खेलना चाहता हूं, लेकिन मैं जब भी क्रीज पर उतरता हूं तो हर समय मेरा ध्यान इस पर नहीं होता। क्रीज पर जमने के बाद मैंने विकेट गंवाया, क्योंकि मैं सामान्य होकर खेलना चाहता हूं, सकारात्मक क्रिकेट जिससे मेरी टीम को मैच जीतने में मदद मिले।' इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें खुशी है कि टीम प्रबंधन प्रत्येक खिलाड़ी का समर्थन कर रहा है और उन्हें पर्याप्त मौके दे रहा है। 21 साल के इस खिलाड़ी ने कहा, 'हम प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हम टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। सभी को पर्याप्त मौके मिल रहे हैं। सभी अपनी स्थिति को लेकर आश्वस्त हैं क्योंकि टीम प्रबंधन उनका समर्थन कर रहा है।' युवा विकेटकीपर बल्लेबाज पंत ने कहा कि विश्व कप सेमीफाइनल से बाहर होना निराशाजनक था, लेकिन यह आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने कहा, 'विश्व कप सेमीफाइनल हारने के बाद हमें बुरा लग रहा था, लेकिन पेशेवर खिलाड़ी के रूप में हमें पता है कि हम खराब नहीं खेले। यह सिर्फ 45 मिनट (न्यूजीलैंड के खिलाफ) का खराब क्रिकेट था।'

114 रन वेस्टइंडीज की टीम ने शुरुआती 10 ओवर में बनाए। यह किसी भी टीम द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन है

08 छक्के वेस्टइंडीज की टीम ने शुरुआती 10 ओवर में जड़े। यह किसी भी टीम द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक छक्के हैं

2007 में भारतीय टीम क्वींस पार्क ओवल में आखिरी वनडे मैच हारी थी। यह हार उसे श्रीलंका से मिली। इसी मैदान पर विंडीज ने आखिरी बार वनडे 2008 में श्रीलंका के ही खिलाफ जीता था

वेस्टइंडीज दौरे पर बने रहेंगे मैनेजर सुनील सुब्रहमण्यम

सख्ती

- भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों से किया था दुर्व्यवहार
- सीओए प्रमुख ने माफीनामे स्वीकार कर टीम के साथ बने रहने को कहा

नई दिल्ली, प्रेट्र : वेस्टइंडीज में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार करने के मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशासनिक मैनेजर सुनील सुब्रहमण्यम को स्वदेश बुलाने के अपने फैसले को बीसीसीआइ ने बदल दिया है। सुब्रहमण्यम द्वारा अधिकारियों से बिना किसी शर्त के माफी मांगने के बाद बोर्ड ने अपना फैसला बदल दिया है।

भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में सुब्रहमण्यम को बीसीसीआइ ने वेस्टइंडीज दौरे के बीच में ही पहली फ्लाइट पकड़कर स्वदेश लौटने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने उनके माफीनामे के बाद उन्हें फटकार लगाई है और टीम के साथ बने रहने को कहा है। विनोद राय ने कहा कि सुनील सुब्रहमण्यम नहीं जानते थे कि यह अनुरोध भारत सरकार की ओर से था। मैंने शुरू में उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया था, लेकिन शाम में उनके बिना शर्त माफीनामे के बाद मैंने उन्हें पूरे दौर तक टीम के साथ रहने देने का फैसला किया। मैंने उनका माफीनामा स्वीकार कर लिया है जिससे वह अब इस दौरे पर टीम के साथ बने रहेंगे। इससे पहले सुब्रहमण्यम के अतिशीघ्र वापसी के लिए फ्लाइट टिकट भेजी गई थीं। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने बताया था कि सरकार के अनुरोध के बाद भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) अधिकारियों ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के साथ एक वीडियो शूट करने के लिए सुब्रहमण्यम से मदद के लिए संपर्क किया था लेकिन उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्हें मुंबई में बीसीसीआइ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राहुल जौहरी के समक्ष पेश होना था और अपने दुर्व्यवहार के लिए जवाब देना था।

बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि भारतीय टीम की जल सरंक्षण परियोजना के लिए काफी लंबी शूटिंग करानी थी और उन्हें इसकी देखरेख करनी थी। इस शूटिंग के समाप्त होने पर उन्हें एक ईमेल भेजा गया, जिसमें उन्हें पहली फ्लाइट लेकर वापस लौटने को कहा गया। हालांकि अभी भी यह देखना होगा कि सुब्रहमण्यम को प्रशासनिक मैनेजर के पद के लिए ताजा नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में शामिल होने का मौका मिलेगा या नहीं। उनके नाम को इस पद के लिए छांटा गया है।

तमिलनाडु के पूर्व स्पिनर सुब्रहमण्यम ने गयाना और त्रिनिदाद एवं टोबैगो में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए बिना शर्त माफी की पेशकश की थी। यह भी पता चला है कि सुब्रहमण्यम ने अपने कथित दुर्व्यवहार के लिए तनाव को जिम्मेदार बताया है। अधिकारी ने कहा, अपने माफीनामे में उन्होंने कहा कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी और वह तनाव में थे, जिससे वह इस तरह का व्यवहार कर बैठे। उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन आपको समझना होगा कि यह मामला सरकार के उच्च स्तर के अधिकारियों के पास पहुंच गया है और बीसीसीआइ इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।

धनंजय की फिरकी में फंसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज

श्रीलंका के खिलाफ बनाए पांच विकेट पर 203 रन, अकिला ने 57 रन देकर पांच विकेट झटके, टेलर का अर्धशतक

वाटलिंग का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते धनंजय • एपी

गॉल, एएफपी : श्रीलंकाई स्पिनर अकिला धनंजय के पांच विकेट झटकने से न्यूजीलैंड की टीम ने आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की दो मैचों की सीरीज के पहले मैच के शुरुआती दिन बारिश के कारण खेल रोके जाने तक पांच विकेट गंवाकर 203 रन बनाए। अनुभवी रॉस टेलर ने नाबाद 86 रन की पारी खेलकर अपनी टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

पिछले साल संदिग्ध एक्शन की शिकायत होने के बाद नए एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे धनंजय ने पिछले छह मैचों में चौथी बार एक पारी में पांच विकेट चटकाए। धनंजय ने 22 ओवर में 57 रन पर पांच विकेट लिए। उनके अलावा श्रीलंकाई टीम के किसी भी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली।

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाजों जीत रावल और टॉम लाथम ने 64 रन जोड़कर कीवी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, जिसके बाद धनंजय ने अपनी फिरकी का जादू चलाया। लाथम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे, जो 30 रन बनाने के बाद धनंजय की गेंद पर विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को कैच दे बैठे। केन विलियमसन भी तीन गेंद बाद खाता खोले बिना धनंजय की गेंद को शॉर्ट मिडविकेट पर विरोधी कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के हाथों में कैच दे बैठे। भोजनकाल से पहले के अंतिम ओवर में धनंजय ने बायें हाथ के बल्लेबाज रावल को गुगली पर पहली स्लिप में धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच कराके मेहमान टीम को तीसरा झटका दिया। उन्होंने 33 रन बनाए। भोजनकाल के बाद हालांकि टेलर को हेनरी निकोल्स का अच्छा साथ मिला और दोनों ने 100 रन की साझेदारी निभाई। धनंजय ने निकोल्स की 42 रन की पारी का अंत उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर किया। उन्होंने इसके बाद विकेटकीपर बीजे वाटलिंग को भी एक रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर चाय से पहले न्यूजीलैंड को पांचवां झटका दिया। इस बीच टेलर ने अपना 31वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 131 गेंद की नाबाद पारी में छह चौके लगाए। दिन का खेल खत्म होते समय टेलर के साथ मिशेल सेंटनर (नाबाद 08) क्रीज पर मौजूद थे। श्रीलंका और न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपना पहला मैच खेल रहे हैं।

जर्मनी नहीं जाएंगी दुति

नई दिल्ली, प्रेट्र : विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने की कोशिशों में जुटीं भारत की फर्राटा धाविका दुति चंद ने मंगलवार को कहा कि वह 'तकनीकी दिक्कतों' की वजह से जर्मनी में होने वाली रेस में भाग नहीं ले पाएंगीं।

दुति ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वीजा दिलाने में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी थी। सरकारी दखल के बाद उन्हें वीजा मिल भी गया था। दुति ने मंगलवार को कहा कि सरकार से सारी मदद मिलने के बावजूद वह रेस में भाग नहीं ले पा रही हैं। दुति ने उड़िया भाषा में ट्वीट किया, 'मैं जर्मनी नहीं जा सकूंगी क्योंकि प्रबंधकीय स्तर पर कुछ दिक्कतें हैं। मैं इससे काफी निराश हूं। भारत सरकार इस अप्रत्याशित चूक से वाकिफ है और मुझे पूरा समर्थन दिया है। मैं सरकार की शुक्रगुजार हूं।'

हाल ही में विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बनने वाली 23 वर्षीय दुति ने एआइआइएफ द्वारा स्वीकृत 100 मीटर की रेसों में दो स्वर्ण पदक जीते थे।

आइटीएफ इस्लामाबाद से हटाए मैच : एआइटीए

एआइटीए ने भारत-पाक के बीच तनाव को देखते हुए डेविस कप मुकाबले के लिए तटस्थ स्थान की भी मांग की

नई दिल्ली, प्रेट्र: अखिल भारतीय टेनिस महासंघ (एआइटीए) ने बुधवार को वैश्विक संस्था अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) से कहा कि वे पाकिस्तान के खिलाफ इस्लामाबाद में डेविस कप मुकाबले को या तो स्थगित करें या फिर दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनयिक तनाव को देखते हुए 'स्वतः संज्ञान' लेकर तटस्थ स्थान पर मुकाबला कराएं।

पहले से अधिक आक्रामक रवैया अपनाते हुए एआइटीए ने कहा है कि 14-15 सितंबर को होने वाले एशिया ओसियाना ग्रुप एक मुकाबले के लिए वह तटस्थ स्थान का आग्रह नहीं करेगा, जैसा कि आइटीएफ ने कहा है। एआइटीए चाहता है कि आइटीएफ मौजूदा स्थिति के आधार पर फैसला करे और महासंघ ने साथ ही हैरानी जताई कि वैश्विक संचालन संस्था भारत को आग्रह करने के लिए कह रही है, जबकि इसकी जिम्मेदारी आइटीएफ की है।

आइटीएफ के कार्यकारी निदेशक जस्टिन अल्बर्ट को लिखे पत्र में एआइटीए ने कहा, 'मौजूदा स्थिति में आइटीएफ का निदेशक मंडल संभवतः दो विकल्पों पर विचार करना चाहेगा। पहला, इस डेविस कप मुकाबले को नवंबर/दिसंबर तक स्थानांतरित कर दिया जाए और उम्मीद करते हैं कि तब स्थिति बेहतर हो जाएगी। दूसरा, मौजूदा स्थिति अनुकूल नहीं लग रही इसलिए आपके सुरक्षा सलाहकारों की रिपोर्ट के हमारे नजरिये के अनुसार आइटीएफ का निदेशक मंडल स्वतः संज्ञान लेते हुए आइटीएफ के खर्चे पर इस डेविस कप मुकाबले को तटस्थ स्थान पर कराने का फैसला कर सकता है।'

अल्बर्ट ने इससे पहले ईमेल लिखकर कहा था कि आइटीएफ इस्लामाबाद में मौजूदा सुरक्षा इंतजामों से संतुष्ट है। अल्बर्ट ने कहा था, 'हम हैरान और बेहद चिंतित हैं कि एआइटीए ने अब तक वीजा हासिल नहीं किया है, जबकि वीजा आमंत्रण पत्र 23 जुलाई को मिल गया था। डेविस कप नियमों के अनुसार वीजा आवेदन जरूरतों को पूरा करना मेहमान देश की जिम्मेदारी है।' यह प्रतिक्रिया एआइटीए के ईमेल पर आई थी जिसमें पाकिस्तान की राजधानी में पुनः सुरक्षा जांच की मांग की गई थी। एआइटीए ने कहा कि वह आइटीएफ के जवाब से 'निराश' है। एआइटीएफ के महासचिव हिरण्मय चटर्जी द्वारा आइटीएफ को लिखे पत्र के अनुसार, 'पाकिस्तान का दौरा करने के हमारे इंतजामों को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास वीजा आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय है। अगर आपके पहले से अलग कोई सूचना है तो हमें बताइए।' एआइटीए ने कहा कि आइटीएफ को गौर करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक रिश्ते कम कर दिए हैं और भारतीय उच्चायुक्त को जाने के लिए कहा है। चटर्जी ने कहा, ' जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से तनाव बढ़ गया है। इस्लामाबाद में अब हमारा उच्चायुक्त नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेन सेवा बंद हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच बस सेवा को भी तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। पाकिस्तान में काफी तनाव है। भारतीय विमानों के लिए वायु क्षेत्र को भी बंद किया गया है।'

चटर्जी ने कहा कि एआइटीए और आइटीएफ के सुरक्षा सलाहकारों के बीच शुक्रवार को टेलीफोन पर चर्चा हो सकती है और अगर भारत सुरक्षा इंतजामों और हमारी संबंधित टीमों के बीच चर्चा से संतुष्ट होता है तो सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने कहा, 'अगर एआइटीए संतुष्ट नहीं होता है तो हम आइटीएफ के निदेशक मंडल से आग्रह करेंगे कि इस डेविस कप मुकाबले में सुरक्षा से सबंधित मुद्दे पर हमें अपना पक्ष रखने का मौका दें। अगर आइटीएफ का निदेशक मंडल और डेविस कप समिति बढ़ते तनाव के कारण भविष्य को लेकर शत-प्रतिशत निश्चित नहीं होती है तो निदेशक मंडल के पास अधिकार है कि वह या तो मुकाबले को स्थगित कर दें या इसका आयोजन तटस्थ स्थान पर करें।'

लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ा

लंदन, रायटर : इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी एशेज सीरीज के लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। बुधवार को लॉर्ड्स में लगातार बारिश होती रही जिसकी वजह से पहले दिन एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी।

सुबह मैदान गीला होने के बावजूद खेल शुरू होने के आसार नजर आ रहे थे और अंपायरों ने स्थानीय समय शाम साढ़े तीन बजे खेल शुरू होने की उम्मीद जताई। इसी बीच जोफ्रा आर्चर को क्रिस जोर्डन ने इंग्लैंड की टेस्ट कैप प्रदान करके उनके टेस्ट पदार्पण की औपचारिकता पूरी की, लेकिन टॉस होने से ठीक पहले बारिश फिर शुरू हो गई जिसके बाद दोनों अंपायरों ने दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा की। अब बचे हुए चार दिनों का खेल आधे घंटे पहले शुरू होगा, ताकि पहले दिन बारिश से खराब हुए खेल की भरपाई की जा सके। पांच मैचों की सीरीज में पहला टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। एजबेस्टन में खेले गए पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 251 रनों से शिकस्त दी थी।

भारतीय टीम का दिव्यांग विश्व क्रिकेट सीरीज पर कब्जा

इंग्लैंड को हराकर विजेता ट्रॉफी के साथ भारतीय टीम • ट्विटर

नई दिल्ली, जेएनएन: भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 36 रनों से हराकर पहली टी-20 दिव्यांग विश्व क्रिकेट सीरीज जीत ली। भारत ने इंग्लैंड के न्यू रोड स्टेडियम में खेले गए फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 180 रन का विशाल स्कोर बनाया। भारतीय टीम की ओर से मध्य क्रम के बल्लेबाज आर जी सांटे ने 34 गेंदों पर 53 रन की शानदार पारी खेली। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज केडी फनासे ने 36, विक्रांत केनी ने 29 और एस. महेंद्र ने 33 रनों का योगदान दिया। भारत से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में नौ विकेट पर 144 रन ही बना सकी। भारत के लिए एस गोयत और केडी फांसे ने दो-दो विकेट चटकाए जबकि इंग्लैंड के लिए ए ब्राउन ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। इस खिताबी जीत पर बीसीसीआइ ने उन्हें बधाई दी।

टेनिस डायरी रोजर ने जुआन को हराकर तीसरे दौर में बनाई जगह, विश्व नंबर एक नोवाक ने दूसरे दौर में क्वेरी को सीधे सेटों में दी शिकस्त

सिनसिनाटी में फेडरर व जोकोविक जीते

रोजर फेडरर • एपी

सिनसिनाटी, एएफपी: स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने एटीपी सिनसिनाटी मास्टर्स टूर्नामेंट में आसान जीत दर्ज की

तीसरी वरीय फेडरर ने 2-2 के स्कोर पर एक घंटे के बारिश के खलल के बाद अर्जेंटीना के जुआन इग्नासियो लोंडरो को 6-3, 6-4 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी फेडरर ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। बारिश से मैच देरी से होने के बाद मैंने जीत हासिल की।' गत विजेता और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जोकोविक खराब शुरुआत के बावजूद अमेरिका के सैम क्वेरी को 7-5, 6-1 से शिकस्त देकर तीसरे दौर में पहुंच गए। जोकोविक ने कहा, 'सैम मैच में अच्छा खेल रहा था। उसका सामना करना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले दौर में भी अच्छा करूंगा।' फेडरर और जोकोविक पिछले महीने विंबलडन फाइनल के बाद किसी टूर्नामेंट में पहली बार खेल रहे थे। स्टेन वावरिंका ने एक अन्य मुकाबले में 2017 के चैंपियन ग्रिगोर दिमित्रोव को 5-7, 6-4, 7-6 से हराया। वहीं, अमेरिका के फ्रांसिस टियाफोए ने फ्रांस के गाएल फोंफिलस को 7-6, 6-3 से हरा दिया।

वीनस ने बर्टेंस को किया बाहर : महिला सिंगल्स में वीनस विलियम्स ने दूसरे दौर के मुकाबले में गत चैंपियन किकी बर्टेंस को 6-3, 3-6, 7-6 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 13वीं वरीय जर्मनी की एंजेलिक कर्बर पहले दौर के मुकाबले में एनेट कोंटावेइट से 6-7, 2-6 से हार गईं। इसके अलावा 12वीं वरीय स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिक जब विक्टोरिया अजरेंका के खिलाफ 4-6, 0-1 से पीछे चल रही थीं तो उन्होंने चोट के कारण यह मैच बीच में छोड़ दिया। इससे अजरेंका दूसरे दौर में पहुंच गईं। अमेरिकी खिलाड़ी मेडिसन कीज ने स्पेन की गबाइने मुगुरुजा को पहले दौर में 6-7, 7-6, 6-4 से हरा दिया।

चोटिल डेल पोत्रो अमेरिकी ओपन से बाहर

पोत्रो • फाइल फोटो, ट्विटर

न्यूयॉर्क, एएफपी: पूर्व चैंपियन अर्जेंटीना के जुआन मार्टिन डेल पोत्रो दायें घुटने के ऑपरेशन से पूरी तरह नहीं उबर पाने के कारण अमेरिकी ओपन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अमेरिकी टेनिस संघ ने कहा कि 2018 के उप विजेता और 2009 के चैंपियन डेल पोत्रो पूरी तरह से नहीं उबरने के कारण टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। डेल पोत्रो का ऑपरेशन इसी साल जून में हुआ था। इससे पहले डेल पोत्रो ने 31 जुलाई को सोशल मीडिया में एक वीडियो साझा किया था जिसमें वह ट्रेडमिल पर चल रहे थे।

सिनसिनाटी मास्टर्स से हटीं सेरेना

सिनसिनाटी : पीठ में तकलीफ के कारण अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स सिनसिनाटी मास्टर्स से हट गईं। रविवार को पीठ में तकलीफ के कारण सेरेना मांट्रियल मास्टर्स में डब्लयूटीए फाइनल से चार गेम में बाद ही हट गई थीं। उन्हें यहां वापसी की उम्मीद थी लेकिन 23 बार की ग्रैंडस्लैम विजेता को पीठ में तकलीफ के कारण सिनसिनाटी टूर्नामेंट से भी हटना पड़ा, जिससे 26 अगस्त से शुरू हो रहे अमेरिकी ओपन में उनके हिस्सा लेने पर भी सवालिया निशान लग गया है। सेरेना ने कहा, 'मुझे सिनसिनाटी से नाम वापस लेकर बहुत दुख हो रहा है क्योंकि यह मेरा पसंदीदा टूर्नामेंट है। दुर्भाग्य से मेरी पीठ अभी भी सही नहीं है और मुझे पता है कि मैं कोर्ट पर नहीं जा पाऊंगी।'

भारतीय हॉकी टीमें ओलंपिक टेस्ट इवेंट के लिए तैयार

टोक्यो, प्रेट्र: ओलंपिक टेस्ट इवेंट से पहले आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी टीम ऊंची रैंकिंग वाली प्रतिद्वंद्वी से भयभीत नहीं होती और दुनिया की किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है। ओलंपिक टेस्ट इवेंट शनिवार को यहां ओई हॉकी स्टेडियम में शुरू होगा, जिसमें भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें खेलेंगी।

दोनों टीमें एफआइएच ओलंपिक क्वालीफायर की तैयारियों में जुटी हैं, जो इस साल के अंत में नंवबर में आयोजित होने हैं। एफआइएच ओलंपिक क्वालीफायर का विजेता 2020 टोक्यो ओलंपिक में अपना स्थान पक्का कर लेगा। विश्व रैंकिंग में पांचवें स्थान पर काबिज भारतीय पुरुष टीम ओलंपिक टेस्ट इवेंट में शीर्ष रैंकिंग की टीम है और वह दुनिया की आठवें नंबर की न्यूजीलैंड, 12वीं रैंकिंग की मलेशिया और 16वीं रैंकिंग की जापान की टीम से भिड़ेगी। हरमनप्रीत की अगुआई वाली पुरुष टीम में कुछ अनुभवी खिलाड़ी मौजूद नहीं होंगे, जिन्हें आराम दिया गया है। इससे टीम अपने कप्तान और उप कप्तान मंदीप सिंह से प्रेरणा लेना चाहेगी। हरमनप्रीत ने कहा, 'हमारे पास मलेशिया, जापान और न्यूजीलैंड के खिलाफ युवा खिलाड़ियों को परखने का मौका है। ये अच्छी टीमें हैं और हम अपने मुख्य कोच के हिसाब से अच्छी तरह सामंजस्य बिठा रहे हैं।' विश्व रैंकिंग में 10वें नंबर की भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया (दूसरी रैंकिंग), चीन (11वीं रैंकिंग) और जापान (14वीं रैंकिंग) से कड़ी चुनौती मिलेगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत होगी, जिससे भारतीय टीम पिछले साल कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में 0-1 से मिली हार के बाद से नहीं खेली है। रानी का मानना है कि एफआइएच ओलंपिक क्वालीफायर में खेलने से पहले बड़ी टीम से खेलने से उनकी टीम को बड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ट्रायल्स 19 व 20 को

नई दिल्ली, जेएनएन: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) कजाखिस्तान के नूर-सुल्तान में होने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए आगामी सोमवार और मंगलवार को ट्रायल्स का आयोजन करेगी।

डब्ल्यूएफआइ ने कहा कि 19 अगस्त को लखनऊ में और 20 अगस्त को दिल्ली के केडी जाधव कुश्ती स्टेडियम में ट्रायल्स का आयोजन किया जाएगा। यह ट्रायल्स पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती के वर्गों में होंगे। डब्ल्यूएफआइ पुरुष फ्री स्टाइल की गैर ओलंपिक वर्ग 61 किग्रा, 70 किग्रा, ओलंपिक वर्ग 74 किग्रा, 79 किग्रा और 92 किग्रा के लिए, जबकि महिला कुश्ती में गैर ओलंपिक वर्ग 55 किग्रा, 59 किग्रा, 65 किग्रा और 72 किग्रा के लिए ट्रायल्स का आयोजन करेगा। विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 22 सितंबर तक होगा। यह चैंपियनशिप टोक्यो ओलंपिक के लिए पहला क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट भी है।

72 मिनट का भाषण दिया था 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से। इस रिकॉर्ड को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 86 मिनट का भाषण देकर तोड़ा। इसके अगले साल 2016 में मोदी ने 94 मिनट का भाषण दिया।

किसी तोप से कम न थी देवनारायण की कलम

आशुतोष मिश्र, लखनऊ

कहानी-8

- आगरा निवासी पंडित देवनारायण थे भारतीय मातृवेदी के साहित्य प्रचार विभाग के प्रमुख
- इनकी लिखी पुस्तकें और पर्चे नौजवानों में भरते थे जोश, नहीं संजोई गईं यादें

आगरा के मदिया कटरा मोहल्ले में 27 मई 1899 को जन्मे पंडित देवनारायण भारतीय के कलम अंग्रेजों के खिलाफ तोप सा असर रखती थी। यही वजह है कि इन्हें मातृवेदी के साहित्य प्रचार का प्रमुख बनाया गया था। पंडित देवनारायण भारतीय के पिता श्याम लाल शर्मा थाना हरीपर्वत में पुलिस निरीक्षक थे। आगरा कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पंडित देवनारायण जब दम्मीलाल पांडेय के संपर्क में आए तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की राह पर चल पड़े। दम्मीलाल और प्रताप सिंह ने आगरा, शिकोहाबाद और मैनपुरी में मजबूत संगठन तैयार हो जाने के बाद देवनारायण को इलाहाबाद में संगठन के निर्माण की जिम्मेदारी दी। इलाहाबाद जाकर देवनारायण ने गंगा सिंह को पार्टी से जोड़ा। उन दिनों बहुत से नौजवान मातृवेदी की ओर आकर्षित हुए। कई भाषाओं का जानकार होने के चलते देवनारायण भारतीय ने विभिन्न भाषाओं के क्रांतिकारी साहित्य का हिंदी अनुवाद भी किया। इन्होंने ही गंज मुरादाबाद के अपने साथी जगदंबा प्रसाद हितैषी के 'शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले...' गीत को 'अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली' पुस्तक के बैक पेज पर छपवाया था।

गंगा तट को बनाया बम बनाने की प्रयोगशाला : 'मातृवेदी- बागियों की अमर गाथा' पुस्तक में शाह आलम ने लिखा है कि मैनपुरी मुकदमे के दौरान फरार नेता देवनारायण जी से देशबंधु चित रंजन दास ने पूछा कि इस समय आपके पास कितनी ताकत है? देवनारायण ने कहा कि आप कहें तो इसी रात मैनपुरी शहर को उड़ा दें। दरअसल, राजा बाजार केस के नायक

प्रतीकात्मक चित्रण। जागरण

शशांक मोहन हाजरा उर्फ अमृत लाल हाजरा से बम बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद फर्रुखाबाद गंगा तट को इन्होंने बम बनाने की प्रयोगशाला बना दिया था। यहां दर्जनों साथियों को प्रशिक्षण देकर क्रांतिकारी गतिविधियों को धार दी जाती थी। जान हथेली पर लेकर चलने वाले इस क्रांतिकारी ने 9 अगस्त 1968 को अंतिम सांस ली। शाह आलम अफसोस जाहिर करते हैं कि ऐसी शख्सियत का एक भी स्मारक नहीं है।

नीलामी दे रही 'आयरन लेडी' को सलामी

मिसाल ▶ पिता से हुनर सीख भानुमती साठ साल से भी अधिक समय से निभा रहीं नीलामकर्ता की जिम्मेदारी

- महज 17 साल की उम्र में बन गई थीं देश की पहली महिला नीलामकर्ता

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

स्वतंत्रता के सारथी
नारी तू नारायणी

एक लाख एक...एक लाख दो...एक लाख तीन...! यह सामान अब आपका हुआ। हमने नीलामकर्ता को इसी तरह विभिन्न चीजों की नीलामी करते देखा है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले नीलामकर्ता की भूमिका में सिर्फ पुरुष नजर आते थे। सदियों से चले आ रहे इस ढर्रे को करीब साठ साल पहले 17 साल की एक बाला ने बदला और पुरुषों के वर्चस्व वाले इस पेशे में कदम रख भारत की पहली महिला और सबसे युवा नीलामकर्ता बनने की उपलब्धि अपने नाम की। यही नहीं, वर्तमान में वे देश की सबसे उम्रदराज नीलामकर्ता भी हैं। ये हैं भानुमती पारेख, जिन्हें 'आयरन लेडी' के खिताब से नवाजा जा चुका है। कारण, वे देश में एकमात्र ऐसी महिला नीलामकर्ता हैं, जो रक्षा मंत्रालय के लिए स्क्रैप, धातुओं व मशीनों की नीलामी करती हैं।

83 साल की भानुमती विभिन्न रक्षा उपक्रमों के लिए नीलामकर्ता की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा रही हैं। सीवीडी पानागढ़, मेटल एंड स्टील फैक्ट्री इच्छापुर, राइफल फैक्ट्री, गन एंड शेल फैक्ट्री, कलाईकुंडा, फरीदाबाद व आगरा की वायुसेना छावनियों समेत देशभर में जाकर वहां पड़े स्क्रैप, खराब मशीनों व अनुपयोगी धातुओं की वे नीलामी कर चुकी हैं। आज भी पूरी तरह सक्रिय हैं। रक्षा उपक्रमों के अलावा वे रेलवे व निजी क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों को भी लंबे समय से सेवाएं प्रदान करती आ रही हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी उनमें 17 साल जितना ही जोश नजर आता है।

पिता से सीखा हुनर : साइंस में स्नातक भानुमती ने नीलामकर्ता बनने के लिए कहीं कोई प्रशिक्षण नहीं लिया बल्कि पिता को देखकर ही सब कुछ सीख लिया। कोलकाता की भानुमती ने बताया-मेरे पिताजी जगमोहन के. पारेख भी नीलामकर्ता थे। हमारा अपना नीलामी घर था। पिता फर्नीचर, एंटिक व ज्वेलरी की नीलामी करते थे। वे मुझे अपने साथ नीलामी में ले जाते थे। इसी तरह दिलचस्पी जगी और उन्हें देख यह कला भी सीख ली। हालांकि, मन के किसी कोने में डॉक्टर बनने की महत्वाकांक्षा भी थी। एक बार पिताजी बीमार पड़ गए तो मुझे नीलामी करने भेजा गया। बस वहीं से सफर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है।

जब फैक्ट्री के गेट पर रोक दिया गया : भानुमती ने शुरुआती दिनों की एक दिलचस्प घटना बयां करते हुए कहा-मुझे जब रक्षा मंत्रालय की ओर से नीलामकर्ता नियुक्त किया गया था, तब मेरी उम्र बहुत कम थी। एक बार इच्छापुर स्थित मेटल एंड स्टील फैक्ट्री में स्क्रैप की नीलामी करने जाते वक्त मुझे सुरक्षाकर्मियों ने गेट पर रोक दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र की कोई, वह भी एक महिला, स्क्रैप की नीलामी करने आई है। फैक्ट्री के अधिकारियों से संपर्क करने के बाद ही मैं अंदर घुस पाई थी।'

मूलरूप से गुजरात के मांगरोल की रहने वाली भानुमती देश की सबसे पुरानी नीलामी संस्था कोलकाता आधारित एम्बर्ट एंड्रयूज ऑक्शन मार्ट में साझेदार हैं। 83 साल की उम्र में 20 युवाओं की टीम की अगुआई कर रहीं भानुमती ने कहा-समय के साथ नीलामी का तरीका काफी बदला है। आज ऑनलाइन

कोलकाता स्थित अपने नीलामी घर में भानुमती पारेख। बिमल कर्मकार

नीलामी का जमाना है। एक अच्छा नीलामकर्ता बनने के लिए नीलाम होने वाली चीजों के मूल्य व महत्व को पूरी तरह जानना बहुत जरूरी है। बोली लगाने वालों की मनोदशा व शारीरिक भाषा को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि बोली लगाने वाला हर कोई मुंह से सारी बातें नहीं कहता। उनके इशारे को तुरंत समझना जरूरी है। इसके लिए उपस्थित बुद्धि चाहिए। बुलंद आवाज की भी जरूरत है, क्योंकि नीलामी के वक्त जोर से बोलना पड़ता है।

बेटे की शहादत के बाद छात्रों की मदद को आगे आई मां

जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहता था शहीद बेटा, इसी को आगे बढ़ा रहीं मां सपना

मनीषा गर्ग, नई दिल्ली

कारगिल युद्ध में बेटे सुमित रॉय की शहादत के बाद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर देश के लिए नए योद्धाओं की फौज तैयार करने में 1999 से जुटी हैं सपना रॉय। नई दिल्ली के द्वारका स्थित कारगिल अपार्टमेंट में रहने वाली सपना बताती हैं कि कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद होकर उनके बेटे ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। वह उनकी शहादत को व्यर्थ न करते हुए विभिन्न तरीकों से समाज के ऐसे युवा जो गरीबी के चलते शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित हैं, उनकी मदद को तत्पर रहती हैं। इसके अलावा आज सपना अपने दम पर कई परिवारों का खर्चा चला रही हैं।

बेटे की शहादत के बाद जब सपना को पेट्रोल पंप चलाने की जिम्मेदारी मिली, तभी उन्होंने यह तय कर लिया था कि वह पेट्रोल पंप से होने वाली कमाई व सुमित की पेंशन का आधा हिस्सा युवाओं को आगे बढ़ाने में खर्च करेंगी। सपना बताती हैं कि सुमित हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहता था। बेटे के इस शौक को वह आगे ले जाना चाहती हैं।

रोहिणी सेक्टर-24 में वह पेट्रोल पंप चलाती हैं। यहां कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का ध्यान रखना उनकी जिम्मेदारी है। कर्मचारियों की सभी जरूरतों को पूरा करने में वह कोई कमी नहीं छोड़तीं। पेट्रोल पंप पर उन्होंने कई ऐसे युवाओं को नौकरी दी है, जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्हें नौकरी देकर आर्थिक रूप से मजबूत करने के साथ ही पढ़ाई करने के लिए भी प्रेरित करती हैं, ताकि भविष्य में वे बड़ी नौकरी व उपलब्धि प्राप्त कर सकें। वर्तमान में उनके पेट्रोल पंप पर एक युवती राधा आर्या कार्यरत हैं, जिसने परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 12वीं में पढ़ाई छोड़ दी। आज यह युवती न सिर्फ पेट्रोल पंप पर काम कर अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभाल रही है, बल्कि स्नातक के बाद अब मास्टर की डिग्री भी ले चुकी है। छत गिरने से माता-पिता की मौत के बाद अनाथ हुए तीनों बच्चों को संभालने के लिए भी सपना ने पहल की थी। उत्तराखंड, गढ़वाल में एक शहीद के परिवार के पालन-पोषण व उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सपना ने अपने मजबूत कंधों पर ले रखी है।

शहीद कैप्टन सुमित रॉय की मां सपना रॉय (दाएं) अपने पेट्रोल पंप पर कार्यरत राधा आर्य के साथ। राधा ने पेट्रोल पंप पर कार्य करने के साथ ही मास्टर डिग्री भी हासिल की। सौजन्य : सपना रॉय

आत्मनिर्भर बनने के लिए करती हैं प्रेरित : सपना सक्षम भारती संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। जिसके विकास नगर, रघुबीर नगर, द्वारका व नोएडा में सेंटर हैं। यह संस्था युवाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग में निपुण बनाती है, ताकि जो युवा शिक्षा में कमजोर हैं वे अपने मन मुताबिक ट्रेनिंग को प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनें। इस संस्था के माध्यम से कई महिलाओं ने अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर दिया है तो कई आज नौकरी कर रही हैं। इसके अलावा पालम स्थित शहीद कैप्टन सुमित रॉय सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर-2 में हर साल सपना 11वीं व 12वीं के ऐसे छात्र-छात्राओं को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देती हैं जो शिक्षा जगत में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रेम, दया व क्षमा को बनाए दैनिक जीवन का हिस्सा : दलाई लामा

जागरण संवाददाता, मनाली : तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा कि सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं मूल रूप से प्रेम, दया और क्षमा का एक ही संदेश देती हैं। उन्होंने अनुयायियों से कहा कि वे इन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। वह मनाली में चल रहे तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन में अनुयायियों को ज्ञान बांट रहे थे।

उन्होंने कहा कि ज्ञान, दया और क्षमा इंसान को बड़ा बनाती है। खुशहाली बनी बनाई नहीं मिलती उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। अपनी क्षमताओं को जानकर और उनपर यकीन करके ही हम एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। अपने साथ दूसरों को भी खुश रखने के लिए करुणा का भाव रखें। दयालुता ही इंसान का धर्म है। सच्चा हीरो वही है जो अपने क्रोध को जीत लेता है। हिमालयन बुद्धिस्ट सोसायटी के मुख्य संरक्षक रवि ठाकुर ने बताया कि महामहिम के प्रवचनों को सुनने के लिए बौद्ध अनुयायियों का भारी हजूम देखने को मिला। आज आर्य अवलोकितेश्वर का अभिषेक होगा, जिसमें अनुयायियों के भारी संख्या में उमड़ने की उम्मीद है। जनजातीय जिला लाहुल स्पीति, पांगी, किन्नौर ओर लेह से भरी संख्या में अनुयायियों ने मनाली में दस्तक दी है। मनाली में बौद्ध अनुयायियों की लगातार भीड़ बढ़ रही है।

पेड़ों को राखी बांध लिया रक्षा का वचन

पोपीन पंवार, यमुनानगर

रक्षा बंधन भाई बहन के रिश्ते का त्योहार। कनालसी गांव की शिवी राणा ने अपने भाई रणजोर सिंह व अमन को राखी बांधने से पूर्व पेड़ों को राखी बांध रक्षा का वचन लिया। इसके लिए यमुना बचाओ समिति के पदाधिकारियों से प्रेरणा मिली है। पदाधिकारियों ने भी इस पर्व पर पेड़ों की रक्षा के लिए राखी बांधने का प्रण लिया है। समिति यमुना को बचाने की दिशा में काफी समय से काम कर रही है।

शिवी राणा बताती हैं कि इनके दादा किरणपाल राणा डेढ़ दशक से यमुना बचाओ के लिए कार्य कर रहे हैं। पिता पंकज व माता रिंकू भी मुहिम से जुड़ी हैं। दादा के सामने उन्होंने बात रखी थी कि इस बार रक्षा बंधन पर वे भाइयों की तरह पेड़ को भी राखी बांधेगी। उन्होंने इस पर स्वीकृति जताई। समिति के सभी पदाधिकारी रक्षा बंधन पर पेड़ों को राखी बांधेंगे। उनका ये भी कहना है कि कॉलेज में उनको सेमिनार में बताया गया कि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण ये दिक्कत आ रही है। इसलिए उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए ये मुहिम शुरू की। क्लास में साथ पढ़ने वाली छात्राएं इस मुहिम में शामिल हैं।

पेड़ काटने पर है जुर्माने का प्रावधान : यमुना किनारे पर हरियाली रहे इसके लिए सैकड़ों पौधे लगाए हैं। जो अब पेड़ बन चुके हैं। समिति पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है। पूरे गांव व आसपास के लोगों को हिदायत दी हुई कि कोई पेड़ नहीं काटेगा। पेड़ काटते हुए कोई मिला तो उस पर जुर्माना का प्रावधान भी है। समिति के सख्त कानून का सभी लोग अनुपालन करते हैं। इसी तरह जलीय जीवों की रक्षा का संकल्प भी समिति की ओर से लिया गया है। पूरे गांव में जलीय जीवों के शिकार पर प्रतिबंध है।

लाल किले पर दिखेगी अखंड राष्ट्र की सशक्त तस्वीर

जागरण विशेष ▶ जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण होगा खास

लोकेश चौहान, नई दिल्ली

- यहां से 13 प्रधानमंत्री 72 बार कर चुके हैं देश को संबोधित
- मोदी ने 2015 में तोड़ा था नेहरू के सबसे लंबे संबोधन का रिकॉर्ड

दिल्ली के लाल किले ने ब्रितानिया हुकूमत का उदय और मुगलकाल का पतन देखा है। कभी यहां की दीवारें खून से रंगी गईं तो कभी यहां कोहिनूर की चमक भी बिखरी थी। इसे भी संयोग ही कहा जाएगा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां तिरंगा फहराएंगे, तो ये किला भी अपने 370 साल पूरे कर चुका होगा। 17वीं से 21वीं सदी तक के बदलाव के साक्षी रहे लाल किले की प्राचीर से इस स्वतंत्रता दिवस पर अखंड राष्ट्र की सशक्त तस्वीर दिखाई देगी। ये ऐसा पहला स्वतंत्रता दिवस होगा, जब देश का मुकुट जम्मू-कश्मीर सही मायनों में देश का हिस्सा होगा।

लाल किले की प्राचीर से अब तक 13 प्रधानमंत्री 72 बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराकर देश को संबोधित कर चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहां सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराया। उन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक 17 बार ध्वजारोहण किया। दूसरे नंबर पर एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। उन्होंने 16 बार राष्ट्रध्वज फहराया है। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम है, जिन्होंने दस बार यहां ध्वजारोहण किया। देश को परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने छह बार तो राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने पांच-पांच बार, मोरारजी देसाई ने दो बार और चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह और एचडी देवगौड़ा ने एक-एक बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां तिरंगा फहराया। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को छठी बार तिरंगा फहराएंगे। गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें लालकिले पर तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला।

लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं तिरंगा। फाइल फोटो

देश को संबोधित करने में मोदी अव्वल : जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में 72 मिनट का भाषण दिया था। इस लंबे संबोधन का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 86 मिनट तक भाषण देकर तोड़ा था। हालांकि 2014 में उन्होंने 65 मिनट तो वर्ष 2016 में 94 मिनट का भाषण दिया। वर्ष 2017 में मोदी ने अपना सबसे छोटा 54 मिनट का भाषण दिया था। 2018 में 82 मिनट का भाषण था। डॉ. मनमोहन सिंह ने यहां से दस बार भाषण दिए। सिर्फ दो बार उनका भाषण 50 मिनट तक पहुंचा, जबकि आठ बार 32 से 45 मिनट का ही रहा। गुरुवार को पूरे देश की नजरें मोदी के भाषण पर लगी हैं क्योंकि उनकी दोबारा जीत के बाद कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

चीन के रेशम और टर्की के मखमल से हुई थी सजावट

मुगल काल में इसे किला-ए-मुबारक के नाम से जाना जाता था, जो शाहजहां की नई राजधानी शाहजहांनाबाद का महल था। यह दिल्ली शहर की सातवीं मुस्लिम नगरी थी।

लगभग डेढ़ मील के दायरे में अनियमित अष्टभुजाकार आकार में बने इस महल का निर्माण कार्य उस्ताद अहमद और उस्ताद हामिद ने किया था। उद्घाटन के समय भारी पर्दों और चीन के रेशम और टर्की के मखमल से इसकी सजावट की गई थी। करीब 200 साल तक इसमें मुगल परिवार के वंशज रहे। ब्रिटिश काल में इसे छावनी के रूप में प्रयोग किया गया। वर्ष 2003 तक इसके कई हिस्से सेना के नियंत्रण में रहे। 22 दिसंबर 2003 को सेना ने अपना कार्यालय हटाकर इसे पर्यटन विभाग को सौंप दिया।

साइबर सिक्योरिटी का बड़ा शोध केंद्र बनेगा आइआइटी कानपुर

जागरण संवाददाता, कानपुर

- बांबे स्टॉक एक्सचेंज, यूपी 100 और फाइनेंस सेक्टर के लिए चल रहा अनुसंधान

आइआइटी कानपुर 2020 तक साइबर सिक्योरिटी का बड़ा शोध केंद्र बन जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों से करार के बाद यहां बांबे स्टॉक एक्सचेंज व यूपी 100 के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर पहले ही काम शुरू हो गया है। इसके अलावा बैंकिंग व अन्य फाइनेंस सेक्टर कंपनियों को साइबर हैकिंग से बचाने के लिए भी अनुसंधान चल रहा है।

यहां साइबर उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। यहां साइबर इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर साइंस व इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्र साइबर सिक्योरिटी की नई तकनीक ईजाद कर सकेंगे। आइआइटी प्रोफेसर उनके मेंटर होंगे। यह पहला मौका होगा, जब युवा टेक्नोक्रेट साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपने स्टार्टअप भी शुरू कर सकेंगे।

साइबर अटैक से बचाने के लिए आइआइटी तैयार : इंडस्ट्री को साइबर अटैक से बचाने के लिए आइआइटी तैयार है। यहां 'साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम' में कई नए सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। इससे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को साइबर अटैक से बचाया जा सकता है। खास बात यह है कि देशभर की विभिन्न इंडस्ट्री ने अपनी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ कंपनियों के साथ मिलकर आइआइटी साइबर सिक्योरिटी पर कार्य करेगा। इसके लिए नए सॉफ्टवेयर व उपकरण विकसित करने के साथ तकनीकी सलाह का करार भी शामिल है।

आइआइटी कानपुर फाइल फोटो

ई-बैंकिंग सिक्योरिटी देगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर

आइआइटी में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित हो चुका है। यह केंद्र साइबर हैकिंग और ई-बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। यहां इजरायल की टेल अवीव यूनिवर्सिटी जल्द ही डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगी। आइआइटी के पास साइबर हैकिंग व अटैक से लड़ने की जो तकनीक है उसका लाभ संयुक्त शोध के दौरान भारत और इजरायल दोनों देशों को मिलेगा।

साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में कई अनुसंधान चल रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर बनने के बाद इसे और गति मिलेगी। इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जो इस क्षेत्र में उद्यमिता से जुड़ना चाहते हैं।

- प्रो. मणींद्र अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट व उप निदेशक आइआइटी

पहल

खादी केंद्रीय बोर्ड, मुंबई ने चरखा स्किल डेवलपमेंट कोर्स को दी मान्यता, खादी बोर्ड ने कॉलेज के गांधी स्टडी सेंटर फॉर रिसर्च के साथ मिलकर शुरू किया प्रयोग, जल्द कॉलेज में शुरू होगा रेडीमेड गारमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स

जमशेदपुर में देश का पहला कॉलेज, जहां छात्राएं सीखेंगी सूत कातना

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर

झारखंड के जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले गांधी जी की अर्थशास्त्र से जुड़ी अवधारणा साकार हुई। यहां खादी केंद्रीय बोर्ड, मुंबई के सहयोग से चरखा केंद्र की शुरुआत हुई। इस केंद्र में बच्चियां सूत कातने के साथ महात्मा गांधी के दर्शन को समझेंगी, साथ ही कमाई भी करेंगी। बुधवार को खादी बोर्ड और कॉलेज के गांधी स्टडी सेंटर फॉर रिसर्च के संयुक्त प्रयास से बने इस चरखा केंद्र का उद्घाटन राज्य के खाद्य व आपूर्ति मंत्री मंत्री सरयू राय ने किया। खादी केंद्रीय बोर्ड, मुंबई ने कॉलेज में चलने वाले चरखा स्किल डेवलपमेंट कोर्स को मान्यता दी है। जल्द ही खादी बोर्ड रेडीमेड गारमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स कॉलेज में शुरू करेगा।

कॉलेज की प्राचार्या डॉ. पूर्णिमा कुमार ने बताया कि तकुआ चरखा का प्रशिक्षण कार्य देश के किसी भी कॉलेज में नहीं होता है। वीमेंस कॉलेज देश का पहला कॉलेज है, जहां इस तरह का प्रशिक्षण हो रहा है। वैसे गांधी दर्शन पढ़ाने वाले कॉलेजों में चरखे तो होते हैं, लेकिन वहां के उत्पाद की बिक्री नहीं होती है। चरखा केंद्र से बने सूतों को पूर्वी सिंहभूम खादी ग्रामोद्योग संघ खरीदेगा। मंत्री सरयू राय ने कहा कि इस योजना से छात्राओं के बीच स्वरोजगार की प्रतिस्पर्धा होगी। स्किल इंडिया को इस योजना को जोड़ देने से कई तरह की सहायता प्राप्त होगी।

जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में बुधवार को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले चरखा केंद्र के उद्घाटन के मौके पर चरखा चलातीं छात्राओं को प्रोत्साहित करते राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, खादी व ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक जेके गुप्ता व कॉलेज की शिक्षिकाएं। जागरण

प्रतिदिन 200 रुपये अर्जन कर सकेगी एक छात्रा : खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक जेके गुप्ता ने कहा कि कुल 25 चरखा से यहां की छात्राओं को प्रशिक्षण मिलेगा। सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक सिर्फ हॉस्टल की छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं।

इस आधुनिक तकुआ चरखा से सूत काटने से लेकर वस्त्र तैयार करने की विधि तक बताई जाएगी। सारा कच्चा माल खादी ग्रामोद्योग आयोग उपलब्ध कराएगा। छात्राओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को भी आयोग खरीदेगा। इससे छात्राएं प्रतिदिन 200 रुपये कमा सकेगी।

रेडीमेंट गारमेंट का कोर्स होगा प्रारंभ

जमशेदपुर वीमेंस कॉलेज में रेडीमेट गारमेंट बनाने का कोर्स प्रारंभ होगा। इसके लिए आवश्यक मशीन व अन्य सामग्रियां खादी ग्रामोद्योग आयोग के सौजन्य से कॉलेज में पहुंच चुकी है। वीमेंस कॉलेज के एकेडमिक काउंसिल की बैठक के बाद इस पाठ्यक्रम को पारित कराया जाएगा। यह सर्टिफिकेट कोर्स होगा और सभी छात्राओं के लिए उपलब्ध होगा।

मौसम विशेष

राजस्थान के पूर्वी भागों में अनेक स्थानों पर गरज व तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा होगी तथा बाढ़ जैसी स्थिति संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी राजस्थान में मौसम गर्म होगा। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ वर्षा का दौर जारी रहेगा।

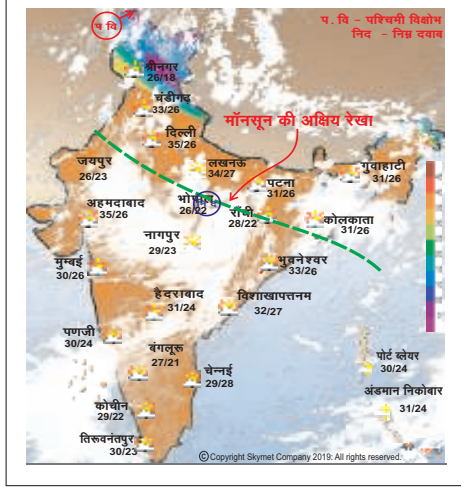

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/26/व	अहमदाबाद	34/25/व
कोलकाता	30/25/आंबा बड़ोदा		33/25/व
चेन्नई	39/28/आंबा नागपुर		32/24/आंबा
हैदराबाद	32/24/व	इन्दौर	27/23/व
बंगलूरु	26/20/व	रांची	33/24/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/24/व	पटना	37/28/आंबा
गुवाहाटी	31/26/व	जमशेदपुर	36/27/व
जंगटोक	19/09/व	पुणे	25/22/आंबा

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

गुरुवार 15 अगस्त 2019

14

www.jagran.com

छह अंकों वाला पिनकोड देश में लागू हुआ

1972 में आज ही पिनकोड लागू किया गया। देश में नौ पिनकोड जोन हैं। कोड का प्रथम अंक किसी एक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। द्वितीय अंक उप क्षेत्र को और तीसरा संबंधित क्षेत्र के जिले का होता है। अंतिम तीन अंक डाकघर की पहचान बताते हैं।

देश में निर्मित आकाश मिसाइल का हुआ पहला प्रक्षेपण

1990 में आज ही जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का पहला सफल प्रक्षेपण किया गया। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 30 किमी है। आकाश 60 किग्रा वजनी युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। 2009 से यह सेवा में है।

है प्रीत जहां की रीति सदा...गीत को शब्द दिए थे इंदीवर ने

1924 में आज ही उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे इंदीवर गीतकार का वास्तविक नाम श्यामलाल बाबू राय था। गीतकार बनने के लिए वह मुंबई पहुंचे। 1949 में फिल्म मल्हार के लिए लिखे उनके गीत 'बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम' ने शोहरत की बुलंदियां हासिल कीं। उन्होंने चार दशक के फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में लगभग एक हजार गीत लिखे। ये ऐसे गीत हैं जिन्हें हर कोई गुनगुनाने पर विवश हो जाता है। 1976 में दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्मफेयर मिला। झांसी में इनके नाम से इंदीवर मोहल्ला भी है। 27 फरवरी, 1997 को 73 साल की उम्र में वह दुनिया को अलविदा कह गए।

इधर-उधर की

केले के पत्तों से हो रही है सामान की पैकिंग

हनोई, एजेंसी : प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए वियतनाम में अनूठी पहल हुई है। खास बात यह है कि यह पहल आम लोगों ने अपने स्तर पर की है। यहां सामान की पैकिंग के लिए केले के पत्तों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, मक्के के पाउडर से बने बैग और रिसाइकिल स्टेशनरी चलन में आ गई है। वियतनाम में सबसे बड़ा प्रयोग शॉपिंग मॉल और दुकानों में हुआ है। यहां सामान केले के पत्तों में बांधकर दिया जा रहा है। यही नहीं यहां पेपर स्ट्रॉ का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही कई मॉल बायो-डिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स बेच रहे हैं, जो मक्के के पाउडर से बने होते हैं।

शोध अनुसंधान

रोजाना एक डिब्बी सिगरेट पीने जैसा घातक है प्रदूषण

प्रदूषण सेहत के लिए कितना खतरनाक है, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। हाल में इसको लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायु प्रदूषण से फेफड़ों पर उतना ही घातक असर पड़ता है, जितना रोजाना एक डिब्बी सिगरेट पीने से पड़ता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोधकर्ता जोएल कॉफमैन ने कहा, 'एंफीसेमा पर प्रदूषण के प्रभाव को देखकर हम चकित रह गए।' एंफीसेमा ऐसी स्थिति है, जिसमें फेफड़े के ऊतकों (टिश्यू) के नष्ट होने से कफ बनने और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह जानलेवा भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ज्यादा ओजोन प्रदूषण वाली जगहों पर रहने वालों में एंफीसेमा का स्तर ऐसा पाया गया, जैसे उन्होंने 29 साल तक रोजाना एक डिब्बी सिगरेट पी हो। - आइएएनएस

बेहतर रहता है चंचल बच्चों का स्वास्थ्य

बच्चों की चंचलता उनकी सेहत को सही बनाए रखने में सहायक होती है। चंचल बच्चे काम करते समय ज्यादा कैलोरी की खपत करते हैं। हालिया अध्ययन में यह बात सामने आई है। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड के शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन को अंजाम दिया है। इस दौरान 40 बच्चों की गतिविधियों और उनकी कैलोरी की खपत को मापा गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ज्यादा चंचल बच्चे ज्यादा कैलोरी की खपत करते हैं। इससे उनकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर जॉन रेली ने कहा, 'कभी बैठने, कभी खड़े हो जाने, कभी लेट जाने जैसी गतिविधियों से होने वाले लाभ को लेकर अब तक ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। इस दिशा में पर्याप्त शोध की जरूरत है कि इन प्रक्रियाओं में कितनी ऊर्जा की खपत होती है।' शारीरिक स्थिति को लगातार बदलते रहना ही चंचलता कहलाती है। बच्चों में इसकी आदत ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी ज्यादा देर तक एक स्थिति में नहीं रहते हैं। - प्रेट्र

जेनेटिक भी हो सकती हैं नींद से जुड़ी आदतें

न्यूयॉर्क टाइम्स से

रात को देर से सोने या सुबह जल्दी उठने की आदत जीवनशैली के साथ जीन पर भी निर्भर

वाशिंगटन : बीते कुछ वर्षों में आम लोगों की जीवन शैली तेजी से बदली है, जिसका असर उनके नींद के तरीके पर भी हुआ हैं। देर तक काम करने या पार्टी के शौकीन लोगों को जहां सुबह जल्दी जगने में परेशानी होती हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को चाहे जितनी देर से सोए, उनकी नींद सुबह जल्दी ही खुलती है। कई बार उनकी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती है। उन्हें लगता है कि खानपान या दिनचर्या के कारण यह हो रहा है। हालांकि, इसमें जीन की भी अहम भूमिका हो सकती है। स्लीप एपनिया (सोते समय सांस बाधित होना) व अनिद्रा के शिकार करीब 2,400 मरीजों का अध्ययन करने के बाद यह दावा किया गया।

शोधकर्ताओं के अनुसार, आमतौर पर नींद का चक्र (स्लीप साइकिल) तीन तरह का होता है। पहला, जिसमें व्यक्ति जल्दी सोता और सुबह जल्दी उठता है। दूसरा, जिसमें व्यक्ति सुबह देर तक सोता रहता है। तीसरा, जिसमें व्यक्ति रात को चाहे कितनी भी देर से सोया हो, सुबह जल्दी जग जाता है। सैन फ्रांसिस्को स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर लुई जे. टासेक के मुताबिक दुनिया में लंबी और छोटी, दोनों तरह की नींद लेने वाले लोगों की भरमार है। नींद लेने का ये तरीका आनुवांशिक भी हो सकता है। कई बार इसका असर इतना अधिक होता है कि व्यक्ति चाह कर भी उसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकता है। यदि उसे सुबह जल्दी जगने की आदत है तो वह दो घंटे की नींद लेकर भी सुबह जल्दी उठ जाएगा। कई मामलों में तो रात में ठीक से ना सोने के बावजूद व्यक्ति को दिन में भी उबासी नहीं आती है। वह इससे खुश भी रहते हैं। हालांकि, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शोधकर्ताओं का कहना है कि नींद ठीक से पूरी ना हो तो उससे भविष्य में अल्जाइमर (याददाश्त का कमजोर होना) के साथ कई सारी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

सुबह जल्दी जगने को समस्या नहीं मानते लोग : बचपन से ही हमें समय पर सोने और समय पर जगने की आदत सिखाई जाती है। देर से सोने के बाद भी सुबह जल्दी जग जाने पर किसी को सजा नहीं बल्कि आमतौर पर शाबाशी ही मिलती है। इसी के चलते देर से सोने के बाद भी सुबह जल्दी जग जाना किसी को समस्या नहीं लगता है। हालांकि, कई साल तक यही चक्र जारी रहे तो आपके नींद की अवधि कम हो सकती है। कई बार व्यक्ति आधी रात को ही उठ जाता हैं और उसे दोबारा सोने में परेशानी आती है।

मोबाइल फोन के इस्तेमाल से भी देर से आती है नींद : अनिद्रा के शिकार और सुबह जल्दी जगने वाले लोगों को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे उन्हें जल्दी नींद आ जाए। मोबाइल फोन और ई-बुक आदि से निकलने वाली नीली रोशनी के चलते भी व्यक्ति को देर से नींद आती है। इसी कारण सोने से पहले फोन आदि के इस्तेमाल से बचना चाहिए।

व्यायाम और स्वस्थ भोजन अच्छी नींद में सहायक : रोजाना व्यायाम करने और सोने से पहले भारी खाने से बचना भी अच्छी नींद में सहायक हो सकता है। यदि नींद आधी रात को या सुबह बहुत जल्दी खुले तो उस वक्त कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे बोरियत हो। दरअसल, बोरियत होने से व्यक्ति को तुरंत ही नींद आ जाती है।

धरती का आंगन छोड़ चांद की ओर बढ़ा चंद्रयान-2

बढ़े कदम ▶ कक्षा में छठी बार बदलाव करते हुए यान चांद के पथ पर गया

न्यूयॉर्क टाइम्स से

20 अगस्त को चांद की कक्षा में पहुंचेगा, सात सितंबर को होनी है लैंडिंग

बेंगलुरु, प्रेट्र: भारत के चंद्रयान-2 ने एक और पड़ाव पार कर लिया है। लांचिंग के 23 दिन बाद बुधवार को चंद्रयान-2 ने धरती की कक्षा छोड़कर चांद की ओर कदम बढ़ा दिया। यान 20 अगस्त को चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। 22 जुलाई को लांच हुए चंद्रयान-2 के लैंडर व रोवर को चांद पर लैंडिंग सात सितंबर को होनी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने बुधवार की अलसुबह दो बजकर 21 मिनट पर यान की कक्षा में बदलाव किया। लांचिंग के बाद से यह चंद्रयान-2 की कक्षा में छठा बदलाव है। इस बदलाव के जरिये यान को लुनार ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी (एलटीटी) पर पहुंचा दिया गया। इसके लिए यान के लिक्विड इंजन को 1203 सेकेंड के लिए चलाया गया था। एलटीटी वह पथ है, जिस पर बढ़ते हुए यान चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इस प्रक्रिया को ट्रांस लुनार इंसर्शन (टीएलआइ) कहा जाता है। यान की कक्षा में पिछला बदलाव छह अगस्त को किया गया था।

इसरो ने बताया कि यान की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। लांचिंग के बाद से अब तक यान पर लगे सभी सिस्टम सही तरह से काम कर रहे हैं। 20 अगस्त को जब यान चांद के मुहाने पर पहुंचेगा, तब एक बार फिर लिक्विड इंजन चलाकर इसे चांद की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। इसके बाद यान को चांद की निकटतम कक्षा तक पहुंचाने के लिए कक्षा में चार बदलाव और किए जाएंगे। निकटतम कक्षा चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर पर होगी।

दुनियाभर की टिकी हैं निगाहें: चंद्रयान-2 पर दुनियाभर की निगाहें टिकी हैं। इस यान के तीन हिस्से हैं- ऑर्बिटर, लैंडर 'विक्रम' और रोवर 'प्रज्ञान'। ऑर्बिटर करीब सालभर चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम देगा। वहीं लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। लैंडिंग के साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक अमेरिका, रूस और चीन अपना यान चांद पर उतार चुके हैं। हालांकि चंद्रयान-2 के लैंडर-रोवर चांद के जिस हिस्से पर उतरेंगे, वहां कोई यान नहीं पहुंचा है।

भारत का दूसरा चंद्र अभियान: यह भारत का दूसरा चंद्र अभियान है। 2008 में भारत ने चंद्रयान-1 भेजा था। यह ऑर्बिटर मिशन था। यान ने करीब 10 महीने चांद की परिक्रमा करते हुए प्रयोगों को अंजाम दिया था। चांद पर पानी की खोज का श्रेय भारत के इसी अभियान को जाता है। चंद्रयान-2 से इस दिशा में और मजबूत प्रमाण मिलने तथा चांद पर खनिज की उपस्थिति का पता चलने की उम्मीद है। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी-मार्क 3 की मदद से प्रक्षेपित किया गया था।

न्यूजीलैंड में विशालकाय पेंगुइन के जीवाश्म मिले

वेलिंगटन, एएफपी : वैज्ञानिकों ने बताया है कि न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में एक मानव के आकार के विशाल पेंगुइन का जीवाश्म पाया गया है। शोधकर्ताओं ने बताया कि विशालकाय समुद्री पक्षी की ऊंचाई 1.6 मीटर (63 इंच) और वजन 80 किलो था। जो आधुनिक पेंगुइन से चार गुना अधिक भारी और 40 सेमी अधिक लंबा था। पेंगुइन की इस नई प्रजाति को 'क्रासवैलिया वैपरेंसिस' नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह 6.6 करोड़ साल पहले न्यूजीलैंड के तट पर निवास करते होंगे।

'अल्केरिंगा' जर्नल में प्रकाशित शोध में बताया गया कि पेंगुइन की इस प्रजाति के पैरों के कुछ जीवाश्म एक वर्ष पहले भी मिले थे। तब इसे एक नई प्रजाति के रूप में पहचाना गया था। कैंटरबरी संग्रहालय की शोधकर्ता वेनेसा डि पिएत्री ने बताया कि यह पेलियोसीन (पुरानूतन) युग का दूसरा बड़ा जीवाश्म मिला है। उन्होंने बताया कि इससे यह पता चलता है कि पेंगुइन ने अपने शुरुआती विकास में एक बड़ा आकार प्राप्त किया था। न्यूजीलैंड अपने विलुप्त विशाल पक्षियों के लिए जाना जाता है। जिनमें उड़ने में असमर्थ मोआ और हास्ट का गरुण भी शामिल है। मोआ 3.6 मीटर तक लंबा था और वहीं हास्ट का ईगल के डैने तीन मीटर तर के थे। पिछले हफ्ते ही कैंटरबरी संग्रहालय ने एक विलक्षण तोते की खोज की घोषणा की थी जो एक मीटर लंबा था और लगभग 1.9 करोड़ साल पहले निवास करता था।

फिल्म रिव्यू

वंस अपॉन ए टाइम इन... हॉलीवुड

निर्देशन: क्विटिन टैरेनटीनो
प्रमुख कलाकार: लियोनार्डो डी कैप्रियो, ब्रेड पिट, मार्गट रॉबी, जूलिया बटर्स, आस्टिन बटलर, अल पचीनो
अवधि: 2 घंटे 4 मिनट

सितारों की जगमगाती दुनिया के कई स्याह पक्ष होते हैं। करियर में आए उतार-चढ़ाव उन्हें हताशा की ओर ले जाते हैं। उनकी इस मनोदशा और मनोवृत्ति का क्विटिन टैरेनटीनो ने अपनी नौवीं फिल्म 'वंस अपॉन ए टाइम इन...हॉलीवुड' में बखूबी चित्रण किया है। कहानी पिछली सदी के छठे दशक के दौरान की है।

निर्देशक टैरनटीनो के प्रशंसक उनके ब्लैक ऐंड व्हाइट में काम करने के तरीके से वाकिफ रहे हैं। यहां पर भी ओपनिंग सीन ब्लैक ऐंड व्हाइट है। लोकप्रिय फिल्म स्टार रिक डॉल्टन (लियोनार्डो डी कैप्रियो) अपने बॉडी डबल क्लिफ बूथ (ब्रैड पिट) के साथ साक्षात्कार देते हुए बॉडी डबल के प्रयोग की अहमियत को रेखांकित करते हैं। अगले दृश्य में रिक की मुलाकात मार्विन स्क्वॉर्ज (अल पचीनो) से होती है, जो उन्हें वेस्टर्न फिल्मों में किरदार का प्रस्ताव देते हैं। यह दृश्य रिक के करियर के ढलान के दिनों के हैं। वह नकारात्मक किरदारों को निभाने के लिए विवश है। फिल्म के दौरान कई ऐसे सीन आते हैं, जिनमें रिक अपने दर्द को बयां करते हुए क्लिफ के सामने स्वीकारता है कि उसे बदलाव की जरूरत है। क्लिफ रिक के ड्राइवर के तौर पर काम करता है। रिक अपने एक पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है, हालांकि उसमें काम करने की उसकी तनिक इच्छा नहीं है। वहां से कहानी क्लिफ और अभिनेत्री शैरन टेट (मार्गट रॉबी) की ओर मुड़ती है। शैरन रिक की पड़ोसी और फ्रेंच निर्देशक रोमन पोलंसकी की पत्नी होती है। दोनों पति-पत्नी अपने करियर के शिखर पर होते हैं। क्विटिन टैरेनटीनो ने रिक, क्लिफ और शैरन के किरदारों और उनके करियर को एक्सप्लोर किया है। तीनों में एक चीज कॉमन है-हॉलीवुड के प्रति उनका जुनून।

सही मायने में फिल्म का ज्यादातर हिस्सा

हॉलीवुड और टीवी को ट्रिब्यूट

हॉलीवुड और टेलीविजन के क्लासिक दौर को ट्रिब्यूट देता नजर आता है। फिल्म के बीच रिक का अपने पुराने शो को देखकर खुश होना, शूटिंग के दौरान अपनी लाइनों को भूल जाना और उसके बाद खुद से बेहतर करने का वादा जैसे सीन कलाकारों के अंतर्द्वंद्व और मनोदशा को दर्शाते हैं। कलाकारों की इस जर्नी को दर्शाने में क्विटिन टैरेनटीनो इस कदर डूबे कि उन्होंने कुछ अनावश्यक दृश्यों की एडीटिंग करने की आवश्यकता नहीं समझी। फिल्म में कई ऐसे प्रसंग भी आते हैं, जब आप सोचने लगते हैं कि कहानी किस दिशा में जा रही है। अंत में उन्होंने सभी कई कड़ियों को जोड़ते हुए उसे शानदार बनाने का प्रयास किया है। फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी और कॉस्ट्यूम डिजाइन, फिल्म के किरदारों से लेकर उसके एक्शन, इमोशन, ड्रामा सभी पहलुओं पर बारीकी से काम किया गया है।

फिल्म का खास आकर्षण लियोनार्डो डी कैप्रियो और ब्रैड पिट की जुगलबंदी हैं। लियोनार्डो ने रिक की असुरक्षा की भावना, मनोदशा और हताशा को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया है। फिल्म में आठ साल की बाल कलाकार के साथ उनके वार्तालाप का प्रसंग रोचक है। वह नई और पुरानी पीढ़ी की सोच के अंतर को रेखांकित करता है। वहीं ब्रैड पिट भी लियोनार्डो को पूरा सहयोग देते नजर आते हैं। बॉडी डबल के तौर पर स्टंट दिखाने के अलावा मारधाड़ के अनेक दृश्य उनके हिस्से में आए हैं। उसमें वह प्रभावित करते हैं। फिल्म में मार्गट रॉबी का किरदार सबसे कमजोर रहा। अल पचीनो का फिल्म में कैमियो है। अपनी संक्षिप्त भूमिका में वह याद रह जाते हैं। सहयोगी कलाकारों की भूमिका में आए कलाकारों ने भी उम्दा काम किया है।

संगीत टैरनटीनो की फिल्मों का खास पहलू होता है। यहां पर उन्होंने वेस्टर्न से लेकर रॉक ऐंड रोल का मिश्रण रखा है। जैसे अपने फार्मूले आजमाते टैरनटीनो दिखे हैं।

स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

हवा शुद्ध करता है यह कृत्रिम वृक्ष

जहरीली हवा विभिन्न देशों के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। इससे निपटने के उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको के प्वेब्ला में हवा शुद्ध करने के लिए एक उच्च क्षमता का एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। यह एक तरह का कृत्रिम पेड़ है जो सजीव शैवाल से युक्त है। इससे प्रकाश संश्लेषण (फोटोसिंथेसिस) की क्रिया होती है और हवा को शुद्ध करता है। मेक्सिकन कंपनी बायोमीटेक द्वारा तैयार इस उपकरण की यह क्षमता 368 प्राकृतिक वृक्षों के बराबर है। एएफपी

इस्पात का विशाल स्कल्पचर

यूरोपीय देश बेल्जियम में इस्पात का विशाल स्कल्पचर (कलाकृति) स्थापित किया गया है। लावाक्स सैंते-एने कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थापित यह स्कल्पचर 60 मीटर ऊंचा है। अर्द्धवृत्त खंड जैसी इस कलाकृति को 'एल आर्क मज्योर' नाम दिया गया है। इसकी डिजाइन 78वर्षीय समकालीन फ्रांसीसी कलाकार बर्नार वेनेट ने तैयार की है। दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर है। स्कल्पचर 200 टन इस्पात से बना है और 2800 टन कंक्रीट में स्थापित हुआ है। अब यह खूब चर्चा बटोर रहा है। रायटर

स्क्रीन शॉट

धागे में बंधा मजबूत रिश्ता

बदलते वक्त के साथ रक्षाबंधन पर भाइयों की जिम्मेदारियां थोड़ी बदली हुई हैं। हर बहन चाहती है कि उसका भाई उसके साथ-साथ बाकी लड़कियों का भी उतना ही सम्मान करे। यही सोच फिल्मी सितारे भी रखते हैं। आज रक्षाबंधन पर रक्षा की अहमियत बताई सितारों ने...

बहन शगुन से बंधवाती हूं राखी : तापसी पन्नू

मेरा कोई सगा भाई नहीं हैं। मैं और मेरी बहन शगुन हम दो बहनें हैं। मुझसे बड़े और छोटे कई चचेरे और ममेरे भाई हैं, जिन्हें मैं राखियां भेजती हूं। विदेश में रहने वाले भाई को मैंने पहले ही राखी भेज दी थी। बाकी भाइयों को अपने हाथों से राखी बाधूंगी। राखी के दिन भाइयों से मिलने वाले उपहार को लेकर मैं बहुत उत्सुक रहती हूं। मेरे भाई राखी के मायने समझते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। मेरा एक भाई है जिसे हर समय मेरी सुरक्षा की चिंता लगी रहती है।

भाई हर बहन की रक्षा के बारे में सोचें : कीर्ति कुल्हारी

मेरा मानना है कि बिना अपनी सोच बदले इस समाज में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हर बच्चे को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा उसके घर से मिलती है। अपने बच्चों को कुछ सिखाने से पहले हमें खुद में भी बदलाव लाना होगा। भाइयों को भी सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि हर बहन की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। मेरा भाई मर्चेंट नेवी में है। वह मुझसे छोटा है। वह सबका बहुत ख्याल रखता है। वह कभी जताता नहीं है, लेकिन उसके हावभाव में यह दिख जाता है।

भाई को सिखाया महिलाओं की इज्जत करना : मृणाल ठाकुर

इस रक्षाबंधन पर मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि दीदी यह मेरे लिए आपकी तरफ से बेस्ट तोहफा है। मेरा भाई मेरे लिए बच्चे की तरह है। मैंने अपने भाई से हमेशा यही कहा है कि तुम्हें महिलाओं को इज्जत देना सीखना चाहिए। हमने उसमें यह आदत डाली है कि घर में जो काम लड़कियां करती हैं वह उसे भी करना चाहिए। भले ही वह छोटा सा काम ही क्यों न हो। मैं अपने भाई से कहती हूं कि तुम भावुक होते हो और लगता है कि रोने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा तो तुम बेहिचक रो सकते हो।

बहन की राखी न मिलने पर था मायूस : प्रभास

राखी का त्योहार बचपन में मनाने में बहुत मजा आता था। मेरी एक बहन और एक भाई है। उसके अलावा कई चचेरी और ममेरी बहनें भी हैं। हमारा परिवार काफी बड़ा है। मेरी बहन मुझे लेकर बहुत इमोशनल है। मैं नौवीं क्लास में हॉस्टल में रहता था। राखी पर स्कूलों में एक दिन की छुट्टी होती थी। लिहाजा घर आने का मौका नहीं होता था। हालांकि उस दिन अपनी बहन की भेजी राखी का बेसब्री से इंतजार रहता था। उस साल मेरी बहन की राखी नहीं आई थी, जबकि मेरे सभी सहपाठी की बहनें आई थीं। वे सब अपनी कलाइयों पर राखी बांधे घूम रहे थे। उस दिन मुझे बहुत निराशा हुई थी। यह बात मैंने अपनी बहन से भी बताई थी। उसके बाद वह कहीं भी हो, राखी पर आती है। विदेश में रहने पर हमारे बीच बात हो जाती है। राखी बहनों की रक्षा का वचन लेने का पर्व है।

बहनों ने सिखाई समझदारी : करण सिंह ग्रोवर

बिपाशा की छोटी बहनें विजयेता और मोनई अब मेरी बहनें भी हैं। उनकी बड़ी बहन बिदिशा को मैंने बहन नहीं बनाया है, क्योंकि वह बहुत ही क्यूट हैं। बहनों का होना एक अलग ही एहसास है। मुझे लगता है कि अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो आज मैं थोड़ा और बेहतर इंसान होता। अब मैं समझ गया हूं कि बहन होने की वजह से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार, प्रोटेक्टिव और समझदार हो गया हूं। जब बहनों के साथ वक्त बिताता हूं तो एक अलग ही जोन में होता हूं। हमारा वाट्सएप पर एक ग्रुप है, जिसका नाम है बासु गर्ल्स और उसमें मेरा नाम भी है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे लड़की मत बनाओ। फिर उन्होंने ग्रुप का नाम बदलकर बासु गर्ल्स प्लस बासु ब्वॉय रख दिया।

स्वतंत्रता दिवस पर 'सारे जहां से अच्छा...' गीत एक नए अवतार में

लोकप्रिय देशभक्ति गीत 'सारे जहां से अच्छा...' को वर्षों से हम गुनगुनाते रहे हैं, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस पर यह गीत एक नए अंदाज में देखने-सुनने को मिलेगा। गीत की धुन और संगीत सब कुछ बिल्कुल एक नए स्वरूप में है। डालमिया भारत ग्रुप की ओर से गीत का यह नया कवर वर्जन लॉन्च किया गया है। नया गीत पहले से भी ज्यादा भक्ति से ओतप्रोत होगा। एक अलग तरह के म्यूजिक और फिल्मांकन के जरिए गीत को बिल्कुल नए अवतार में पेश करने की कोशिश की गई है, ताकि नई पीढ़ी जो अपनी विरासत को भूलती जा रही है, उसे इससे रूबरू कराया जा सके।

बदलाव की तैयारी

मोटर वाहन उद्योग के अधिकारी रुकावटों को दूर करने पर कर रहे हैं काम, ताकि आने वाले समय में रफ्तार पकड़ सके बिना चालक की कारों का बाजार

स्वचालित कारों की राह में अभी हैं कई रोड़े

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

आने वाला समय स्वचालित कारों यानी बिना चालक की कारों का है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से जमीन पर उतारने से पहले अभी कई रुकावटों को पार करना है। मसलन, पैदल यात्री और सड़क पर चलने वाले सामान्य वाहन। इनके बीच स्वचालित कारों को दौड़ाना अभी टेढ़ी खीर है।

जरा कल्पना करिए मैनहटन की सड़कें बिना पैदल यात्रियों के या लॉस एंजिलिस की सड़कों पर धीमी रफ्तार में चलते वाहन, या फिर मॉस्को की सड़कें बिना भारी ट्रैफिक के। यदि स्वचालित कारों की दिशा में आगे बढ़ना है तो उपरोक्त स्थितियों पर भी विचार करना होगा, क्योंकि उपरोक्त स्थितियां सिर्फ काल्पनिक हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर तो एक अलिखित नियम स्पष्ट है। कहीं से भी कभी भी सड़क पार करिए, बस इतना ध्यान रहे कि किसी से टकरा न जाएं। मोटर वाहन उद्योग के अधिकारी इसका एक हल बताते हैं कि किनारों पर गेट बनाए जाने चाहिए, ताकि पैदल यात्री किसी भी समय सड़क पार कर सकें।

प्रतीकात्मक

एक ऑटोनोमस वाहन डेवलपर जोक्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी मार्क रोजकिंड के मुताबिक, स्वचालित वाहनों के अंदर तकनीकि सामान काम करेगा। ऐसे में सामाजिक हिस्से को संभालना महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका एक हल यह हो सकता है कि वाहनों को वहां की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया जाए। मसलन, कैलिफोर्निया में भारी ट्रैफिक को देखते हुए स्वचालित कारों की अधिकतम गति को कम रखा जाना चाहिए।

छह वर्गों में विभाजित हैं स्वचालित वाहन

स्वचालित वाहनों को छह वर्गों में विभाजित किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पूर्ण रूप से स्वचालित वाहन को लेवल पांच में रखा गया है, जिनके करीब आगामी 10 सालों तक आने की संभावना अभी नहीं है। इनके लिए अनगिनत टेस्ट होने बाकी हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पूरी तरह से बिना चालक के चलने वाले वाहन आगामी पांच साल या उससे कम वर्षों में सड़कों पर दिखाई देंगे। रोजकिंड के मुताबिक, हाल के दिनों में स्वचालित वाहनों के कारण कुछ दुर्घटनाओं की खबरें प्रकाश में आई हैं, लेकिन लोगों को इस दिशा में जागरूक करने की जरूरत है कि स्वचालित कारें आज की कारों और ट्रकों की तुलना में अधिक सुरक्षित होंगी। आज अमेरिका में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 30 हजार से भी अधिक लोगों की जानें चली जाती हैं। **अलग लेन की जरूरत :** टेक्सास ए एंड एम परिवहन संस्थान के निदेशक और परिवहन विभाग में पूर्व सहायक सचिव ग्रेगरी विनफ्री के मुताबिक, आने वाले 30 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। स्वचालित वाहनों के लिए बाजार तैयार हो रहा है। अभी इसमें कई रुकावटें हैं। एक रुकावट तो यह है कि स्वचालित वाहनों का उन्हीं सड़कों पर चलना, जिन पर सामान्य वाहन और पैदल यात्री चलते हैं। एक तरीका यह अपनाया जा सकता है कि स्वचालित कारों के लिए अलग से लेन बनाया जाए, ताकि वे सामान्य कारों और पैदल यात्रियों के साथ मिक्स न हों।